भारत सरकार
के
ग्रामीण विकास मंत्रालय
द्वारा पोषित
जलग्रहण योजनाओं के संबंध में
आदेश तथा परिपत्र

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(भू-संसाधन प्रकोष्ठ)

कमरा नं. 153, कृषि पंत भवन

क्रमांक : प. 2 (104) ग्रावि/एलआर/2 /2003 जयपुर, दिनांक 17/18.4.2006

परिपत्र

भारत सरकार द्वारा जलग्रहण विकास कार्यक्रम (डीडीपी, डीपीएपी एवं आईडब्ल्यूडीपी) के अन्तर्गत प्रतिवर्ष स्वीकृत होने वाली जलग्रहण परियोजनाओं की क्रियान्विती मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत की जाती है। जलग्रहण क्षेत्रों के चयन के लिए हरियाली मार्गदर्शिका में मानदण्ड नियत किए गए है, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 5 में किया हुआ है। उल्लेखित मानदण्डों में से जलग्रहण परियोजना के चयन हेतु एक मानदण्ड निम्नानुसार है:-

''ऐसा जलग्रहण क्षेत्र जो ऐसे अन्य जलग्रहण क्षेत्र जिसे पहले विकसित किया जा चुका है के साथ सटा हुआ हो।''

विभाग के ध्यान में लाया गया है कि किसी एक गांव में पूर्व में स्वीकृत जलग्रहण परियोजना के कार्य पूर्ण किए जाने से पहले ही अन्य परियोजना स्वीकृत की जाती है, जो कि मार्गदर्शिका का उल्लंघन है।

प्रत्येक गांव का समान रूप से विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि गांव का चयन इस प्रकार किया जावे कि प्रत्येक गांव परियोजना के कार्यों से लाभान्वित हो। ''

मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरियाली मार्गदर्शिका के अनुच्छेद 5 (vii) की अनुपालना सुनिश्चित करे।

ह./-

आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त निदेशक (I/II)
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त (श्रीगंगानगर के अतिरिक्त)

ह./-

उप सचिव (भू-संसाधन)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

RURAL DEVELOPMENT & PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

(Land Resources Section)

Room No. 153, Pant Krishi Bhawan

No. : F. 2 (104) RD/LR/2/2003 Jaipur, Dated : 20.4.06

CIRCULAR

Watershed Programmes are being implemented in the state under DDP, DPAP and IWDP under the provisions of the GOI guidelines. It has been observed that only construction activities are being taken up in the name of Watershed programmes violating para 16 of Hariyali Guidelines and during this all the soft activities are apparently missing. The main objective of watershed programme is promotion of the overall economic development and improvement of the Socio economic conditions of the resource poor section of people inhabiting the programme areas by treating degraded lands with the help of low cost and locally accessed technologies such as in situ soil and moisture conservation and production measures through a participatory approach that seeks to secure close involvement of the user communities.

Thus, the activities undertaken are process oriented and a period of six months is given for Community organisation, Exposure visit, trainings and preparation of DPR. As such, procedure laid down in guidelines has to be adhered to strictly to ensure effective and successful implementation of the programmes. Activities to be carried out are listed below in order of their happenings :-

(i) Allotment of project to PIA with the sanction of GOI.
(ii) Constitution of competant WDT by PIA, placement in Watershed, ensuring payment of honorarium.
(iii) Community Mobilization and Training of WDT members, if not trained earlier, orientation of watershed villages and training on watershed management to all concerned, including SHG's, UG's & PRI's.
(iv) Constitution of SHGS' of poor, landless SC/ST Women etc. for income generating activities.
(v) Constitution of UGS' for every Watershed activity.
(vi) Engaging Van Rakshak and Volunteers as per requirement.
(vii) PRA, Constraint analysis and prioritization of problems.
(viii) workout technical & participatory solutions and preparation of yearwise annual action plan for project period.
(ix) Preparation of Detailed Project Report (DPR) through PRA involving WDT and indicating clear exit protocol. Approval of DPR in Gram Sabha and then in ZP.
(x) Opening of project Account & WDF Account by GP.
(xi) Implementation of activities of DPR by GP under technical guidance of WDT.
(xii) Imposition of user charges by GP for Usufructs.
(xiii) Transparency in execution of the programme as have been provided in Guidelines.
(xiv) Mid term evaluation of works after receipt of 45% of total cost of project (second instalment under Haryali).
(xv) Timely submission of MPR & QPR's & Completion of project in prescribed period in such a way that Communities & Users groups own every activity of the programme.

It is directed to follow process spelt out in the guidelines to ensure land and water resource management for sustainable development and community empowerment.

Sd/-
Pr. Secretary (RD & PR)

Copy for information and necessary action to :

1. PS to Commissioner, Wasteland, Watershed Development and Soil Conservation, Jaipur
2. Addl. Director I/II, Wasteland, Watershed Development and Soil Conservation, Jaipur
3. Chief Executive Officer, Zila Parishad, All districts (except Sri Ganganagar)
4. Joint Director, Watershed Development and Soil Conservation, Region Jaipur/Ajmer/Jodhpur/Kota/Bhilwara/ Udaipur

Sd/-
Dy. Secretary (LR)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

क्रमांक : प. 19 (1) ग्रावि/2/2006 जयपुर, दिनांक 27.04.2006

परिपत्र

मरू विकास कार्यक्रम, सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम एवं बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत जलग्रहण परियोजना में प्रत्येक परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन ''जलग्रहण विकास दल'' के माध्यम से किया जाता है। जिले में स्वीकृत जलग्रहण परियोजनाओं के लिए गठित जलग्रहण विकास दल परियोजनाओं के परिपेक्ष्य में एक विषय विशेषज्ञ के रूप में परियोजनाओं के प्रति तकनीकी दायित्वों का निर्वहन करता है।

जलग्रहण परियोजना के अन्तर्गत गठित जलग्रहण विकास दल अपने समस्त दायित्वों का निर्वहन सुचारु एवं व्यवस्थित रूप से करने तथा स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यों को अपेक्षित गति प्रदान करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा जलग्रहण विकास दल के लिए मापदण्ड निर्धारित किये गये है, जिसका विवरण परिशिष्ठ-'अ' पर संलग्न है। समस्त जिला परिषद निर्धारित मापदण्डों का पूर्णरूपेण पालन सुनिश्चित करे।

Sd/-

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त, बंजर भूमि, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रथम/द्वितीय) बंजर भूमि, जलग्रहण विकास एवं भू संरंक्षण विभाग।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त जिले (गंगानगर के अतिरिक्त)।
6. संयुक्त निदेशक, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा एवं कोटा वृत।

Sd/-

उप सचिव (भू संसाधन)

जलग्रहण विकास दल के गठन हेतु मापदण्ड

1. प्रत्येक परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह ''जलग्रहण विकास दल'' के जरिये पूरा किया जायेगा। प्रत्येक जलग्रहण विकास दल में कम से कम चार सदस्य होंगे, जो निम्न विषयों से होना अनिवार्य है :-

अ. कृषि ब. वानिकी स. अभियांत्रिकी
द. पशुपालन य. सामाजिक विज्ञान

2. **जलग्रहण विकास दल के सदस्यों के दायित्व**

अ. कृषि विशेषज्ञ :

- कृषि योग्य भूमि को उन्नत कृषि तकनीक से उपचारित कराना।
- फलदार पौधों का रोपण कराना।
- समुदाय को यथा समय नवीनतम कृषि तकनीक से अवगत कराना।

ब. वानिकी विशेषज्ञ :

- सामुदायिक भूमि पर वनीकरण।
- चारागाह विकसित करना।
- परियोजना क्षेत्र में सम्मिलित वन भूमि को उपचारित करने में सहायता प्रदान करना।

स. अभियांत्रिकी विशेषज्ञ :

- भू एवं जल संरक्षण गतिविधियों तथा
- नालों का उपचार करना।

द. पशुपालन विशेषज्ञ :

- पशुधन की नस्ल सुधार करना।

य. सामाजिक विज्ञानी :

- भूमिहीन एवं संसाधनहीन व्यक्तियों को स्वयं सहायता समूह के रूप में गठित करना।
- परिक्रामी निधि से व्यवसायिक विकास हेतु मूल राशि (Seed Money) उपलब्ध कराना।
- बैंक से ऋण सुविधा उपलब्ध कराना तथा
- उत्पादन एवं विपणन की आवश्यक व्यवस्था करना।

3. प्रत्येक जलग्रहण विकास दल के सदस्य हेतु चिन्हित प्रशिक्षण संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त किया जाना आवश्यक है, यदि पूर्व में प्राप्त नहीं किया हो तो।

4. दल के सदस्यों में से एक सदस्य को परियोजना प्रमुख के रूप में नामांकित करना।

5. स्वयं सहायता समूह गठित करने में ग्राम पंचायत की सहायता करना।

6. प्रयोक्ता समूह गठित करने में ग्राम पंचायत की सहायता करना।

7. ग्राम पंचायत को मार्गदर्शन प्रदान कर विस्तृत कार्ययोजना तैयार करना।

8. **चयन :** परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा जलग्रहण विकास दल के सदस्यों का चयन निम्न प्रक्रिया के जरिये किया जा सकता है।

(i) पूर्णरूप से स्वयं के अधीन कर्मचारियों को लगाना।
(ii) सेवानिवृत्त योग्य कर्मियों को नियुक्त करना।
(iii) नये अभ्यार्थियों को भर्ती करना।

(iv) राज्य सरकार अथवा अन्य संगठन से प्रतिनियुक्ति पर कर्मियों को लेना।

9. जलग्रहण विकास दल में कम से कम एक महिला सदस्य होना अनिवार्य है।

10. **योग्यता :** दल के सदस्य हेतु संबंधित विषय में व्यावसायिक डिग्रीधारी होना। उपयुक्त मामलों में जिला परिषद द्वारा दल के सदस्य के अनुभव को ध्यान में रखते हुए निर्धारित योग्यता में छूट दी जा सकती है।

11. **जलग्रहण विकास दल का कार्यालय :** सामान्यत कार्यालय पीआईए/पंचायत समिति मुख्यालय पर अथवा परियोजना क्षेत्र से निकटतम स्थान पर होना चाहिये।

12. **मानदेय :** दल के प्रत्येक सदस्य को जलग्रहण क्षेत्र में प्रति निरीक्षण दिवस विभाग द्वारा निर्धारित मानदेय प्रदान किया जावे। प्रत्येक निरीक्षण सार्थक (Result oriented) होने की स्थिति में मानदेय देय होगा, जिसकी सुनिश्चितता पी.आई.ए. द्वारा की जायेगी।

13. बेसलाइन सर्वेक्षण करना।

निम्न मूल संकेतको (Key Indicators) का उल्लेख किया जावे

अ. कुओं का जलस्तर।

ब. सामुदायिक भूमि, चारागाह एवं लाभार्थी कृषक की भूमि पर अलग अलग उपलब्ध पेड़ों की संख्या।

स. चारे के उत्पादन का विवरण।

द. Artificial insemination वाले बछड़ों की संख्या।

य. कृषि उत्पादन की स्थिति।

र. जैविक खेती अपनाने वाले कृषकगण की संख्या।

ल. स्वयं सहायता समूहों की संख्या जिन्हें बैंक/संस्था द्वारा लोन उपलब्ध कराया गया ।

व. कृषकगण की संख्या, जिनके द्वारा उन्नत कृषि तकनीक अपनाई गई ।

14. गतिविधिवार कार्य योजना तैयार करने में ग्राम पंचायत की सहायता/तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना।

15. वर्षवार वास्तविक लक्ष्य प्राप्त करने के लिये कार्यकलाप सम्बन्धी रूपरेखा तैयार करना।

16. प्रत्येक कार्यकलाप हेतु निश्चित समय अवधि निर्धारित करना।

17. प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु प्रौद्योगिकी क्रियाओं का निर्धारण करना।

18. प्रत्येक कार्यकलाप हेतु सफलता के मानदण्ड निर्धारित करना।

19. ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन की जांच कर जिला परिषद को प्रस्तुत करना।

20. **स्पष्ट बहिगर्मन व्यवस्था के अन्तर्गत**

अ. प्रयोक्ता प्रभार की व्यवस्था करना।

ब. जलग्रहण विकास निधि के उपयोग से सृजित परिसम्पत्तियों के रख रखाव व संवर्द्धन की क्रियाविधि तय करना।

स. परियोजना अन्तर्गत प्राप्त किये गये लाभों के एक समान वितरण एवं सतत् बनाये रखने की क्रियाविधि तैयार करना।

परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी/जलग्रहण विकास दल के स्तर पर
प्रशासनिक व्यय की अधिकतम सीमा (उदाहरणार्थ)

क्र.सं.	आइटम	एक परियोजना हेतु	दस परियोजना हेतु
अ.	1. जलग्रहण विकास दल के सदस्यों को मानदेय	रुपये 75,000	रुपये 7,50,000
	2. यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता	रुपये 45,000	रुपये 4,50,000
	3. कार्यालय कर्मचारी/आकस्मिकताऐं	रुपये 27,000	रुपये 2,70,000
	योग	**रुपये 1,47,000**	**रुपये 14,70,000**
ब.	दल के सदस्य को निरीक्षण हेतु प्रति दिवस देय मानदेय	रुपये 250	रुपये 2500
2.	पांच वर्षीय परियोजना अवधि में		
	(i) दल के सदस्यों द्वारा निरीक्षण योग्य दिनों की संख्या	300	3000
	(ii) प्रति सदस्य औसत निरीक्षण योग्य दिनों की संख्या		
	अ. चार सदस्यीय दल हेतु	75	750
	ब. पांच सदस्यीय दल हेतु	60	600
(iii)	प्रति वर्ष निरीक्षण योग्य दिनों की संख्या		
	अ. चार सदस्यीय दल हेतु	19	190
	ब. पांच सदस्यीय दल हेतु	12	120

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(भू-संसाधन प्रकोष्ठ)

कमरा नं. 153, कृषि पंत भवन

प. 2 (104) ग्रावि/भूसं./2/2006 जयपुर, दिनांक : 01.05.2006

परिपत्र

भारत सरकार द्वारा मरू विकास कार्यक्रम, सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम एवं एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रतिवर्ष जलग्रहण परियोजनायें स्वीकृत की जाती है। महसूस किया गया है कि परियोजना की स्वीकृति पश्चात् विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने तथा इसके अनुमोदन में काफी समय लग जाता है, जिसके फलस्वरूप कार्य शुरू करने में अत्यधिक विलम्ब होता है।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने एवं अनुमोदन में लिए जाने वाले समय को कम करने के उद्देश्य के मध्यनजर आवश्यक है कि, वाटरशेड एटलस एवं कलस्टर/इंडेक्स केचमेंट/जलग्रहण क्षेत्रों के चयन एवं प्राथमिकता बाबत जारी विभागीय परिपत्र क्रमांक 15 (4) ग्रावि/2/2003 पार्ट-II दिनांक 20.4.06, 18 (3) पीएफसी/डीडब्ल्यू डीएससी/2006/58-609 दिनांक 21.4.06 एवं 610-1055, दिनांक 22.4.06 एवं विभागीय समसंख्यक परिपत्र दिनांक 18.4.06 के आधार पर जलग्रहण क्षेत्रों की प्राथमिकता सूची तैयार कर पहले से ही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली जावे, ताकि भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होते ही जिला परिषद के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जा सके। शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट बनाने का दायित्व भी परियोजना अधिकारी (भू-संसाधन) का ही है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005-06 में स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या से 10-15 प्रतिशत अधिक परियोजना प्रतिवेदन अगस्त 2006 तक परियोजना अधिकारी (भू-संसाधन) द्वारा तैयार कर लिये जावें, ताकि वर्ष 2006-07 में स्वीकृति प्राप्त होते ही जिला परिषद से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का अनुमोदन प्राप्त किया जा सके। इस प्रक्रिया से परियोजनाओं की क्रियान्विति समय पर शुरू की जा सकेगी।

कृपया इसे अति आवश्यक समझें।

ह./-

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपिः-

1. अतिरिक्त निदेशक, I/II
2. संयुक्त निदेशक, जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, भीलवाडा।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त (गंगानगर को छोड़कर)।
4. परियोजना अधिकारी (भू-संसाधन) समस्त (गंगानगर को छोड़कर)।

ह./-

अतिरिक्त निदेशक (प्रथम)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(भू-संसाधन प्रकोष्ठ)

कमरा नं. 153, कृषि पंत भवन

प. 02 (104) ग्रावि/भूसं/2/2003 जयपुर, दिनांक 11.05.2006

परिपत्र

मरू विकास कार्यक्रम (डीडीपी), सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) एवं राष्ट्रीय जलग्रहण विकास कार्यक्रम (एनडब्ल्यूडीपीआरए) के अन्तर्गत राज्य में जलग्रहण परियोजनाओं की क्रियान्विति की जा रही है। इन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भारत सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुरुप किया जा रहा है।

राज्य में वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नियंत्रित कार्यक्रम यथा डीडीपी, डीपीएपी व आईडब्ल्यूडीपी के अन्तर्गत वर्ष 2000-2001 एवं तत्पश्चात् स्वीकृत परियोजनाओं के कार्य चालू हैं जिनके लिए भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धान्त (संशोधित-2001) एवं हरियाली प्रभावशाली है। वित्तीय वर्ष 2002-03 तक स्वीकृत परियोजनायें मार्गदर्शी सिद्धान्त (संशोधित-2001) तथा 2003-2004 से उत्तरोत्तर परियोजनायें हरियाली मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुसार निष्पादित की जा रही है।

मार्गदर्शी सिद्धान्त (संशोधित-2001) के अनुच्छेद 21 के अनुसार प्रत्येक जिले में कार्यक्रम से सम्बन्धित गतिविधियों में विभिन्न स्तर पर सामंजस्य रखने हेतु जिला परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में जिला जलग्रहण विकास समिति गठित किये जाने का प्रावधान है। तद्नुसार राज्य सरकार द्वारा जिला जलग्रहण विकास समिति का गठन जिला प्रमुख की अध्यक्षता में किया गया। प्रत्येक जलग्रहण परियोजना हेतु तैयार किये गये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुमोदित करने का अधिकार जिला जलग्रहण विकास समिति में निहित है।

हरियाली मार्गदर्शिका जो 01.04.2003 तथा उत्तरोत्तर स्वीकृत परियोजनाओं के लिए प्रभावी है, के अनुच्छेद 26 के अनुसार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत करने का अधिकार जिला परिषद को सौंपा गया है। जिलों से समय-समय पर मार्गदर्शन चाहा जाता है कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का अनुमोदन तथा परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी को परियोजनाओं का आवंटन किसके द्वारा किया जावेगा। इस विषय में स्थिति निम्नानुसार स्पष्ट की जाती है :-

(1) जिला परिषद ही परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी को जलग्रहण परियोजना आवंटित करने हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त (संशोधित-2001) एवं हरियाली के क्रमशः अनुच्छेद 20 एवं 9 के अनुसार सक्षम है।

(2) हरियाली मार्गदर्शिका के प्रभावी होने से पूर्व की जलग्रहण परियोजनाओं, जिनके विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जिला जलग्रहण विकास समिति द्वारा अनुमोदित किये गये, उनमें यदि कोई संशोधन किया जाना है तो, समिति ही प्रस्तावित संशोधन का अनुमोदित करने हेतु सक्षम है।

(3) हरियाली मार्गदर्शिका के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का अनुमोदन एवं संशोधन यदि कोई हो तो, जिला परिषद द्वारा ही किया जावेगा।

(4) जिला जलग्रहण विकास समिति परियोजना हेतु परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी तथा जलग्रहण विकास दल के सदस्यों केचयन, प्रशिक्षण, सामुदायिक संगठन, प्रचार, स्थानीय एवं कम लागत के कार्य करवाने, जन समुदाय को परियोजना के प्रति प्रेरित कर जोड़ने तथा संसाधनहीन व्यक्तियों की सामाजिक एवं आर्थिक दशा सुधारने हेतु सहायता एवं सलाह देगी। जिला जलग्रहण विकास समिति प्रत्येक जलग्रहण विकास योजना के चयन, विस्तृत कार्य योजना तैयार करना, कार्य योजना की समयबद्ध क्रियान्विति मार्गदर्शिका के अनुसार हो, इसकी परियोजनावार समीक्षा करेगी एवं कार्यों की गति एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करेगी तथा बेहतर क्रियान्विति हेतु जिला परिषद को सलाह दे सकेगी।

ह./-

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त बंजर भूमि, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग।
4. अतिरिक्त निदेशक प्रथम/द्वितीय, बंजर भूमि, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त जिले (गंगानगर के अतिरिक्त)।

ह./-

उप सचिव (भू-संसाधन)

E-Mail

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

RURAL DEVELOPMENT & PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

No. F. 1 ( ) PS/PSRD & PR/2006 Jaipur, Dated : 07.06.2006

To

All Chief Executive Officers,

Zila Parishad, Rajasthan.

Subject : Use of machines in execution of watershed works.

Sir,

In the recently concluded meeting of the Public Accounts Committee, the issue of use of machines in watershed works was discussed at length. The committee seriously viewed the use of machines against the scheme guidelines and directed that strict action should be taken against the officers responsible for this violation.

In the meeting itself, one of the Hon'ble Members brought to the notice of the Committee that even now machines were being used on work in his area. On enquiry, this allegation was found correct.

Your attention is invited to Para 26 of the Hariyali Guidelines, which clearly mention that costly masonary/cement works and use of machinery should be discouraged. Besides, one of the major objectives of the projects under Hariyali as per Para 3(iii) of the Guidelines is employment generation, poverty alleviation, community empowerment etc. Apparently, the scheme guidelines stipulate that works are to be executed by engaging labourers on Muster Rolls, so that the above objectives are achieved. During enquiry, it was mentioned that the guidelines issued by Director Watershed permitted use of machines on watershed works. But these guidelines were issued before the Hariyali guidelines.

In order to clear all doubts, it has been decided that on watershed works, no machines will henceforth be engaged even if, those works were sanctioned before issue of Hariyali guidelines. In case the use of machines on some work is a technical requirement for completion of the work, first of all it should be incorporated in the DPR alongwith the reasons as to why the work can not be done by engaging labourers. After the approval of the DPR by the Watershed Committee and the Zila Parishad, specific approval of the Commissioner, Watershed should be obtained to carryout that particular task by use of machine. No machine should be engaged without specific approval of the Commissioner.

In no other case use of machine would be allowed. CEO should strictly have these works supervised through Panchayats, PO (LR) and field officers of Watershed Deptt. CEO and BDO's will also inspect the works from time to time. Suitable instruction should be issued to PIA's and Panchayats informing them that use of machines without specific approval of Commissioner Watershed is not allowed and they should strictly enforce this decision.

The system of payment of wages to the labourers engaged on watershed works in the presence of third party i.e. Sarpanch, Patwari, Gram Sevak etc. should also be introduced to bring in transparency. A copy of the Muster Roll should be displayed at the Notice Board of the Panchayat, so that the authenticity of attendance could be verified by the villagers. These measures are necessary to obviate any attempt to prepare false muster rolls after getting the work done through machines. There have been number of complaints on this in the past.

These instructions should be strictly implemented.

Yours faithfully,

Sd/-

(Ram Lubhaya)

Pr. Sec. (RD & PR)

(i) Copy to the Commissioner, Watershed Development for information and necessary action. He should strictly implement these instructions in the filed and issue suitable directions to the field offices also.

(ii) SA to Minister, RD & PR.

Sd/-

Pr. Sec. (RD & PR)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

WASTELAND, WATERSHED DEVELOPMENT & SOIL CONSERVATION DEPARTMENT

No. F 19 (3) RD/LR/2/2006 Jaipur, Dated : 27.06.2006

Chief Executive Officer
Zila Parishad, All.

Subject : Sustainable livelihood to people in watersheds.

Sir,

Watershed Programme is being implemented in the district under DDP, DPAP, IWDP & NWDPRA programmes. One of the important objectives of the programme is to educate and train farmers for adopting new and latest techniques of production system in view of increased ground water table and moisture conservation, as so far, the focus has remained more on civil construction activities.

The project reports are required to be prepared in consultation with the people to improve their livelihood on sustained basis. WDT/PO (LR) are required to motivate/educate farmers for adoption of new production techniques with improved cropping pattern and value addition and all this be included in DPR, as part of production plan.

Following activities as per land capability and need of the area should also be identified & taken up in implementation of watershed programme immediately:-

CONSERVATION ACTIVITIES

* Adoption of Drip and sprinkler irrigation system for efficient use of ground and surface water. One set of Drip and Sprinkler Irrigation system can be put in the field of BPL, SC farmer for demonstration purpose. The cost of the set can be met out from project fund and subsidy of Agriculture department.
* Roof top water harvesting in all Government buildings coming within watershed area also to be given priority.

CONVERGENCE ACTIVITIES

* Convergence of extension activities of Agriculture and Animal Husbandry department in watershed projects.

CREDIT LINKAGES

* Arrangement of requisite Credit through Cooperative Societies or SHG's from Banks. **PRODUCTION ACTIVITIES**
* Horticulture development, Medicinal/Herbal plants cultivation, commercial/cash crops cultivation.
* Improved AH techniques and breed improvement through AI.
* Cultivation of protein rich fodder varieties and preparation of cattle feed.
* Pasture development and Social forestry to be taken up to meet timber, fuel and fodder requirement.
* Adoption of Vermi compost and organic farming.
* The production Plan should be prepared in close coordination of Agriculture and AH Specialist included in WDT and clear cut Physical & Financial target should be brought out for every production activity.

COMMUNITY MOBILISATION & EXTENSION ACTIVITIES

* For taking AH activities forward, one Gopal in each Gram Panchayat be selected & training be organised through BAIF or Livestock Development Board. Training cost & kit of Gopal can be arranged from the provision available in training. Gopal will provide services to the community on User fee basis. BAIF model can be adopted for this.

MARKETING TIE-UPS

* Forward & Backward Linkages should be ensured. Cooperative Societies & SHG's need be mobilized building their Capacity for marketing support.

PO (LR) will be responsible for following these instruction through WDT in every watershed area and ensure that appropriate production activities are taken up in right earnest for improvement of livelihood of people living in watershed areas.

Yours Faithfully,

Sd/-
Commissioner

1. Copy to P.S. to Pr. Secretary, RD & PR Government of Rajasthan in reference to MR. No. 2621 dated 12.6.06.
2. Copy forwarded to Jt. Director, WD & SC for information & necessary action.

Sd/-
Commissioner

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, बंजर भूमि, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक प. 5 (1) आरडी/एलआर/2/2006-07 जयपुर, दिनांक : 0 5.07.2006

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद (श्री गंगानगर के अतिरिक्त)।

विषय : मानसून 2006 में विभिन्न जलग्रहण योजनाओं में वानस्पतिक कार्याकलापों के क्रम में।

विभिन्न जलग्रहण योजनाओं में जल एवं मृदा का insitu संरक्षण कर कृषि एवं अकृषि भूमि में फसल प्रदर्शन, वानिकी पौधारोपण, चरागाह विकास, उद्यानिकी विकास के कार्य इस प्रकार सम्पादित कराये जावे कि सम्बन्धित भू भाग से अधिकतम उत्पादन किया जा सके। अतः भूमि की क्षमता (Land capability class) को ध्यान में रखते हुए जलग्रहण क्षेत्रों में सामुदायिक भूमियों पर जहां चारागाह विकास एवं वृक्षारोपण के कार्यक्रम हाथ में लिये जाकर आम आदमी को ईधन, चारे एवं छोटी इमारती लकड़ी उपलब्ध कराने के प्रयास किये जावें, वहीं निजी भूमिओं पर उन्नत कृषि के फसल प्रदर्शन, चारा विकास एवं फलोत्पादन द्वारा उत्पादकता बढ़ाकर सम्बन्धित काश्तकारों की आय में इजाफा किया जा सकता है। Agro Climatic Zone वार उपयुक्त प्रजातियों का विवरण संलग्न कर अनुरोध है कि काश्तकारों से विचार-विमर्श कर उपयुक्त प्रजातियों के बीज/पौधों की अग्रिम व्यवस्था कर प्रभावी कार्यवाही इस प्रकार करे कि जलग्रहणवासी इसका अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके।

अ. फसल प्रदर्शन

ग्रामीण विकास कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं जैसे आई.डबल्युडीपी, डीपीएपी डीडीपी इत्यादि से सम्बन्धित जलग्रहण क्षेत्रों में भारत सरकार की दिशा निर्देशिका ''हरियाली'' के पैरा 26 के बिन्दु (ix) के अनुसार खरीफ 2006-07 में फसल प्रदर्शन आयोजित किये जाने है। फसल प्रदर्शनों के आयोजन में निम्नलिखित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जावे-

1. प्रदर्शन आयोजन से पूर्व जलग्रहण क्षेत्रों के कृषकों में इसका व्यापक प्रचार प्रसार करे। तत्पश्चात किसानों का चयन कर इन्हें प्रशिक्षित किया जावें। प्रशिक्षण में फसल की किस्मों का चयन, नमी संरक्षण, भूमि एवं बीज उपचार, बीमारी एवं कीटों की रोकथाम सम्बन्धी तकनीकी जानकारी, कृषि विशेषज्ञों से दिलावें तथा भू एवं जल संरक्षण सम्बन्धी गतिविधियां प्रस्तावित हो तो उसे समय पर पूर्ण कराने का प्रयास करावें, ताकि कृषकों को फसल प्रदर्शन में उक्त गतिविधि का भरपूर लाभ मिल सके।
2. बीज की नई किस्म का प्रदर्शन आयोजित किया जावे।
3. फसलों के प्रदर्शन में आदान व्यवस्था कृषि विभाग को पैकेज ऑफ प्रैक्टीसेज में दी गई सिफारिश के अनुसार की जावे।
4. प्रदर्शन आवंटन हेतु कृषकों का चयन करते समय महिला कृषक, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा लघु एवं सीमान्त कृषकों को प्राथमिक दी जावे।
5. जलग्रहण विकास दल में कृषि से सम्बन्धित सदस्य की सेवाओं का भरपूर उपयोग किया जावें।
6. तुलनात्मक अध्ययन हेतु प्रदर्शन स्थल के समीप नियंत्रित प्लांट (कन्ट्रोल प्लांट) भी चिन्हित किया जावें।
7. फसल प्रदर्शन ऐसे स्थानों पर आयोजित हो जहां सभी की आसानी से पहुंच हो सके एवं अन्य कृषक इसे देखकर लाभ उठा सके।
8. चयनित कृषकों के खेत की मिट्टी एवं पानी की जांच करवाकर प्रदर्शनों में फसल की आवश्यकता अनुसार पोषक तत्वों की मात्रा के अनुरूप खाद एवं उर्वरक के प्रयोग सुनिश्चित करें।
9. प्रदर्शन बारानी क्षेत्र में आयोजन होने है, अतः वर्षा जल का अधिकाधिक उपयोग किया जावे। इसके लिए Dry Land Agriculture Practices पर विशेष ध्यान दिया जावे।10. फसल प्रदर्शन के आयोजन हेतु बीजों की व्यवस्था राजस्थान राज्य बीज निगम के क्षेत्रीय कार्यालय एवं डीपो/अन्य आदनों की व्यवस्था नियमानुसार सुनिश्चित किया जावें। फसल प्रदर्शन आयोजन के लिये राज्य की जलवायु एवं भौगोलिक स्थिति के अनुसार जोनवाइज/जिलावार उपयुक्त/किस्मों का विवरण (संलग्न)।

यदि प्रदर्शन आयोजित करने में किसी प्रकार की कठिनाई महसूस की जावें तो अविलम्ब विभाग को अवगत करावे, ताकि उचित कार्यवाही यथा समय की जा सकें।

ब. कृषि वानिकी

जलग्रहण विकास कार्यक्रम की क्रियान्विति भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुरूप डीडीपी, डीपीएपी-आईडब्ल्यूपी के अन्तर्गत की जा रही है। मार्गदर्शिका में निहित प्रावधान के अनुरूप जलग्रहण परियोजना क्षेत्र में ब्लाक पौधारोपण, चारागाह विकास, कृषि वानिकी के कार्य यथा संभव कराये जाने चाहिये। मानसून 2006 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जलग्रहण क्षेत्रों में कृषि /अकृषि भूमि में पौधारोपण का कार्य किया जाना है, पौधों की आपूर्ति जलग्रहण क्षेत्रों में स्थापित नर्सरियों एवं वन विभाग के माध्यम से सुनिश्चित की जानी है। वन विभाग को मांग यथा समय प्रेषित कर दी जावे ताकि पौधों

को प्राप्त करने में कठिनाई न हो। पौधों की प्रजाति का चयन जलग्रहण क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति, जलवायु, मिट्टी का प्रकार व पानी की उपलब्धता को ध्यान में रखकर की जावे।

स. चारा विकास

राजस्थान में खेती बाडी के साथ-साथ पशुपालन भी किसानों की आय का प्रमुख स्त्रोत है। दुग्ध उत्पादन ग्रामवासियों के लिए आर्थिक दृष्टि से तो लाभप्रद धंधा है ही, इसके कारण शहरवासियों के लिये विभिन्न प्रकार के आवश्यक खाद्य एवं पेय पदार्थ भी उपलब्ध होते है।

राज्य में हरे चारे की विशेष रूप से बहुत कमी है इसके प्रमुख कारण है कम भूमि पर चारे की खेती और प्रति इकाई भूमि से कम पैदावार, कम व अनिश्चित वर्षा तथा लगातार सूखे की परिस्थितियों में विशेषकर शुष्क अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में चराई क्षमता से अधिक पशु होने के कारण निरन्तर चारे की कमी तथा अकाल की सी परिस्थितियां बनी रहती है। अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक जोत के कम से कम 1/5-1/10 भाग पर अथवा पडत भूमि पर हरे चारे की खेती की जावे।

पशुधन की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए हरा चारा अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि हरे चारे आवश्यक संतुलित तत्वों की पूर्ति होती है और यह पशु आहार की तुलना में अधिक सस्ता भी पडता है। चारा उत्पादन से किसानों की आर्थिक स्थिति में तो सुधार होता ही है, साथ-साथ उपलब्ध भूमि एवं जल संसाधनों का वैज्ञानिक तरीकों से भली प्रकार उपयोग होता है। तद्नुसार चारा विकास एवं कृषि वानिकी महत्व प्रदान किया गया है।

द. उद्यानिकी कार्यक्रम

फलों के उत्पादन में वृद्धि एवं कृषकों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य में क्रियान्वित जलग्रहण योजनाओं में, योजनाओं की मार्गदर्शिका अनुसार जलग्रहण क्षेत्रों में कृषि भूमि में जहां सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो वहां फलदार पौधों के रोपण का कार्यक्रम लिया गया है। फलदार पौधों की किस्मों का चुनाव, जलग्रहण क्षेत्रों की जलवायु भौगोलिक स्थिति, भूमि का प्रकार एवं स्थानीय मांग के अनुरूप किया जावे।

Sd/-
आयुक्त

प्रतिलिपिः
1. अति. निदेशक प्रथम/द्वितीय आयुक्तालय बंजर भूमि।
2. समस्त संयुक्त निदेशक वृत जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण।

Sd/-
आयुक्त

जोन/जिलेवार खरीफ 2006
हेतु कृषि भूमि में फसल प्रदर्शन, चारा उत्पादन
एवं फलोत्पादन हेतु हेतु उन्नत किस्म/प्रजातियों का विवरण

जोन	जिले	फसल	उपयुक्त किस्में
जोधपुर	जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, बाड़मेर	बाजरा	एचएचबी-67, डब्ल्यू सीसी-75, राज 171, आरएचबी58, आईसीएमएच 356, आरएचबी 90, एमएच 169, आरएचबी 121, जबीवी-2, सीडीपी-9802
	कृषि भूमि में फसल प्रदर्शन हेतु उपयुक्त किस्में	ज्वार	सीएसएच-5, एसपीवी-96
		मक्का	संकर मक्का 5, संकुल अगेती 76, संकुल नवज्योत (जे-684), संकुल किरण (जे-660)
		कपास	आरजी-8, बीकानेरी नरमा, गंगानगर अगेती, आरएसटी-9
		मूंगफली	एम-13
		तिल	आरटी-46, आरटी 125, आरटी 127
		अरण्डी	अरूणा, जीएसएच 4, जीसीच-5, आरएचसी-1
		मूंग	के-851, पूसा बैसाखी, एस-8, आरएमजी 62, गंगा-1
		चंवला	जेसी 5, सी-152, आरएस-9, एफएस-68, आरसी-19
		मौठ	जडिया, ज्वाला, आरएमओ 40
		अरहर	टी-21, प्रभात, ग्वालियर-3
		ग्वार	दुर्गापुरा सफेद, मरू ग्वार, आरजीसी-936
	चारा उत्पादन हेतु उपयुक्त किस्में	मक्का	अफ्रीकन टाल, गंगा-5
		ज्वार	राजचरी-1, 2 पूसाचरी-1,6, एसएसजी-593
		बाजरा	जायन्ट बाजरा, राजको, के-599
		बरसीम	जेबी-1, मसकावी
		रिजका	टी-8, आनन्द-2
		जई	केन्ट
		लोबिया (काउपी)	एनपी-3, रसियन जायन्ट, आईजीएफआरआई-450
		ग्वार	आईजीएफआरआई-212, एफ एस-277, दुर्गापुरा सफेद
	फलोत्पादन हेतु उपयुक्त प्रजातियां	नींबू	कागजी, बरहमासी
		बेर	गोला, सेव, मूण्डिया
		आंवला	चकैया, एनए-7
		अनार	गणेश, जालौर, सीडलैस
		खजूर	हलानी, बरही
जयपुर टोंक, दौसा	जयपुर, अजमेर,	बाजरा	आरसीबी-2, डब्ल्यूसीसी-75, एचएचबी 67, एचएचबी-60, एमएच-179, आरएचबी-30, आरएचबी-58, राज-171, आइसीएमएच-356, आरएचबी-90, आरएचबी-121, आईसीटीपी-8203, पूसा-334
		ज्वार	सीएसएच 6, सीएसएच-9, सीएसवी-10, सीएसवी-15
		मक्का	अगेती-76, बस्सी सलैक्टेड, संकुल माही कंचन, अरावली मक्का-1, पीईएमएच-1, 2
		कपास	आरजी-8, बीकानेरी नरमा, आरएसटी-9, आरएस-2013,810
		मूंगफली	आरएस-1, एम-13, एमए-19 (चित्रा), आरएसबी-87, आरजी-14 जी.जी.-7
		तिल	टीसी-25, आरटी-46, आरटी-125
		सोयाबीन	मोनेटा, पीके-472, एमएसीएस-58, पीएस-16, जेएस-335, मैक्स 450

		अरण्डी	अरूणा, गॉच-1, जीसीएच-4
		मूंग	के-851, पूसा, बैशाखी, आरएमजी-62, आर-288-8, आरएमजी 268, आरएमजी-344, एमयूएस-2
		चंवला	सी-152, आरएस-9, एफएस-68, आरसी-19,101
		मोठ	जडिया, ज्वाला, आरएमओ 40, 257, 435, आईपी-सीएमओ- 312
		उड़द	कृष्णा, टी-9, आरबीयू-38
		अरहर	टी-2, प्रभात, ग्वालियर-3
		ग्वार	दुर्गाजय, दुर्गापुरा सफेद, आरजीसी-197, आरजीसी-936, 986, 1003, 1017
	चारा उत्पादन हेतु	मक्का	अफ्रीकन टाल, गंगा-5
	उपयुक्त किस्में	ज्वार	राजचरी-1, 2, एमपी चरी, एसएसजी-593
		बाजरा	जायन्ट, बाजरा, राजको
		बरसीम	जेबी-1, पूसाजायन्ट, वरदान
		रिजका	टी-9, आनन्द-2
		जई	केन्ट
		ग्वार	दुर्गापुरा सफेद
	फलोत्पादन हेतु उपयुक्त	आम	लंगड़ा, दशहरी, आम्रपाली
	प्रजातियां	अमरूद	एल-49, इलाहाबादी सफेदा
		नींबू	कागजी, बारहमासी
		बेर	उमरान, कैथली, सेव
		आंवला	चकैया, कृष्णा, एनए-7
	अनार	गणेश	
पपीता	पूसा नन्हा, कोयम्बटूर-2, कुर्गहनीडयू		
भीलवाडा	राजसमंद, भीलवाड़ा,	बाजरा	आरसीबी-2, एचएचबी-67, एम एच 36, सीएम-46
	चित्तौडगढ़	ज्वार	सीएसएच 5, 6, 14, 9, 13, एसपीवी-245, 96, 346, सीएसवी 15, 17 प्रताप
		मक्का	गंगा सफेद-2, डक्कन, 103, गंगा-11, संकुल मक्का विजय, नवजोत (जे-684) किरण (जे-660), माही धवल, माही कंचन, अरावली मक्का, हिम-129, पीइएमएच-2, 1, (पूसा अरली मेज हाइब्रीड) प्रताप संकर मक्का-1, 3
		कपास	बीकानेरी नरमा, आएसटी-9, संकर-4
		मूंगफली	आरएस-1, आएसबी-87, एके-12-24, एम-13, जेएल-24, एसबी-11, जीजी-2, जे-38, डीएच-86, टीजी 37 ए
		तिल	आरटी-46, 125, टीसी-25
		सोयाबीन	जेएस-335, टी-49, गौरव
		अरहर	आइसीपीएल-151, 87, ग्वालियर-3
		मूंग	के-851, पूसा बैशाखी, आरएमजी-62
		चंवला	सी-152, जेसी-5, 10 आरएस-9
		उड़द	कृष्णा, टी-9, पन्तयू-19, आरबीयू-38 (बरखा)
		ग्वार	दूर्गाजय, आरजीसी-936,987, दुर्गापुरा सफेद
	चारा उत्पादन हेतु	मक्का	अफ्रीकन टाल, गंगा-5, विजय, किसान,
	उपयुक्त किस्में	ज्वार	राजचरी-1, 2, एमपी चरी, पूसाचरी, 1, 6
		बाजरा	जायन्ट बाजरा, राजको
		बरसीम	जेबी-1, पूसाजायन्ट, वरदान
		रिंजका	टी-8, आनन्द-2
		जई	केन्ट
		ग्वार	एफएस-277, दुर्गापुरा सफेद

	फलोत्पादन हेतु	नींबू	कागजी, बारहमासी
	उपयुक्त प्रजातिया	बेर	सेव, गोला
		आंवला	बनारसी, चकैया, एनए-7
		अनार	गणेश
		आम	दशहरी, लंगडा
श्रीगंगानगर	गंगानगर,	अमेरिकन	आरएसटी-9, बीकानेरी नरमा, आरएस-875, गंगानगर अगती,
	हनुमानगढ़	कपास	आरएस-810, एलएचएच-144
		देशी कपास	आरजी-8, 18
		बाजरा	राज 171, एचएचबी 67, डब्लयूसीसी 75, आरसीबी-2
ग्वार	आरजीसी-936, मरू विकास		
		धान	पीआर-106, जया, बी.के. 190, माही सुंगधा (बासमती)
		मूंगफली	एचएनजी-10, आरएसबी-87, एम-13, चन्द्रा, टीजी-37ए
		मूंग	के-851, पूसा बैशाखी, एमयूएम-2, गंगोत्री-8
		मोठ	जडिया, आरएमओ-40
		तिल	टी-13, टीसी-25, सी-50, आरटी-46
		अरहर	पारस (एच 82-1) यूपीएएस-120
		अरण्डी	गोच-1, जीओसीएच-4, आरसीएच-1
	चारा उत्पादन हेतु	ज्वार	राजचरी-1, 2, एमपीचरी
	उपयुक्त किस्में	बाजरा	राजको
		बरसीम	वरदान, जेबी-1, पूसा जायन्ट
		रिजका	टी-8, आनन्द-2
		जई	केन्ट
		ग्वार	दुर्गापुरा सफेद, एफएस-277
	फलोत्पादन हेतु	अमरूद	इलाहाबाद सफेदा, एल-49
	उपयुक्त प्रजातिया	नींबू	बारहमासी, कागजी
		संतरा	नागपुर
		बेर	गोला, सेव, मूण्डिया
		आंवला	चकैया, एनए-7
उदयपुर	उदयपुर, डूंगरपुर,	मक्का	गंगा सफेद-2, गंगा-11 माही धवल, नवजोत, जीएम-6, माहीकंचन,
	बांसवाडा		माधुरी पीईएचएम-1, 2
		ज्वार	सीएसएच-5, 6, 9 सीएसवी-17, प्रताप ज्वार 1430, एसपीएच 837
		मूंगफली	टीजी 37ए, डीएच-86, प्रताप-1, जीजी-7
		तिल	टीसी-25, प्रताप, आरटी-46, आरटी-125
		सोयाबीन	पीके 472, जेएस-335, कालीतूर, जेएस 7105,
		अरण्डी	अरूणा, गॉच-1, जीएसएच-4
		मूंग	के-851
		चंवला	सी-152, आरएस-9
		उडद	टी-9, बरखा
		अरहर	टी-21, प्रभात, ग्वालियर-3, आइसीपीएल-87
	चारा उत्पादन हेतु	मक्का	अफ्रीकन टोल, गंगा-5, विजय, किसान
	उपयुक्त किस्में	ज्वार	राजचरी-1, 2, एमपी चरी, पूसाचरी 1, 6
		बाजरा	जायन्ट बाजरा, राजको
		बरसीम	जेबी-1, वरदान
रिजका	टी-8, आनन्द-2		
		जई	केन्ट
		ग्वार	एफएस-277, दुर्गापुरा सफेद
	फलोत्पादन हेतु	नींबू	कागजी, बारहमासी

	उपयुक्त प्रजातियां	आम	लंगडा, दशहरी, आम्रपाली
		बेर	गोला, सेव, मूण्डिया
		आंवला	बनारसी, चकैया, कृष्णा, एनए-7
		केला	बसराई
		चीकू	काल पत्ती
कोटा	कोटा, बूंदी, बारां,	ज्वार	सीएसएच-5, 6, 9, एसपीवी-475, 245, 96, 346
	झालावाड, टोंक	मक्का	संकर गंगासफेद 2, 5, संकुल अगेती 76, संकुल नवजोत
		बाजरा	आरसीबी-2, डब्ल्यूसीसी 75, एमएच, 179
		सोयाबीन	गौरव, एमएसीएस-13, मोनेटा, जेएस 80-21, पीके-472, पी.एस.-16, जेएस-335, एमएसीएस-450, एनआरसी-37
		मूंगफली	आरएसवी-87, आरएस-138, जेएल-24, आरजी 141
		तिल	टीसी-25, प्रताप, आरटी-46, 125, 103
		अरण्डी	अरूणा, गॉच-1, जीएसएच-4
		मूंग	के-851, पूसा बैसाखी, एमएल-131, 267
		उडद	कृष्णा, टी-9, पन्तयू 19 आरबीयू 38 (बरखा)
		अरहर	प्रभात, ग्वालियर-3, यूपीएएस-120, आईसीपीएल 151, 87
	चारा उत्पादन हेतु	ज्वार	राजचरी, 1, 2, एमपी चरी, पूसाचरी 1,6
	उपयुक्त किस्में	बाजरा	जायन्ट बाजरा, राजको
		बरसीम	जेबी-1, वरदान
		रिजका	टी-8, 9 आनन्द-2
		जई	केन्ट
		ग्वार	दुर्गापुरा सफेद
	फलोत्पादन हेतु	आम	लंगडा, दशहरी, आम्रपाली
	उपयुक्त प्रजातियां	अमरूद	इलाहाबाद सफेदा, लखनऊ-49
		नीबू	कागजी, बारहमासी
		संतरा	नागपुर, किन्नो
		बेर	गोला, सेव, मूण्डिया, उमरान
		आंवला	बनारसी, चकैया, कृष्णा, एनए-7
		अनार	गणेश
भरतपुर	अलवर, भरतपुर,	बाजरा	डब्ल्यूसीसी 75, एचएचबी-67, एमएच 179, एमएच 169,
धौलपुर,			आइसीटीबी 8203, आइसीएमएच-356
	सवाईमाधोपुर	ज्वार	सीएसएच 6, 9, एसपीवी-245
		मक्का	सफेद गंगा 11, संकुल अगेती-76, बस्सी सलैक्टेड
		चंवला	सी-152, एफएस-68, आरसी-19, वी-240
		सोयाबीन	टी-49, गोरव, मोनेटा, एमएसीएस 58, पीएस-16
		मूंगफली	आरएस-1, एम-13, बारएसबह-87, एके-12-24
		तिल	टी-13, टीसी-25, आरटी-46, प्रताप, आरटी-125
		मूंग	के-851, पूसा बैसाखी, एस-8
		उडद	टी-9
		ग्वार	दुर्गाजय, दुर्गापुरा सफेद, आरजीसी 96, 986, 1003
	चारा उत्पादन हेतु	मक्का	अफ्रीकन टोल, गंगा-5, विजय, किसान
	उपयुक्त किस्में	ज्वार	राजचरी, 1, 2, एमपी चरी, पूसाचरी 1, 6, एसएसजी-59
		बाजरा	जायन्ट बाजरा, राजको
		बरसीम	जेबी-1, वरदान
		रिजका	टी-8, आनन्द-2
		जई	केन्ट
		ग्वार	दुर्गापुरा सफेद

फलोत्पादन हेतु उपयुक्त किस्में	आम	लंगडा, दशहरी, आम्रपाली
	अमरूद	इलाहाबादी सफेदा, लखनऊ-49
	नींबू	कागजी, बारहमासी
	बेर	गोला, सेव, मूण्डिया,
	आंवला	बनारसी, चकैया, कृष्णा, एनए-7
	अनार	गणेश।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

WASTELAND, WATERSHED DEVELOPMENT & SOIL CONSERVATION DEPARTMENT

No. F 6 (12) RD/2/96 pt. III Jaipur, Dated : 18. 07. 2006

ORDER

Sub. : Instructions for Community Development & Training under Hariyali guidelines.

Watershed works are being implemented under various schemes as per Hariyali guidelines. 5% of the total funds are ear-marked for various activities under Community Development & Training in watershed areas. Community Development and Training is a weak link of this programme which requires maximum attention as the success of watershed programme greatly depends on this. It has been observed that at times under sheer pressure of utilization of the community mobilization and training funds, the quality aspects take back seat. While organizing training, please ensure that it is-

- to strenghthen those processes and skills that help in the delivery of activities.
- to convey technical subject matter.
- to develop communication skills &
- to increase community participation.

The following instructions need to be followed:

(i) The sensitization and orientation of Watershed Project Management to all concerned functionaries and elected representatives should be given as the projected is sanctioned.

(ii) Community mobilization and training should be under-taken prior to taking up physical works of the watershed, following para 25 of the guidelines.

(iii) Reputed & experienced NGO's could also be engaged to under-take Community Organisation & training after signing an MOU, as being practised in DPIP.

(iv) WDT should be trained in IGPRS or through reputed NGO's as per the training module of IGPRS, at Block/Distt. HQ's.

(v) A module of community Mobilization and training under RD Schemes has been enclosed, covering important activities alongwith tentative provision, which are indicative. Selected activities may be included as per requirement of the watershed area and actual cost/expenditure may be charged. If any other activity or training is to be organised outside thisenclosed list, prior approval of Commissioner, Watershed be obtained.

(vi) It may be ensured that all kinds of community mobilization & training activities need to be completed within the stipulated period of 3 years from the sanction of the project.

Encl : As above Guidelines.

Sd/-

Pr. Secretary (RD & PR)

Copy for information and necessary action :-

1. P.S. to Pr. Secretary, RD & PR Department, Rajasthan, Jaipur
2. P.S. to Commissioner, WWD & SC, Rajasthan, Jaipur.
3. Additional Director, WWD & SC, Rajasthan, Jaipur.
4. Deputy Secretary (LR), WWD & SC, Rajasthan, Jaipur.
5. Chief Accounts Officer, WWD & SC, Rajasthan, Jaipur.
6. Joint Director, WWD & SC, Ajmer, Jaipur, Bhilwara, Kota, Jodhpur, Udaipur.
7. Joint Director, ADM./MOAP/PFC/MIES, WWD & SC, Rajasthan, Jaipur.
8. All CEO, Zila Parishad ..... for needful action and further transmission to concerned officers/officials.
9. All PO (LR), ZP .....

Sd/-

Commissioner

MODULE OF COMMUNITY MOBILIZATION AND TRAINING UNDER RD SCHEMES

S. N.	Activities	Training Needs	Who will Organise	Where it should be Organised	Duration	Tentative Expenditure
1	2	3	4	5	6	7
A.	**COMMUNITY MOBILIZATION**					
1.	Orientation for watershed inhabitants and public representatives. Cost and period of the project	**Watershed inhabitants and Public representatives :-** - Watershed concept - Problem of the Watershed - Cost and period of the project - Role of PIA, WDT & Watershed functionaries - Funding pattern - Utilization of funds, etc.	PIA	GP/ Watershed Level	1 day with the beginning of the project.	Rs. 5,000/-
2.	Awareness creation and publicity	**Awareness and publicity :-** - Slogan writing on wall and prominent places - Distributing pamphlets/hand bills - Pasting posters and banners - Pad yatra - Rallies of school children - Nukad natak - Cultural program. - Awareness camp - Watershed mela - Kishan mela - Organizing debate/essay competition on watershed activities - hoarding - Soil conservation week etc.	PIA/ WDT	Watershed area	within 6 months preferably	Rs. 25,000/-

1	2	3	4	5	6	7
.	Awareness generation through organizing camps (pertaining to national programmes)	**Organizing camps :-** - Organizing the community camps for small savings - Blindness control - Family welfare - Gram Sabha - Literacy campaign - Pulse polio campaign - Jal abhiyan etc.	PIA/ WDT	GP/ Watershed Area	As and when required within 1st three years	Rs. 10,000/-
B.	**TRAINING**					
4.	Training of WDT member (Engineering, Agriculture, Animal Husbandry & Social Scientists)	**WDT members :-** - Watershed concept - Objective & principle - Institutional structure and operational feature - Attitude and behavior change - Mechanism of monitoring and evaluation - Process management system - Basic foundation course (Base line survey, conflict resolution contstraint analysis, DPR, Action Plan, output indicators) - PRA - Communication - Skill enhancement - Emphasis on empowerment of women and weaker section, etc - Exit protocol - Post project management	PIA/	ZP level	6 days within two months	Rs. 6,000/- (out of administrative overheads)
5.	Training of watershed functionaries and public representative (Sarpanch, Secretary, UGs, SHGs Volunteers, Van Rakshak).	**Sarpanch & Users Group Members :-** - Watershed concept and operational guidelines - Supervision & execution of works - Roles and responsibilities. - Issues : Shramadan, Gramkosh, Equity gender, WDF	PIA	District Level/ PTC/KVK	3 days within 1st three years	Rs. 60,000/-

1	2	3	4	5	6	7
The entire watershed community to be organised in to groups based on activities pertaining to Watershed (UG) or income generation (SHG).		- Layout & Measurement - Exposure visit, etc				
		Watershed Secretary :-				
		- Watershed concept and operational guidelines. - Supervision of works. - Roles and responsibilities of Secretary. - Issues : Sharamdan, Gramkosh, Equity gender. - layout & Measurement - Reporting - Record keeping - Transparency - Exposure visit, etc.			6 days within 1st three years	
		Volunteers :-				
		- PRA, participatory planing - Mapping exercises. - Conducting measurements - Maintenance of Assets - Exposure visit, etc			2 days within 1st three years	
		SHG :-				
		- Group Dynamics - Rules and regulation regarding group function, membership, responsibility of office bearers. - Fund flow. - Reporting, recording and monitoring. - Benefit sharing principles and agreements. - Activities based training. 1. Shoe making 2. Carpentry 3. Bee keeping 4. Basket making 5. Muda making 6. Mushroom cultivation			2-3 days at a time within 1st three years	

1	2	3	4	5	6	7
	7. Black smithing etc. - Exposure visit Women Empowerment : - Ensure participation and representation - Natural resource management - Issues like equity, sustainability - Group management - Saving and credit, micro-enterprise - Account keeping reporting and record keeping - Exposure visit, etc.			2-3 days within 1st three years		
6. Skill development trainings at Watershed/Village level for beneficiaries of watershed	**May-June :** - Awareness and skill enhancement for cattle care - Skill enhancement for kharif crop & fodder production - Jal Sanchaya & water management - Forestry & Agro forestry Planation - Orchard (fruit) - Pasture development - Water table recording - Data recording to analyze the benefit from watershed treatment, etc. **September-October :** - Awareness and skill enhancement for cattle care, - Skill enhancement for Rabi crop & Fodder production - Tendering operations. - Data recording to analyze the benefit from watershed treatment, etc. - Usufruct collection/user charges/sharing	PIA/ WDT area	GP/ Watershed three years	2 year within 1st	Rs. 20,000/-	

1	2	3	4	5	6	7
C.	**EXPOSURE VISIT**					
7.	Exposure visit (Sarpanch, Secretary, UG & SHG members, WDTmember, beneficiaries).	To visit within the district or outside district/state (Successful watershed activities)	PIA	Within district/ outside district	7 days within 1st six months	Rs. 30,000/-

* *In a project of 500 ha. in 1st year Rs. 90,000/-, in 2nd & 3rd year Rs. 30,000/- each need be spent for community mobilization and training*

* *For WDT training, ZP can spend Rs. 6,000/- per project for quality training from its administrative overheads.*

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(भू-संसाधन प्रकोष्ठ)

कमरा नं. 153, कृषि पंत भवन

क्रमांक प. 2 (104) ग्रावि/भूसं/2/2005 जयपुर, दिनांक 01.08.2006

परिपत्र

विषय : जलग्रहण विकास कार्यक्रम यथा मरू विकास कार्यक्रम, सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम एवं बंजर भूमि विकास कार्यक्रम की क्रियान्विति-हरियाली मार्गदर्शिका की भावना के अनुरूप।

राज्य में जलग्रहण परियोजनायें मरू विकास कार्यक्रम, सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम एवं एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम अन्तर्गत भारत सरकार की मार्गदर्शिका ''हरियाली '' के अनुसार क्रियान्विति की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भूमि व जल संरक्षण के माध्यम से काश्तकारों व भूमिहीन मजदूरों के Livelihood का मजबूत आधार तैयार करना है। इसलिए इन योजनाओं की सफलता Users की सक्रिय भागीदारी पर भी निर्भर करती है। लेकिन यह देखा गया है कि प्रायः Community mobilization व प्रशिक्षण की गतिविधियों पर वांछित ध्यान नहीं दिया जाता और ना ही परियोजना की sequence of activities का क्रियान्वयन होता है। उदाहरण के तौर पर Production Plan बनाया ही नहीं जाता, जो कि परियोजनाओं का आधार है। इसलिए यह आवश्यक है कि मार्गदर्शिका के प्रावधानों के निहित चयनित जलग्रहण क्षेत्र में समन्वित रूप से विभिन्न गतिविधियों यथा भू-संरक्षण, जल संरक्षण, पशुधन विकास, चारागाह विकास, कृषि उत्पादन आदि के कार्य जन समुदाय को प्रेरित कर एवं ''प्रयोक्ता समूह '' (Users Groups) व स्वयं सहायता समूह (SHGs) का गठन कर करवाये जाने चाहिये।

उच्च अधिकारियों द्वारा परियोजनाओं के कार्यों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि जलग्रहण क्षेत्र में सिविल निर्माण कार्यों का निष्पादन मुख्य रूप से किया जा रहा है, जबकि मार्गदर्शिका के अनुच्छेद 16 में स्थापित व्यवस्था के अनुसार इस प्रकार की प्रवृति से बचना चाहिये।

जनसमुदाय को परियोजना से प्रभावी रूप से जोड़ने वाली गतिविधियां यथा सामुदायिक संगठन, स्वयं सहायता समूह तथा जलग्रहण विकास दल का गठन , प्रशिक्षण, पशुधन विकास एवं कृषि उत्पादन पर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जन समुदाय को परियोजना क्रियान्विति में उनकी भागदारी एवं भूमिका, मार्गदर्शिका में स्थापित संस्थागत व्यवस्था, राशि की उपलब्धता आदि की जानकारी पी.आई.ए. द्वारा नहीं दी जा रही है, जिसके अभाव में ग्रामवासी परियोजना से जुड़ नहीं पाते। इस कारण परियोजनाओं की सफलता पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगना स्वाभाविक है।

हरियाली मार्गदर्शिका की भावना के अनुरूप जनसाधारण को परियोजनाओं से जोड़ने के क्रम में कार्यक्रमों की प्रभावी एवं समुचित रूप से क्रियान्विति हेतु निम्न कार्यवाही प्रत्येक परियोजना में आवश्यकतानुसार की जावेः-

1. **सामुदायिक संगठन** : समुदाय को परियोजना से अर्जित होने वाले लाभ की जानकारी देकर उन्हें प्रेरित कर जोड़ना ताकि, अपेक्षित उद्देश्य की प्राप्ति संभव हो। इसके लिए प्रत्येक गतिविधि के लिए उससे लाभान्वित एवं प्रभावित होने वाले व्यक्तियों का प्रयोक्ता समूह बनाया जाये। संबंधित गतिविधि को उनके स्थानीय ज्ञान का उपयोग कर यथासम्भव उन्हीं से करवाया जावे ताकि, उस गतिविधि से उनका जुडाव हो एवं परियोजना अवधि समाप्त होने के पश्चात भी उसका संधारण हो सके और प्रयोक्ताओं को निरन्तर लाभ मिलता रहे।

2. **प्रशिक्षण** : उपभोक्ता समूह, स्व-सहायता समूह, जलग्रहण विकास दल, सरपंच, ग्राम सेवक, पी.आई.ए. हेतु यथा सम्भव समय समय पर प्रभावी प्रशिक्षण आयोजित किये जावे।

3. स्व-सहायता समूह को व्यावसायिक विकास के लिये मूल राशि (सीड मनी) उपलब्ध करायी जावे, उनको आर्थिक गतिविधि से जोडा जावे, प्रशिक्षण/एक्सपोजर दिया जावे।

4. समन्वित विकास हेतु विभिन्न गतिविधियों यथा उपलब्ध सतही व भूजल के बेहतर उपयोग हेतु drip व Spinkler Irrigation पद्धतियों, कृषि योग्य भूमि में फसल प्रदर्शन, उद्यानिकी विकास एवं कृषि वानिकी पौधारोपण कार्य, अकृषि भूमि में चारागाह विकास एवं वानस्पतिक कार्य तथा पशुधन विकास कार्यक्रम के तहत पशु चिकित्सा शिविरों के आयोजन की क्रियान्विति परियोजना क्षेत्र में सुनिश्चित की जावे।

5. वानस्पतिक गतिविधियों पर विशेषकर सामुदायिक एवं राजस्व भूमि तथा चारागाहों को विकसित करने पर अधिक ध्यान दिया जावे, इसके लिए बीज/पौधों की अग्रिम अव्यवस्था की जाकर वर्षा का पूरा-पूरा लाभ उठाया जावे, जिससे गरीब ग्रामवासियों को चारे, ईधन, छोटी इमारती लकड़ी का लाभ मिल सके।

6. कृषि विभाग की विशिष्ठ योजनाओं के तहत उपलब्ध अनुदान का लाभ काश्तकारों को सुनिश्चित कराना व विशेषतोर पर राष्ट्रीय बागवानी मिशन की सुविधायें काश्तकारों तक पहुंचाना।

7. परियोजना कार्यों पर मशीनरी के उपयोग से परहेज रख क्षेत्र के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराया जावे (पैरा-26)।

8. ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की प्रत्येक बैठक में परियोजना के कार्यों की लागत, प्राप्त राशि, व्यय राशि, भौतिक प्रगति आदि का विवरण ग्राम सेवक द्वारा प्रस्तुत किया जावे।

9. परियोजना के पूर्ण विवरण की जानकारी कार्य स्थल व ग्राम के मुख्य स्थानों पर बोर्ड लगाकर/दीवारों पर अंकित करवाकर दी जावे।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/परियोजना अधिकारी (भू-संसाधन)/पी.आई.ए. सुनिश्चित करें कि परियोजना की सफल क्रियान्विति हेतु सभी गतिविधियों की जानकारी आम समुदाय को देकर जिम्मेदार जलग्रहण विकास दल की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए आवश्यकतानुसार गतिविधियों को डी.पी.आर. में समावेश करवाकर उनकी समुचित क्रियान्विति करावें ताकि परियोजना अवधि समाप्त होने के उपरान्त समस्त गतिविधियों का रख-रखाव कर अनवरत रूप से लाभ उठाया जा सके। इन कार्यों को सफलतापूर्वक व समयबद्ध ढंग से सम्पन्न करनेहेतु एक Schedule of activities मय समय सारणी, इस परिपत्र के साथ संलग्न है। इन गतिविधियों का संचालन इसी क्रम में निर्धारित समय में सम्पन्न कराने का उत्तरदायित्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, परियोजना अधिकारी (भू-संसाधन) व विकास अधिकारी का होगा। जहां कही भी इसमें Deviation पाई गई तो, तीनों को उत्तरदायी ठहरा कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

ह./-

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. अतिरिक्त निदेशक, प्रथम/द्वितीय, मुख्यालय ।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त (श्री गंगानगर के अतिरिक्त)।
3. संयुक्त निदेशक, बंजर भूमि, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण वृत जयपुर/अजमेर/उदयपुर/भीलवाड़ा/कोटा/जोधपुर।

ह./-

आयुक्त

YEARWISE BREAKUP OF ACTIVITIES WITH PERMISSIBLE FINANCIAL OUTLAY AS PER PROVISIONS OF THE GUIDELINES

(Rs. In lacs)

S. No.	Activity	Time for Completion from date of sanction of GOI	1st yr.	2nd yr.	3rd yr.	4th yr.	5th yr.	Total
1.	Allotment of project to PIA	1 months	-	-	-	-	-	-
2.	Appointment of WDT	45 days						
3.	Soil Survey and Soil Analysis, Calculations of availability of Ground Surface Water in watershed area and justification of a draft production plan with the objective of increasing productivity and production through efficient use of available water, changed cropping pattern, use of High Yield Variety seeds, organic farming, improving soil health etc. by WDT.	70 days						
4.	Training & Community Mobilisation		0.90	0.30	0.30			1.50
	* PIA	60 days						
	* WDT	60 days						
	* G.P. members	80 days						
	* Watershed Community							
	* Awareness creation and publicity							
	* Constitution and training of SHGS' and UGS' and their training							
	* Exposure visits	85 days						
	* Capacity building of PO (LR), Sarpanch, Gram Sewak							
5.	Prioritization of problems on constraint analysis and technical and participatory solution (PRA) & finalization of production plan	105 days						
6.	A. Preparation of DPR based on production plan, its approval by Gram Sabha, followed by ZP.	180 days						
	B. Natural Resources Management Plan							
	* Water Conservation Measures		3.00	8.10	8.10	3.9	2.4	25.50
	* Soil Conservation Measures with vegetative Cover*	Agricultural Production Plan						
	(i) Kharif-Crops							
	Fodder							
	(ii) Rabi-Crops							
	Fodder							
	* Nursery Development							
	* Horticulture Development							
	* Agro Forestry							
	* Planting of Medicinal, aromatic and Herbal plants							
	* Pasture Development							
	* Vermi Compost unit Establishment							

* Live stock Development

7. Post Project Management
   * Training
   * Exit Protocol
   (i) User charges
   a. Imposition
   b. Collection
   (ii) Use of WDF on maintenance of Common Property Resources
   * Sharing of usufruct

8. Administrative overheads

(i) PIA		0.294	0.294	0.294	0.294	0.294	1.47	
(ii) GP		0.294	0.294	0.294	0.294	0.294	1.47	
(iii)	Zila Parishad		0.06	-	-		-	0.60

---

* Important points to be strictly adhered in schedule of activities at appropriate place.
* Constitution of full contingent of WDT.
* SHG meeting regularly with a common interest, Revolving fund of Rs. 10,000 should be given after 6 months of its Constitution.
* Mid Term Evaluation of Projects before submitting proposal of 3rd installment.
* Action Taken Report on the points suggested in MTER.
* Meeting of DWDC as per norms.
* Display Boards on every watershed with full details.
* Social Audit of project in Gram Sabha.
* No overlapping of area and No duplication of funds to be ensured.
* CA audit of accounts every year before 30 June.
* Meeting of Gram Panchayat every month.
* Project works sanctioned in DPR to be completed as per fix time schedule (4 & Half years).

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, बंजरभूमि, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक प. 5 (2) आरडी/एलआर/2/2006-07 जयपुर, दिनांक : 07.08.2006

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद (श्री गंगानगर के अतिरिक्त)।

विषय : रबी 2006-2007 में फसल प्रदशनों के आयोजन के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य में जलग्रहण परियोजनायें मरू विकास कार्यक्रम, सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम एवं एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम अन्तर्गत भारत सरकार की मार्गदर्शिका ''हरियाली'' के अनुसार क्रियान्वित की जा रही है। उक्त योजनान्तर्गत जलग्रहण क्षेत्रों में कृषि भूमि में रबी 2006-07 में फसल प्रदर्शन आयोजित किये जाने है। फसल प्रदर्शनों के आयोजन में निम्नलिखित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जावेः-

1. फसल प्रदर्शन के आयोजन से पूर्व जलग्रहण क्षेत्रों के कृषकों में इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें। तत्पश्चात किसानों का चयन कर इन्हें प्रशिक्षित किया जावे। प्रशिक्षण में फसल की किस्मों का चयन नमी संरक्षण, भूमि एवं बीज उपचार, बीमारी एवं कीटों की रोकथाम सम्बन्धी तकनीकी जानकारी कृषि विशेषज्ञों से दिलवावे तथा भू एवं जल संरक्षण सम्बन्धी गतिविधियां प्रस्तावित हो तो उसे समय पर पूर्ण कराने का प्रयास करावें ताकि कृषकों को फसल प्रदर्शन में उक्त गतिविधियों का भरपूर लाभ मिल सकें।
2. हरियाली मार्गदर्शिका के पैरा 26 के बिन्दु संख्या (ix) के अनुसार नई फसलों/किस्मों अथवा नवीन प्रबंध प्रक्रियाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए फसल प्रदर्शन आयोजित किया जावें।
3. फसल प्रदर्शन में आदान व्यवस्था कृषि विभाग की पैकेज ऑफ प्रैक्टीसेज में दी गई सिफारिश के अनुसार की जावें।
4. प्रदर्शन आवंटन हेतु कृषकों का चयन करते समय महिला कृषक अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग तथा लघु एवं सीमान्त कृषकों को प्राथमिकता दी जावे।
5. जलग्रहण विकास दल में कृषि से सम्बन्धित सदस्य की सेवाओं का भरपुर उपयोग किया जावे।
6. तुलनात्मक अध्ययन हेतु प्रदर्शन स्थल के समीप नियंत्रित प्लाट (कन्ट्रोल प्लाट) भी चिन्हित किया जावें।
7. फसल प्रदर्शन ऐसे स्थानों पर आयोजित हो, जहां सभी की आसानी से पहुंच हो सकें एवं अन्य कृषक इसे देखकर लाभ उठा सकें।
8. चयनित कृषकों के खेत की मिट्टी एवं पानी की जांच करवाकर प्रदर्शनों में फसल की आवश्यकतानुसार जो तत्वों की मात्रा के अनुरूप खाद एवं उर्वरक का प्रयोग सुनिश्चित करें।
9. प्रदर्शन के आयोजन हेतु बीजों की व्यवस्था राजस्थान राज्य बीज निगम के क्षेत्रीय कार्यालय/डिपो एवं अन्य आदानों की व्यवस्था नियमानुसार सुनिश्चित किया जावे।

फसल प्रदर्शनों के आयोजन के लिए राज्य की जलवायु एवं भोगौलिक स्थिति के अनुसार जॉनवाईज जिलावार उपयुक्त किस्मों कावरण संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। यदि, प्रदर्शन आयोजित करने में किसी प्रकार की कठिनाई महसूस की जावे तो अविलम्ब विभाग को अवगत करावे, ताकि यथा समय पर उचित कार्यवाही की जा सकें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

Sd/-
आयुक्त
जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण

प्रतिलिपि :-

1. अति. निदेशक प्रथम/द्वितीय आयुक्तालय बंजर भूमि
2. समस्त संयुक्त निदेशक वृत जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण।

Sd/-
परियोजना अधिकारी (भू-संसाधन)

जोन/जिलेवार रबी 2006-07 हेतु कृषि भूमि में फसल प्रदर्शन हेतु उन्नत किस्म/प्रजातियों का विवरण

जोन	जिले	फसल	उपयुक्त किस्में
जयपुर	जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक	गेहूं	राज. 1482, राज 1555, राज 3077, डब्ल्यूएच 147, राज. 3765, राज. 3777 (2003)
		जौ	आरडी 2052, आरडी 2664, आरडी 2592, आरडी 2552, आरडी 2624, आरडी 31, आरडी 103, बीएल-2, आरडी 2503, आरडी 2035
		चना	सीएसजेडी 884 (आकाश) आरएसजी-888 (अनुभव), सी-235 एच-208 आरएसजी-44
		सरसों	लक्ष्मी, बायो 902 (पूसा जय किसान), पीआर 15 (क्रांति) पूसा बोल्ड, टी-59 (वरुणा)
कोटा	कोटा, झालावाड, बूंदी, सवाईमाधोपुर	गेहूं	राज 4037, पीडी डब्ल्यू 215, जीडब्ल्यू 322, एचडी 4672, जेडब्ल्यूएस-17, एचडब्ल्यू 2004, राज 3765, जीडब्ल्यू 273, राज. 3777, मुक्ता (एचआई 385), डब्ल्यूएच 147, राज 3077, ए-9-30-1, डी-134
		जौ	आरएस-6, आरडीबी 1, आरडी 31, आरडी 57, आरडी 103, बी.एल.-2 (बिलाडा-2) आरडी 387 (राजकिरण)
		चना	सी-235, एच-208, दोहदयलो, बीजो 256, जीएनजी-149, फूलेजी-5
		सरसों	पीआर-15, आरएच-30, टी-59 (वरूणा) पीआर 45, पूसा बोल्ड, बायो 902, माया (आरके 9902) वसुन्धरा (आरएच 9304) अरावली (आरएन 393), स्वर्ण ज्योति (आरएच 9802)
जोधपुर	जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू	गेहूं	राज 1482, राज 1972, राज. 3077, डब्ल्यूएच 147, खारचिया-65, राज 3765,
		जौ	आरडी 2052, आरडी 2035, आरडी 57, आरडी 103, बीएल 2, आरडी 31
		चना	दोहद यलो, सी-235, एच-208, आरएसजी-44, आरएसजी-2, आरएसजी-888
		सरसों	ट-59, आरएच-30, पीआर-15, बायो 902, जीएम-2, उर्वशी
		तारमीरा	टी-27, आइटीएसए
गंगानगर	श्रीगंगानगर, हनुमानगढ	गेंहूं	राज 1482, राज 3077, राज. राज 3765, एचडी-2329, एचडी-2687, राज-3777, पीबीडब्ल्यू 343, पीबीडब्ल्यू-373, पीबीडब्ल्यू-226, डब्ल्यूएस-47, सीपीएल-3004, एचडी-2285 एचडी 2009
		जौ	आरडी 2052, आरडी 57, बीएल-2, आरडी 2035, आरडी 2508
		चना	सी-235, एच-208, आएसजी-44, जीएनजी-146, जीएनजी-663, जीएनजी-469, आरएसजी-888 (2003) आरसीसी-32, जीएनजी-1292 (2002)
		सरसों	टी-59, (वरुणा), क्रान्ति, आरएच-30, बायो-902, (पूसा जय किसान), पूसा बोल्ड, आरएलएम-619, रजत पीसीआर-7 (1997), आरएन-393 (अरावली) (2001), आरजीएन-13, आरएच-8812 (लक्ष्मी)।
		तारामीरा	आइटीएसए, टी-27, आरटीएम-314 (2001)
भरतपुर	अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर	गेहूं	पीडब्ल्यू-343 (1996) राज. 3765, डब्ल्यूएच-542, सीपीएल-3004, डब्ल्यूएच-147, राज 3077, राज 2184, एचडी-2236, राज 1972, राज-1482, एचडी 2329, एचडी 2285.
		जौ	आरएस-6, आरडीबी-1, आरडी 2052, आरडी 31, आरडी 2035,

			आरडी 57, आरडी 103, बीएल-2, आरडी 387, आरडी 2503 (1997)
		चना	सी 235, जी-130, एच 208, आरएसजी-44, आरएसजी-2
		सरसों	आरएन 393, टी-59, पूसा बोल्ड, आरएच 30, कृष्णा, लक्ष्मी, आरएल 1359, पीआर 15 (क्रांति), बायो 902, आरएच-819, रजत (पीसीआर-7)
		तारामीरा	टी-27, आरटीएम-314
उदयपुर	सिरोही,	गेहूं	डब्ल्यूएच 147, राज 3077, जीडब्ल्यू 190, राज 3765, जीडब्ल्यू 273,
	उदयपुर,		राज 3777, जीडब्ल्यू 322 (2001) राज 4037 (2005) राज. 1555,
	राजसमन्द		मालवशक्ति एचआई-8498 (1999), एचआई 8627 (2005)
	भीलवाड़ा	जौ	आरडी 103, बीएल-2, आरडी 387, आरडी 2552, (2000)
	चित्तौड़गढ़		आरडी 2052, आरडी 2035, आरडी 2503, आरडी 2508
		चना	आरएसजी 44, दाहोदयलो, जीएनजी 16, आएसजी 2, (किरण), आईसीसीवी 10 (1992) आरएसजी-888, प्रताप चना-1 (2004)
		सरसों	टी-59, बायो-902, लक्ष्मी
		तारामीरा	टी-27, आरटीएम-314
भीलवाडा	पूर्व सिरोही,	गेहूं	राज-3077, जी. डब्ल्यू.-190, जीडब्ल्यू-273 (1998) राज 3765 (1996),
	उदयपुर		एचआई-8498 (1999), केआरएल-19 (2000) जीडब्ल्यू-322 (2001),
	राजसमन्द		राज 3777 (1998)
	चित्तौड़गढ़	जौ	आरएस-6, आरडीबी-1, आरडी-31, आरडी-57, आरडी-103, बीएल-2 (बिलाडा-2), आरडी- 2552 (2000)
		चना	एच-208, आरएसजी-44, दाहोद यलो, जीएनजी-16, आईसीसीवी.10, आरएसजी- 888
		सरसों	टी-59 (वरूणा), बायो 902, लक्ष्मी,
		तारामीरा	टी-27, आरटीएसए, आरटीएम-314

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, बंजरभूमि, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक प. 5 (2) आरडी/एलआर/2/2006-07 जयपुर, दिनांक 29.8.2006

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद (श्री गंगानगर के अतिरिक्त)।

विषय : जलग्रहण क्षेत्रों में भूमि विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत मृदा स्वास्थ्य कार्ड (Soil Health Card) वितरण हेतु लक्ष्यों के आवंटन के क्रम में।

जैसाकि विदित है कि वर्तमान कृषि परिपेक्ष्य में मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन उत्पादकता वृद्धि का महत्वपूर्ण पहलू है। सघन कृषि पद्धतियों के प्रचलन, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग, मृदा कटाव, जैविक खादों का नाम मात्र उपयोग के फलस्वरूप मृदा की उर्वरता एवं उत्पादकता तेजी से क्षीण हो रही है तथा मृदाओं में प्रायः एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी देखने को मिलती है। टिकाऊ कृषि के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन अति आवश्यक है।

राज्य में जलग्रहण विकास परियोजनायें मरू विकास कार्यक्रम, सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, एकीकृत बंजर भूमि कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय जलग्रहण कार्यक्रम अन्तर्गत भारत सरकार की मार्गदर्शिकाओं के अनुसार क्रियान्वित की जा रही है। उक्त कार्यक्रम में कृषि योग्य भूमि में फसल/चारा के प्रदर्शन आयोजित किये जाते है। फसल प्रदर्शनों में खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग कृषि विभाग द्वारा जारी पैकेज ऑफ प्रैक्टीसेज के अनुसार किया जाता है जबकि, भूमि में उर्वरता पोषक तत्वों की मात्रा में काफी भिन्नता होती है, इसलिए प्रत्येक जलग्रहण क्षेत्रों में कम से कम 20 कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण करने का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार ने वर्ष 2006 को ''मृदा उत्पादकता वृद्धि वर्ष'' के रूप में मनाने का सकल्प लिया है। कृषि विभाग द्वारा ''कृषि योजनायें आपके द्वार'' एक अभियान के रूप में लिया जा रहा है।

उक्त अभियान में मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण व मिट्टी के नमूनों का एकत्रीकरण करने हेतु जिलेवार लक्ष्यों का आवंटन परिशिष्ठ ''अ'' पर संलग्न है। जलग्रहण क्षेत्रों में जलग्रहण विकास दल के कृषि विषय से सम्बन्धित सदस्य के मार्गदर्शन में मिट्टी के नमूने एकत्रित कराये जायेंगे। जलग्रहण क्षेत्रों में रबी 2006 में आयोजित किये जाने वाले फसल/चारे के प्रदर्शनों हेतु मिट्टी के नमूने एकत्रित कर संलग्न तालिका के अनुसार मिट्टी परीक्षण प्रयोग शालाओं में भिजवाये जाने है।

मिट्टी के नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशालाओं द्वारा मुख्य पोषक तत्वों हेतु क्रमशः 5 रूपये (स्थिर प्रयोगशाला) व 10 रूपये (भ्रमणशील प्रयोगशाला) जांच सेवा शुल्क लिया जाता है तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे जिंक, कॉपर, आयरन, मैगनीज आदि की जांच हेतु 20 रूपये प्रति नमूना जांच सेवा शुल्क निर्धारित है। उक्त भुगतान परियोजना मद से किया जावेगा।

मिट्टी का नमूना लेने का तरीका–

1. नमूना लेने से पूर्व खेत की ढाल, मिट्टी का रंग, गठन एवं फसल प्रबन्ध आदि के बारे में जानकारी होनी चाहिये। खेत में मिट्टी बनाव, ढलान एवं रंग समान नहीं होने पर विभिन्न टुकड़ों में बांटकर प्रत्येक क्षेत्र का अलग अलग नमूना लेवें।

2. असाधारण स्थान, रास्ता, सिंचाई की नाली, मेड, खाद के ढेर, पेड के पास, कुऐं के पास, दलदली जगह आदि से नमूना न लेवें।3. मिट्टी परीक्षण हेतु 0 से 15 सेमी तक की गहराई से मिट्टी का नमूना लिया जाता है, लेकिन यदि ट्रेक्टर आदि से गहरी जुताई की जाती है तो यह 20 सेमी की गहराई तक लिया जा सकता है।

4. नमूना लेने हेतु खेत को समान गुणों वाले भागों में बांटकर अलग-अलग नमूने लेवें। मिट्टी की उपरी सतह से घास काटकर नमूने लेने हेतु 8-10 स्थानों का चयन करें। चयनित स्थानों पर खुर्पी या फावडा से 15 से 20 सेमी की गहराई तक 'V' के आकार का गड्डा बनायें, फिर इसकी दीवार के साथ पूरी गहराई तक मिट्टी की एक इंच मोटी एक समान परत काटकर एक परात में एकत्रित करें। इस प्रकार सभी चयनित स्थानों से मिट्टी एकत्रित करें। फिर पूरी मिट्टी को अच्छी तरह से मिलाकर साफ कपड़े पर डालकर फैलावें एवं चार समान भागों में बांटे। चार में से आमने सामने के दो भाग फेंक दे। आमने सामने के दो भाग की मिट्टी को फिर मिलाकर चार समान भाग बनाये एवं आमने-सामने के दोनों भाग रखें एवं दो भाग फेंक दें। यह कार्य तब तक दोहराते रहें जब तक की मिट्टी का नमूना आधा किलो का न रह जाये। नमूने को कपड़े अथवा प्लास्टिक की

थैली में भरे। दो मोटे कागज के टूकडों पर कृषक, जलग्रहण का नाम, गांव, पंचायत समिति का नाम, खसरा नं. फसल का नाम, सिंचित/असिंचित समस्याग्रस्त भूमि हो तो ''भूमि सुधार हेतु'' एवं अन्य कोई विशेष जानकारी हो तो विवरण लिखकर एक थैली के अन्दर व दूसरा थैली के बाहर मूंह पर बांधे। इसके बाद नमूने को मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला को भेजे। तत्पश्चात सम्बन्धित प्रयोगशालाओं द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाकर वितरण किया जावेगा। कार्ड में अंकित सिफारिश के अनुसार प्रदर्शन आयोजित कराया जाना सुनिश्चित करावें।

ह./-

आयुक्त

बंजर भूमि, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण

प्रतिलिपिः-

1. अपर सचिव, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को उनके अर्द्ध शासकीय पत्रांक न. 8-7/2006-एनआरएम-।, 14 जुलाई 2006 के क्रम में।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर।
4. निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव, कृषि विभाग पंत कृषि भवन को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित मृदा परीक्षण प्रयोगशाला प्रभारी को जलग्रहण क्षेत्रों में मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण प्राथमिकता से करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करे।
5. अति. निदेशक प्रथम/द्वितीय आयुक्तालय बंजर भूमि जलग्रहण विकास विभाग।
6. संयुक्त निदेशक (MOAP) आयुक्तालय, जयपुर
7. समस्त संयुक्त निदेशक, वृत जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण।

ह./-

आयुक्त

मृदा स्वास्थ्य कार्ड (Soil Health Card) वितरण हेतु जिलेवार लक्ष्य

क्र. सं.	नाम जिला	जलग्रहण क्षेत्रों की संख्या	वितरित किये जाने वाले मृदा स्वास्थ्य कार्डो की संख्या	आवंटित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला का नाम
1.	जयपुर	60	1200	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला दुर्गापुरा, जयपुर
2.	दौसा	26	520	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, दौसा
3.	अलवर	6	120	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, अलवर
4.	सीकर	358	7160	मोबाइल मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, सीकर
5.	झून्झुनू	311	6220	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, झून्झुनूं
6.	चुरू	390	7800	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, चूरू
7.	अजमेर	240	4800	मोबाइल मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, अजमेर
8.	टोंक	112	2240	मोबाइल मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला,टोंक
9.	नागौर	573	11460	मोबाइल मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, नागौर
10.	उदयपुर	156	3120	मोबाइल मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, उदयपुर
11.	बांसवाड़ा	238	4760	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, बांसवाड़ा
12.	डूंगरपुर	159	3180	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, डूंगरपुर
13.	कोटा	64	1280	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, कोटा
14.	बूंदी	4	80	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, बूंदी
15.	झालावाड़	105	2100	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, झालावाड
16.	बारां	74	1480	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, बारां
17.	सवाईमाधोपुर	45	900	मोबाइल मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, सवाईमाधोपुर
18.	करौली	54	1080	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, करौली
19.	भरतपुर	32	640	मोबाइल मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, भरतपुर
20.	धौलपुर	15	300	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, धौलपुर
21.	जोधपुर	566	11320	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, जोधपुर
22.	बाडमेर	576	11520	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, बाडमेर
23.	पाली	473	9460	मोबाइल मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, पाली
24.	जालौर	357	7140	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, जालौर
25.	बीकानेर	448	8960	मोबाइल मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, पाली
26.	जैसलमेर	519	10380	STL, IGNP, CAD, बीकानेर
27.	सिरोही	68	1360	मोबाइल मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, सिरोही
28.	हनुमानगढ़	106	2120	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, हनुमानगढ़
29.	भीलवाड़ा	41	820	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, भीलवाडा
30.	राजसमंद	72	1440	मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, राजसमंद
31.	चित्तोडगढ़	60	1200	मोबाइल मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, चित्तौडगढ़
	कुल	**6308**	**26160**	

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(भू-संसाधन प्रकोष्ठ)

कमरा नं. 153, कृषि पंत भवन

क्रमांक : एफ. 15 (4) ग्रावि/भू.सं./2/06 जयपुर, दिनांक : 04.09.2006

परिपत्र

भूमि संसाधान विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जलग्रहण विकास परियोजनाओं हेतु जारी की गई मार्गदर्शी सिद्धान्त ''हरियाली'' के पैरा 15 के अन्तर्गत प्रत्येक परियोजना क्रियान्वयन अभिकरण (PIA) अपने कर्तव्यों को जलग्रहण विकास दल (WDT) नामक एक बहुआयामी दल के जरिये पूरा करेगा। इसके लिए 10 जलग्रहण परियोजनाओं के लिए एक 4 सदस्यीय जलग्रहण विकास दल का गठन किया जाना अनिवार्य है। अधिकांश जिलों द्वारा जलग्रहण विकास दल का गठन किया जाकर उनको 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिलवाया जा चुका है।

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार कंसलटेन्सी लेने की व्यवस्था नियम 38ए के एपेन्डिक्स 5 में दी गई है, इसके अनुसार परियोजना क्रियान्वयन अभिकरण और जलग्रहण विकास दल के सदस्यों के बीच एक अनुबन्ध किया जाना वांछनीय है। अतः जलग्रहण विकास दल के लिए सौ रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस प्रकार का अनुबन्ध करवा लिया जावे ताकि भविष्य में कोई विधिक कठिनाई नहीं आवे, ड्राफ्ट एग्रीमेन्ट की प्रति संलग्न है।

जलग्रहण विकास दल का जलग्रहण परियोजनाओं के लिए जो सामूहिक दायित्व है, उसका विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न किया जा रहा है। कुछ उनकी विशेषज्ञता से संबंधित ऐसे दायित्व हैं जिन्हें उनको व्यक्तिगत रूप से निष्पादन करने हैं, सामाजिक विज्ञानी के लिए परिशिष्ट-ख पर, कृषि विज्ञानी का परिशिष्ट-ग पर, पशुपालन विशेषज्ञ का परिशिष्ट-घ पर और अभियांत्रिकी विशेषज्ञ का परिशिष्ट-च पर उनके दायित्वों का विवरण संलग्न कर दिया गया है।

जलग्रहण विकास दल की सेवाएं परियोजना के लिए जब तक राशि प्राप्त होती रहे, तब तक ही ली जा सकेगी। सामान्यतया परियोजना अवधि 5 वर्ष है। एग्रीमेन्ट भरवाने का काम 30.9.2006 तक अनिवार्य रूप से पूरा कर लिया जावे। जलग्रहण विकास परियोजनाओं गति देने एवं गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए दल के सदस्य माह में 20 दिवस जलग्रहण परियोजनाओं का भ्रमण सुनिश्चित करेंगे। परियोजना क्रियान्वयन अभिकरण इनके कार्य एवं सामयिक भुगतान हेतु उत्तरदायी होंगे।

ह./-

उप सचिव (भू–संसाधन)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित हैः

1. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान। (गंगानगर को छोड़कर)
2. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति (गंगानगर जिले को छोड़कर)

ह./-

उप सचिव (भू–संसाधन)

AGREEMENT FOR CONSULTANCY SERVICES

This AGREEMENT (Agreement) is entered into this ..... by and between PIA (the client) having its Office located at ..... and Shri 1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. ..... members of WDT ..... having their office at .....

Whereas, the client wishes to have the WDT members performing the consultancy (hereafter referred as services) services under the Hariyali Guidelines issued by Ministry of Rural Development, Department of Land Resources, GOI for Watershed Project hereinafter referred to and Whereas, the WDT members severally and jointly are willing to perform these consultancy services,

Now therefore the 'Parties' hereby agree as follows :-

1. Consultancy Services.

1.1 The WDT members severally and jointly shall perform the consultancy services as specified in Annexure 'A' & 'B' in 10 alloted watershed projects in the jurisdiction of PIA. Description of services of WDT and its members and engaged in Project Implementation which is made as an integral part of this agreement (Services).

1.2 The WDT members shall provide the reports listed in Annexure 'B' within the time period.

1.3 The Client may find it necessary to postpone or cancel the assignment or shorten or extend its duration. In such case, every effort will be made to give the WDT as early as possible, notice of any change.

2. Term

The WDT members shall perform the services as specified in Annexure ''A'' and 'B' and other specific task relating to the activities given by the PIA.

3. For the services rendered pursuant to annexure 'A' and 'B' the client shall pay each WDT member an amount not to exceed the agreed ceiling. The amount has been established on the basis of ceiling fixed and works to be carried out by the WDT and its members as assigned by the client.

4. Payment of honorarium & TA/DA will be made on monthly basis as per activity executed inthe field on the rates approved by the client. If the number of visits fall short of the prescribed number, prorata deduction from honorarium and T.A./DA shall be made. If the PIA finds that work done by the WDT & individual member (s) is not satisfactory, a notice will be issued giving details of unsatisfactory performance. The WDT members would remedy those deficiencies and report to the PIA within 10 days and only thereafter the payment shall be released. The details of payment, number of visits & records to be maintained and reports are in annexure 'C'.

5. Performance Standard : The WDT members undertake responsibility to perform the Services with the highest standard of professional and ethical competence and integrity. Quantifiable and monitrable performance indicators shall be mutually fixed by WDT & PIA and this will form basis of performance measurement. If the client, finds the performance of the WDT member (s) unsatisfactory, it will notify to the concerned member, giving reasons, and ask for the members (s) to improve their work within 10 days. If after 10 days, the performance does not improve, the payment to the members (s) would be suspended till such time as the Client is satisfied with the performance of the WDT and the member.

6. Termination

6.1 By the Client : The Client may terminate this Contract, by not less than ten (10) days written notice of termination to the members (s) to be given after the occurrence of any of the events specified in paragraphs (a) through (b) of this Clause 6.1 and fifteen (15) days in the case of the event referred to in (c).

(a) if the WDT do not remedy a failure in the performance of their obligations under the Contract, within (10) days after being notified or within any further period as the Client may have subsequently approved in writing;

(b) if, as the result of Force Majeure, the WDT is unable to perform a material portion of the Services for a period of not less than fifteen (15) days; or

(c) if the Client in its sole discretion, decides to terminate this Contract.

6.2 By the WDT or its individual member : The WDT member may terminate this Contract, by not less than fifteen (15) days written notice to the Client, such notice to be given after the occurrence of any of the events specified in paragraphs (a) and (b) of this Clause 6.2.

(a) If the Client fails to pay money due to the WDT pursuant to this Contract and not subject to dispute to Clause 6.1 within fifteen (15) days after receiving written notice from the member that such payment is overdue; or

(b) If, as the result of Force Majeure, the WDT or member (s) is unable to perform a material portion of the Services for a period of twenty (20) days or more.

6.3 Payment upon Termination : Upon termination of this Contract pursuant to Clauses 6.1 or 6.2, the Client shall make the payments to the WDT of all such remuneration pursuant to Clause 3 for Services satisfactorily performed prior to the Effective date of termination.

7. **Assignment :** The WDT or its member shall not assign this Agreement or sub-contract any portion of it without the Client's prior written consent.

8. **Law Governing Contract and Language :** The agreement shall be governed by the laws of Union of India and the language of the Agreement shall be English.

9. The WDT members will be responsible for appropriate insurance coverage on their own and PIA will have no liability on this account.

10. **Taxes :** The WDT and its members shall pay the taxes, duties and other imposition levied under the applicable law and the Client shall perform such duties in this regard to the deduction of tax as may be lawfully imposed.

11. **Dispute Resolution :** Any dispute arising out of the Agreement, which cannot be amicably settled between the parties, shall be referred to CEO, Zila Parishad whose decision shall final and binding on the parties.

(Sh. .....)
For and behalf of PIA

WDT (i) ..... member
(ii) ..... member
(iii) ..... member
(iv) .....member

WITNESSES

(i) Name & address **Signature**
(ii) Name & address **Signature**

Annexure-A

DESCRIPTION OF SERVICES OF WDT ENGAGED IN PROJECT IMPLEMENTATION

1. The Government of Rajasthan with the support of the GOI is implementing water shed development programme in the district. The specific object of the watershed programme is to develop the area of the project for achieving long term benefits for providing livelihood to the resource poor by in-situ conserving water and increasing production through Agriculture, Horticulture, Forestry, Pasture Development, Livestock Development and drought/proofing along with checking migration of both human and animal wealth in the areas, as.

2. The WDT will :-

   (i) Mobilise the community and motivate them to work in a participatory manner and assist WDT in carrying out detailed PRA in watershed Villages.

   (ii) Identify a group of people for each watershed activity who may be affected most-the user group. The User Group should be involved in planning & execution of the activity and motivated to maintain accounts for the works/activities undertaken by group and own activity for subsequent maintenance.

   (iii) Improve the abilities of Panchayati Raj Institutions (PRIS') and watershed community in a participatory and cohesive manner to generate ownership feelings and to make watershed activities sustainable.

   (iv) Empower the community for social audit of watershed project and other RD schemes.

   (v) Arrange exposure visits to successful watershed for the stakeholders in consultation with PIA and ZP where users can see the demonstration of positive impact of Collaborative action on issues such as social fencing, equitable sharing, innovative technologies, sharing Usufructary rights on common properties etc.

   (vi) Arrange trainings for different stakeholders as prescribed by Commissioner, Wasteland Watershed Development & Soil Conservation Department.

   (vii) Identify homogenius groups out of Poor, SC, ST & Women into SHG's. An economic activity looking to the ability, skill & resources for each group need be selected. Arrange and upgrade their skills and establish forward and backward linkages for proper outputs as indicated below-

STAGE- 1

* Those villagers who are directly or indirectly dependent on the watershed need be enrolled as member of atleast one SHG.

* Separate SHG's be organised for Women, SC, ST, Agriculture labour, Shepherds etc.

* Meet regularly at least once in a month and take all their decisions by common consensus amongst the members.

STAGE- 2

* Organise trainings for SHGS'
* Encourage Thrift and Credit activities
* Encourage internal loaning amongst group members
* Arrange seed money from revolving fund and ensure its recovery
* Transact business with around 50% of the resources generated from amongst the members.

STAGE- 3

* Preparation of Project Report in Consultation with Bank Officers.
* Arranging Bank Credit for the groups.
* Take up income generating activities ensuring backward and forward linkages.
* Return the loan as per schedule.

Schedule for Completion of Tasks

* As payment is to be made monthly on the basis of task completed as per performance indicators given in annexe-C, the WDT is encouraged to complete all task during the specified time frame of this Agreement.
* The client will provide the WDT with the guidelines and other details necessary to execute job assigned to the WDT.

Output required of the WDT

The NGO is expected to furnish following outputs:

* Copies of useful materials developed during the PRA efforts and summaries of PRA findings.
* Details of SHGS' constituted and their bank account.
* Copy of plans prepared for maintenance of assets created, accompanied by statements of the support required by Users Groups and to be provided by the WDT.
* Reports on any conflicts arising and their resolution.

Monitoring of WDT work

* The Monthly progress of activities of WDT will be monitored by PIA and at district level by ZP in the prescribed format of Commissioner, Wasteland Watershed Development & Soil Conservation Department. At the State level, Commissioner WWDSC will review the details of activities carried out in the field, by the WDT.

Annexure-B

WDT REPORTING OBLIGATIONS

The WDT will initiate its activities in the project area/village assigned to it soon after signing the Agreement. It will report to CEO, Zila Parishad And BDO, Panchayat Samiti

The WDT written reporting obligations

A. An inception report within 15 days of the start of the assignment covering activities undertaken to date and monthwise plan of Action for the agreement duration and actual plan for the first quarter.

B. Regular monthly reports for the period of the agreement.

C. Final report after completion of the assignment.

Details to be provided by the WDT

* Staff available with the WDT for the assignment with their biodata.

* Awareness generation and community mobilization in the village/project area.

* PRA.

* Involvement of PRIS'.

Annexure-C

QUALIFICATION, DUTIES AND HONORARIUM TO WDT MEMBERS

[A] Team of the WDT

1. WDT team is required to mobilize community and impart training to the target group. Names of Key personnel with qualifications and experience in following format be given :

S. No.	Discipline	Name of Personnel	Qualification	Full time/ Part time
1.	Agri/Civil Engineer			
2.	Agriculture Scientist			
3.	Social Scientist			
4.	Veterinary Surgeon and if not available VA.			

Specialist of above discipline will be required to carry out assigned assignment.

In case of unavoidable circumstances, any specialist is required to be substituted, prior approval of CEO, Zila Parishad will be mandatory. PIA will have to submit request for each substitution indicating reasons and biodata of the proposed specialist 7 days in advance. After approval of CEO, ZP placement and functioning of the personnel will be assumed.

Agro Forestry plantation shall be planned in consultation with ACF Zila Parishad and if ACF is not available with DFO.

[B] Honararium and Conditions for WDT members

WDT members will get honorarium observing following conditions during the course of discharging their duties in implementing project :

(i) As there is a provision of Rs. 2.70 lac for office Contingencies for WDT constituted for 10 watershed projects for project period of five years, an office of WDT need be maintained where they should keep necessary records, maps etc.

(ii) Office of WDT should be located in one of the sanctioned projects area or centrally located Gram Panchayat for which concerned Gram Panchayat will allot room either free of cost or on nominal rent to be paid from out of the project funds.

(iii) A Small board shall be put informing that there is a WDT Office.

(iv) A Movement register will have to be maintained in each WDT office for all members.

(v) Every member will make entry of his movement in Movement register, which will be kept in the office.

(vi) Members of WDT will carry out visits jointly for items specified in Annexure 'A' and individually for items as specified in Annexure 'B'.

(vii) Tour of 20 days will have to be carried out in sanctioned project areas by every member in each month. Monthly report shall be submitted to PIAs by 1st of every month.

(viii) Honorarium and TA/DA to the WDT members shall be paid as under :

(a) Honorarium :

- WDT-Engineering — Rs. 3500/- per Month
- WDT-Agriculture, Veterinary Science and Social Science — Rs. 3000/- per Month

(b) TA/DA to all WDT members — Rs. 1000/- per month per member.

(ix) Monthly payment of honorarium & TA & DA to WDT members will be made by PIA after receipt of MPR latest by 10th of every month.

(x) Common lands, Revenue wastelands and Panchayat Charagah need be treated on priority with an aim to produce maximum grass, fodder, fuel & small timber to benefit the poor.

(xi) All WDT members will prepare & develop an action plan monthly/yearly to take up timely activities which lead to increase in production and benefit the people, specially poor, widows, SC, ST small & marginal farmers and the landless.

JOINT RESPONSIBILITY OF WDT MEMBERS

The WDT shall be jointly and severally responsible to carry out the following tasks :

S. No.	Objective	ACTIVITY	Time frame for Completion	Performance Indicators
1	Notification of WDT Office	1. WDT members report to Panchayat. 2. Board showing WDT office (Panchayat office or any other building made available by Panchayat). 3. Details of WDT, proposed watershed activities and map by painting on wall (through Gram Sewak). 4. Required stationary, movement register, publicity material (of all related department also) and project material be kept in the office (By Gram Sewak).	15 Days 15 Days 15 Days Continuous	1. All the WDTs have established their offices. 2. Material of other line department is collected. 3. Movement register is properly maintained by the WDT. 4. All records at the WDT level are properly maintained.
2.	Initial orientation about watershed activities in Gram Sabha	To orient & educate the entire watershed community about the watershed concept.	15 Days	% families oriented.
3.	PRA activities	To carry out PRA to identify felt needs & problems, their prioritization and to arrive at consensus solutions (including Base Line Survey of Land, Water, Agriculture, Livestock, Socio-Economic etc.)	45 Days	Existing status before commencement of project : 1. Land resources. 2. Water resources. 3. Agriculture resources. 4. Livestock resources. 5. Socio-Economic status. 6. Prioritization of feft needs including andless laboures and landless families (for common lands, if they are not included, the post completion sustainablity shall remain precarious.
4	User Groups formation	1. Formation, orientation and functionalisation of UG's. 2. Develop a consensus among the user groups on use of surface and ground water resources by each member, use of resources in common lands, user charges so that the assets are maintained and equitably used.	During PRA	100% land owning families organised in UGs.
5.	LRDP Preparation based on land capability and	Preparation and finalization of Land Resource Development Plan based on soil health and water availability. It may be advisable to have soil	During PRA	Plan is prepared as per demand and need of the area taking into consideration the suggestive plan for treatment/development of LRDP.

	classification	tested in the lab so as to plan proper cropping pattern. The Plan may include apart from crop production : 1. Agro-Forestry 2. Agro-Horticulture 3. Silvi Pasture 4. Horti-Pasture 5. Fisheries Development 6. Index Catchment 7. Forest Gap Plantation 8. New Forest area in Wasteland 9. Forest Protection 10. Fodder and Fuel wood plantation 11. Sand dune stabilization.		
6	DPR preparation	Finalization and submission of DPR to PIA after approval of Gram Sabha based on production plans of Agriculture, Animal Husbandry Pasture Development, Afforestation.	Within 6 months of the project allotment to PIA	1. Plans suggested by the community have been incorporated in the DPR. 2. People's plan is prepared alongwith the implementation schedule for each activity and the estimated expenditure and physical targets.
7	Technical support	Technical guidance to Gram Panchayat for execution of approved work plan and ensure quality of activities and time lines for implementation.	Continuous	100% bottlenecks coming in the implementation of watershed are removed.
8	Social Audit	Participate in Gram Sabha Meetings and ensuring social audit of watershed programme.	(Twice a year) Continuous	1. Social audits are being carried out in the GS meetings. 2. Complete transparency is observed.
9.	Submission of UCS and claims	1. Ensure timely utilization, submission of UCs and claiming of funds. 2. Fortnightly review for backlog matters.	Within max. 6 months of receipt of last installment. Backlog cases to be handled on priority.	1. Submission of UCs, claims in stipulated time. 2. Timely implementation/completion of the project is done.
10.	Timely implementation of project	Carry out implementation of the activities of the DPR through Gram Panchayat qualitatively and within the stipulated time.	Continuous	100% activities as per schedule are carried out.
11.	MPR submission	Submit monthly progress of tasks performed (in consultation with the Secretary of Gram Panchayat) so that MPR could be submitted to PIA before 1st of every month.	Continuous (Before 1st of every month)	Regular submission of MPR as per schedule.
12.	Approval of Deviations in DPR	Revised DPR including deviation be got approved in Gram Sabha/ZP, if required.	Need based, but in the end of five year, if any	This will ensure authenticity and correctness of DPR and avoid future audit objections.

13.	Post Project Sustainability	t-come parameters and finalizing the end project report. Exit Protocol Activities. CA Audit. Post Project Evaluation. 5. Capacity building of Gram Sabha for management of Watershed Development Fund and the activities that would need to taken up through the fund.	Within 6 month of the closing date of project.	Outcome parameters are linked with base line data and production plans.
14.	Maintaining 'JALGRAHAN SAR'	Complete data about the watershed is to be recorded/maintained/updated enabling process monitoring and impact assessment.	During the entire project period.	1. Visitors comments. 2. Timely/proper entries in 'JALGRAHAN SAR'. 3. Proper colourful depiction of activities in the map (Design Plan).

LOG FRAME ANALYSIS (LFA) FOR WDT MEMBERS

1. SOCIAL SCIENTIST

S. No.	Objective	ACTIVITY	Time frame for Completion	Performance Indicators
	1.Community Mobilization	1.Organize Gram Sabha for the concept and management of watershed development projects.	15 Days	1. Gram Panchayat Members trained & sensitized about WS activities.
		2. Orientation of Gram Panchayat.		2. No. of person/members attending GS/GP meeting.
		3. Create awareness among the Community on :	1 month	3. % Members regularly participating in the Gram Sabha/GP meetings.
		(A) The Project & it's benefits.	Within 3 months & continued efforts during the project period.	4. No. of Social audits conducted during the project period (twice in every year).
		(B) Build capacity for Social Audit through training.		5. Massive Slogan writing.
		(C) Slogan writing on every site and prominent place.		6. Wall Paintings and Action Plan of WS on Panchayat building's wall or on Panchayat notice Board.
	2.Institutional arrangements	1. To assist in the constitution of User's Group for each watershed activity, train & build their capacity for execution of watershed activities and their subsequent upkeep & maintenance.	Within 3 months	1. 10 SHGs per WS are constituted in 100% WS giving preference to the revival of existing SHGs.
		2. Constitute SHG's, organize their training, grading them and linking them for bank credit.		2. Organize their training and grading.
		(A) Providing revolving fund to stabilized groups.	Within 3 months	3. Providing revolving fund to stabilize groups.
		(B) Ensure SHG meetings, thrift, credit and timely recovery of funds.		4. Providing bank credit to atleast 50% SHGs.
			Within 1 year	5. Atleast 50% of SHGs engaged in income generating activities.
			Within 1 year	6. Timely recovery of funds.
	3. Empowerment of weaker section of community	1. Ensure intended benefits like wage employment to SC/ST.	Continuous	7. No. of SHGs benefited through project activities like works, seed collection, nursery etc.
		2. Facilitate women's participation.		8. SHG meetings are regular.
		3. To provide benefits of schemes of SCD Corporation.		1. No. of BPL, SC & ST who got (A) Wage employment.

	4. Community Involvement 5. Record Keeping 6. Exposure Visit 7. Post Project SUSTAINABILITY	Ensure 10% community contribution for works on community lands. 1. Assist the GP/SHG to (A) Maintain proper minutes of meetings. (B) Accounts. 2. Help GP to submit timely UCs. 3. Help GP Secretary to submit monthly progress report to PIA i.e. PS. Organise exposure visits of members in consultation with the PIA & GP. 1. Ensure sustainability of the project after it is over.	Continuous Continuous Within first year of the project and continuously thereafter, once every year. Continuous	(B) Fodder, fuel and other usufructs from common lands of WS. 2. % women members in SHG's. 3. No. of families/individuals benefited under SCDC schemes. 10% community contribution is deposited in the WDF Accounts regularly. 1. Record keeping is done properly. 2. Reports are sent on time. 3. Funds are received in time and properly utilized as per time frame laid down in the project guidelines. 4. Records & Accounts are properly maintained by the Gram Panchayat. Confidence and faith in the programme is developed in WS people. 1. Panchayat is able to take over, run the project.
	8. Submission of MPR	2. Convergence of schemes of other departments like W&C Dev., Insurance schemes, Social benefit/security schemes (Old age/Widow pension/handicapped) for benefit of watershed people. Submit timely progress report to PIA in consultation with member Secretary of the GP in the specified format.	Continuous First day of every month	2. People are benefited at large through insurance & Social benefit scheme. 3. All eligible are covered. Progress report is submitted every month timely.

2. AGRICULTURAL SCIENTIST

S. No.	Objective	ACTIVITY	Time frame for Completion	Performance Indicators
	1. Increase agriculture productivity and production on a sustainable basis	1. Assessment of crop wise and area wise actual and potential yield, identify reasons for difference in actual and potential yield.	2 months	1. Present status of production is available. 2. Village wise plan prepared.
		2. Village wise assessment of actual SRR (seed replacement rate) and gap from ideal SRR.		
		3. Assessment of village wise NPK consumption ratio and plan to maintain ideal NPK ratio by way of promotion of balance use of fertilizers.		
		4. Preparation of a crop specific production plan based on soil characteristic, agro-climatic conditions, water availability, need for change in agricultural practices, cropping pattern, horticulture, Agro-forestry for enhancing productivity etc. through PRA.	3 months	1. Production plan is prepared. 2. Farm plan prepared for all farmers. (Format of farm plan is enclosed).
		5. To record existing data of production and productivity (pre & post).		
		6. Preparation of area/crop specific plan to achieve desired SRR.		
		7. Farm Plan for each Farmer.	Continuous	
		8. Application of fertilizers on soil test basis; providing soil health card to every farmer before every crop season,soil health card	Continuous	
		should include recommended dose of fertilizers including micronutrients.	3 months	1. Bench mark survey done. 2. 100% farmers get soil health cards (In convergence with Agriculture Deptt.).
		9. Preparation of water budget based on the availability of ground water, recharging through WHS in WS	Continuous process twice	

		introduction of sprinkler/drip irrigation systems through PRA (This is to be part of the Production Plan).	a year	3. Optimum production is achieved.
		10. In consultation with KVK & Agriculture Extension Officer advise the farmers on suitable cropping pattern based on mix. Of :	within 1 month	Atleast 50% farmers adopt Micro Irrigation or Water Saving Devices.
		I. Horticulture II. Agro Forestry III. Herbal cultivation IV. Floriculture V. Organic Farming VI. Vermi composting VII. Efficient water use through Micro Irrigation System alongwith cost & benefit VIII. Tissue culture IX HYV seeds X. Improved agricultural practices XI. Shield yielding fodder XII. Fodder management XIII. Low water requiring crops XIV. Bio-Farming XV. INM and IPM practices XVI. Fisheries XVII. Use of various rain-fed farming conservation practices such as Broad bed and furrow cultivation across contour or slope etc.	Continuous Continuous Continuous Continuous Continuous	1. Atleast 50% farmer adopt non-conventional cropping pattern and improved agricultural practices. 2. 100% farmers use HYV. 3. Atleast 50% farmers produce vermi-compost and introduce organic farming. 4. Atleast 50% farmers adopt sprinkler/drip irrigation system. 5. 100% increase in income to the farmer through planting of fruit plants/vegetables/medicinal plants/forest plants. 6. Atleast 50% farmers adopt Horticulture & Agro forestry. 7. % families adopted low water requiring crops. 1. % of farmers linked with credit institutions. 2. 100% crop insurance cover is provided.
		11. Help farmers to arrange timely input such as good quality seed, fertilizers, bio fertilizers, gypsum etc. & credit to the community members from Co-operatives, Commercial Bank. Risk cover under NAIS and Weather insurance.		Disease free crop production. All farmers adopting new cropping patterns are tied up with marketing linkage.

		12. Advice the farmers on emerging disease patterns & treatment thereof. 13. Tie-up marketing arrangements for the farmers adopting non-conventional cropping patterns. [Contract farming etc.]. 14. Facilitate farmer's visit to KVK, Agro Universities in the State, Krishi Melas etc. to expose them to latest techniques. 15. Facilitate demonstrations of Agriculture Deptt. in WS area and regular visits of the Agriculture Extension worker to WS Areas.		Atleast two visits of farmers to KVK Agro Universities & Krishi Melas during the project period, pre harvest visits. 1. All eligible farmers get subsidies of Agriculture Department under various Schemes viz. Irrigation pipeline, Sprinklers, Drip Irrigation, Farm
	2. Identification of UGS	16. Help the farmers to avail subsidies under Agriculture and other schemes of the Government. 17. All farmers plant trees, Jatropha plantation, fodder trees on the boundaries of their fields. 18. On fallow and common lands Pasture Development and Afforestation will be carried out.	Continuous 2 months	production inputs, Agricultural machinery, Plant protection equipment, Seed production, Organic farming, Vermi culture etc. 2. All eligible farmers get subsidies of Horticulture Mission Schemes viz. Development of nurseries, Veg. Seed production, Seed infrastructure, establishment of new gardens, regeneration of senile plantation, creation of water resources, protected cultivation, promotion of IPM/INM, Organic Farming, Post Harvest Management, Processing and Value addition, Research and Development etc. 3. 20% growth in Agricultural production is achieved every year on a sustainable basis. 1. 75% trees planted are surviving. 2. Production of grasses, fodder trees, fuel wood trees is maximized in the pasture and common lands through improved practices and sustained maintenance.

		1. Users groups for nursery, plantation, crop production, horticulture, Agro forestry etc. 2. Training to these UGs.		1. 100% users group are mobilized and trained.
	3. Identification and treatment of common lands/wastelands 4. Nursery development 5. Timely operation for successful plantation of Agro forestry/Horticulture/Pasture Dev./Afforestation	3. Exposure visits. 4. Capacity building- Seed Production, Post Harvest Management, Agro Processing, Preservation, Organic Farming, Vermi-Compost Production, Mushroom Cultivation, Bee Keeping. 1. To know the status and demand of fuel wood, fodder and small timber. 2. Institutionalizing the community efforts for sustainable use of common lands. 3. Utilization of fallow lands for productive use. 4. Documentation of the yields. Encourage Kissan nursery development in the project area. To ensure timely operations for successful plantation activities. (a) Advance action (b) Soil work (c) Grass seeding (d) Planting (e) Weeding & hoeing (f) Use of insecticides & fertilizers (g) Replacement of casualties.	3 months Continuous First two years	2. Exposure visit arranged as per requirement. 1. Whether requirement of fodder, fuel-wood and small timber is met locally. 2. Regular assessment of surplus/deficit of fodder. 1. Seedlings are available in project area. 2. Self sufficiency about seedling is achieved. 1. More than 75% survival under plant category. 2. Pasture's carrying capacity is increased.

	6. To prepare management plan indicating the intermediate yields - usufructs sharing and final harvest	1. To draw mechanism for cost sharing. 2. To draw strategy for usufruct sharing giving priority to the weaker sections SC/ST/Women.	Continuous Continuous	Increase in Panchayat revenue by way of user charges/auction of grasses, seeds, fruits, pods, fodder, fuel wood etc.
	7. Output Monitoring	1. Laying out demonstration. 2. Crop cutting exercise. 3. Yield calculation. 4. Value addition. 5. Marketing support. 6. Documentation.	Continuous Continuous Every month	1. Increase in crop production. 2. Increase in productivity/yield. 3. Change in cropping pattern. 4. Increase in socioeconomic status. 5. Increased production of : (a) Grass seeds (b) Grass & Fodder (c) Fuel-wood (d) Small timber.
	8. Increasing women participation	Sanction of assistance only in the name of women farmer under individual beneficiary agricultural programme viz. Minikits/Water Saving Devices/Agricultural Implements/Plant Protection Equipments.		% of women benefited/empowered.
	9. Promoting use of alternate extension	Kisan Call Centre (No. 1551, online advice on Agriculture and Animal Husbandry matters). All India Radio and Doordarshan programmes on agriculture.		Popularization of new schemes in the area, percent of farmers benefited.
	10. Submission of MPR	Submit timely progress report to the PIA in the specified format.		Progress report is submitted every month.

3. VETERINARY EXPERT

S. No.	Objective	ACTIVITY	Time frame for Completion	Performance Indicators
	1. Preparation of Livestock Development Plan to make Animal Husbandry a sustainable source of livelihood & to ensure crop-livestock integration	1. Cattle census-Owner wise. 2. Knowledge about useful and unproductive livestock of the village. 3. Genetic improvement of cattle & small ruminates through AI. 4. Constitution of groups of livestock owners (Cows, Sheep, Goat, Camel Poultry and Buffalo) and their training for better upkeep and improved output. 5. Educate the Livestock owners on : I. Breed improvement. II. Castration of scrub bulls. III. Infertility treatment. IV. Nutrition. V. Disease prevention and immunization. VI. Management practices for productivity. VII. Bio gas. VIII. Organic manure, vermi-composting. IX. Economics of Animal Husbandry. X. Poultry farming.	20 days 20 days Continuous First year Alleast one a year Once a year	1. Atleast 75% Livestock owners adopt AI and 100% for Pedigree services. 2. % of Livestock owners having improved knowledge on these aspects and adopting scientific AH practices in WS area. 3. 100% convergence with ongoing Animal Husbandry Department activities namely Ajeevika Mission, Two days livestock owner training programme, Populty farming training, Enrichment of straw programme, Sheep development programme, Hybrid Ram distribution programme, Goat development programme.
	2. Tie-up AI Arrangements	To Tie-up for breed control, breed improvement and AI arrangements with a nearby AH Centre or a Gopal and facilitate timely service delivery.	Continuous	1. Successful AI's %. 2. No. of AI Calves.
	3. Immunization activity	1. Identification of common diseases in the area. 2. Organize timely immunization through Animal	Continuous	100% of cattle immunized.

		Husbandry Department.		
	4. Fodder availability	1. To ascertain nutritional requirement of cattle- to identify the gaps- plan to fill up the gap. 2. Facilitate development of pasture land and its scientific management through Panchayat (BAIF Model- enclosed).	Continuous	1. Development & use of pastures. 2. Increase in nutritional intake through eggs, fish, meat, milk etc.
	5. Marketing linkages	1. Establishment of dairy route (if not already existing) through District Milk Union. 2. For egg, meat and wool.	6 months	1. Increased production of milk, meat, wool, fish, chicken, eggs etc. 2. Linkage with dairy. 3. Atleast 20% increase in income to the livestock owners.
	6. AH Camps	1. Organize infertility treatment camps through Animal Husbandry Department. 2. Department provide treatment services during visit of WS.	Regular	No. of cattle treated.
		Regular submission of MPR to PIA on monthly basis.	Regular	
	7. Submission of MRPs	Tie up with Animal Husbandry Department for ongoing cattle Insurance Schemes (Avika Kavach Yojana, Avikapal Jeevan Rakshak Yojana, Avirakshak Yojana, Kamdenu Yojana, Gopalak Beema Yojana & Gorakshak Yojana).	Continuous	
	8. Livestock owner & Cattle Insurance		Once a year	100% coverage of eligible livestock owners and cattle insured.

Salient Features of BAIF's Cattle Development Programme

- Use of state-of-the-art technology with high quality frozen semen of proven bulls, to breed non-descript, low productive cows, which are under neglect.
- Artificial Insemination (AI) services at the doorsteps of farmers. Instead of farmers bringing their animals to the AI Centre, the technician visits the farm. This results in better understanding of the farm situations.
- Close follow-up and monitoring, which results in better performance and helps in building confidence of the farmers.
- Conservation of native breeds and coverage of buffalo and goat breeding services as well.
- Integration of breeding services with extension, training, fodder resource development, health control and blend of research suitable to local conditions.
- Provision of support services like disease investigation, vaccination and nutritional advice.
- Training of local youth to take over the operational responsibilities after the withdrawal of BAIF.
- Targeting of the underprivileged and sensitivity to social and gender issues.
- Development of local organizations to manage the programme without external dependence.

4. AGRICULTURE/CIVIL ENGINEER

S.No.	Objective	Activity	Time frame for completion	Performance Indicators
	1. Status of watershed	1. Demarcation of watershed boundaries in the field. 2. Preliminary surveys (collection of revenue data, reconnaissance survey, Bench Mark Survey, DLT survey as required). 3. Water budgeting.	1 month	Present status of land & water resources are available prior to start of project.
	2. DPR preparation	1. Estimation, designing & preparation of annual action plan in consultation with GP members. 2. Prepare DPR with assistance of other WDT members through PRA and submit it to PIA i.e. PS through the GP.	Within 6 months of the sanction of the project.	DPR is ready within the stipulated time.
	3. Harvest and reclaim every drop of rain water in the WS area, ensure its efficient use for sustained livelihood of people	1. Based on the terrain, plan and construct WHS, Water recharging structures, in-situ moisture conservation measure, so that almost entire water in the watershed area is harvested, conserved, recharged and reclaimed. 2. Small, Low cost, traditional know-how, earthen local material with emphasis on vegetative cover.	Within 2 years of the sanction of the project.	1. % of rainwater harvested and reclaimed. 2. Retention of water in tanks is increased. 3. Increase in area under cultivation. 4. Rise in water level in identified wells. 5. Recharging of water is increased. 6. Reduction in runoff %.
	4. Train and orient users groups for effective and efficient use of	1. Educate the farmers on : a. Water budgeting. b. Efficient water use technologies like drip irrigation & sprinkler systems and their economics. c. Pitfalls and adverse effects of flood irrigation on soil and crops. 2. Create a consensus among members of GP not to use water directly from WHS for irrigation and use this water for recharge with assistance of Social Scientist.	2 months of sanction of the project. 1st year & continuously	1. Atleast 50% of farmers aware of water budgeting. 2. Atleast 50% farmers adopting MIS's. 1. Deposits in WDF (% of land owning families contributing in WDF). 2. Beneficiary share not deducted from wages of labour.

	water	Capacity building of Panchayat and community for maintenance & upkeep sustenance of structures.	thereafter.	3. People own the responsibility of maintenance & upkeep of community assets. 1. Timely payments within 15 days after completion of work will be ensured. 2. Quality of works is improved.
	5. Capacity building for maintenance	To assist maintaining MB for the Civil works, recording measurements and 100% verification of work, muster rolls for payment as per quantity of work done, materials procured and used etc. Have the social audit of civil works done in the Gram Shabha.	Continuous Twice in a year	1. No. of social audits held. 2. Objections received/settled. 3. Transparency will be observed by displaying boards/wall paintings. Improved quality of works. Progress report is submitted every month.
	6. To assist GP Secre-tary in recording measuren-ments in MBs., preparation of bills and payments to labourers 7. Social audit of works carried out 8. Quality Control 9. Submission of MPR	To ensure quality of works as per specification of DPR by 100% verification. Submit timely progress report to the PIA in the specified format.	Continuous 1st day of every month	

HOW TO DO WATER BUDGETING

BASIC DATA TO BE COLLECTED :-

(A) Area (Calculated from revenue record).

1. Good catchment-where runoff is maximum & infiltration is minimum like hillocks, plateau etc.
2. Average catchment-cultivated land, forest land with vegetation.
3. Bad catchment-where runoff is minimum & infiltration is maximum e.g. Sandy soil.

(B) AVERAGE ANNUAL RAINFALL DATA (AVAILABLE AT TEHSIL)

* Proportion of Estimated Runoff of rainfall : To be worked out from Strange's Table.

For example; for 500 mm total monsoon rainfall.

(a) Percentage of run-off to rainfall from Strange's table.

In good catchment- 15%

In average catchment- 11.25%

In bad catchment- 7.5%

Type of W/s	Area of W/s	Factor	Expected Yield Cum
Good	X	750 Cum/Ha	Xx 750 =
Average	Y	563 Cum/Ha	Yx 563 =
Bad	Z	375 Cum/Ha	Zx 375 =
Total	**X+Y+Z**		**''A''**

*** PRESENT STORAGE BY EXISTING RUN-OFF MANAGEMENT STRUCTURE :**

S.No.	Name of structure	No/Area	Storage Capacity (Cum)
1.	Tank/Talab/Nadi		
2.	Anicut/WHS/Khadin		
3.	Local Depression Pond etc		
	Total		**''B''**

* Balance run-off= Expected yield -Percentage storage= ''A''-''B''= ''C''.

* 75% of balance run-off may be stored by constructing new structures= ''C'' x 0.75= 0.75C.

*** PROPOSED NEW STRUCTURES :**

S.No.	Name of structure	No/Area	Storage Capacity (Cum)
1.	Gabion structure		
2.	Dug out pond		
3.	Nadi/Talab		
4.	Minor masonry structure		

''D'' to be less than "0.75C''

फार्म प्लान बनाते समय सम्मिलित करने योग्य बिन्दु

- कृषक के पास उपलब्ध संसाधनों के आधार पर ऐसी योजना तैयार करना जिससे-
- कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो।
- आय में वृद्धि हो।
- उत्पादन, आय तथा रोजगार में स्थिरता (Sustainability) जिससे कृषक सूखे/अन्य विपरीत मौसम परिस्थितियों में Survive कर सके।
- कृषक के पास उपलब्ध भूमि के प्रकार, क्षमता, जल संसाधन आदि को देखते हुए फसलों/किस्मों का चयन जिसमें : अनाज, दलहन तिलहन वाणिज्यिक फसलों के साथ-साथ स्वयं की आवश्यकतानुसार चारा, सब्जी आदि का भी समावेश हो।
- Waste land पर औषधीय/जैट्रोफामसाला फसल/फोरेस्ट प्लान्ट
- Boundry Plantation Trees/Shrubs जिससे Fodder, Fuel, Timber ..... ?
- Arid Horticulture (अतिरिक्त आय+स्वयम् की मांग की पूर्ति)।
- अंतराशस्य (Intercrops) (अतिरिक्त आय, खाली भूमि का उपयोग)।
- प्रत्येक कृषक के यहाँ वर्षा जल संग्रहण हेतु फार्म पौण्ड/डिग्गी/खेत तलाई
- माइक्रो इरीगेशन हेतु फव्वारा/ड्रिप/पाइप लाइन तथा जल संपक्षी कृषि-क्रियाएं
- वैज्ञानिक विधि से कार्बनिक खाद निर्माण-वर्मी/सुपर कम्पोस्ट/FYM
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर INM-Plan एवं फसलवार IPM Plan का चयन
- कृषक के पास उपलब्ध संसाधनों/क्षैत्रीय मांग/बाजार/खपत की संभावना को देखकर कम से कम एक सहायक गतिविधि फार्म-प्लान में सम्मिलित की जावे जैसे-नर्सरी, Floriculture मशरूम उत्पादन, पशुपालन/भेड़-बकरी/मुर्गीपालन/वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन अथवा अन्य जिससे फसलों के उप-उत्पादों (By products) का समुचित उपयोग होकर उत्पादकता व आय में वृद्धि हो।
- प्रत्येक प्लॉट के लिये फसल मौसम वार, गतिविधि वार योजना बनाई जावे। प्रत्येक वर्ष खरीफ/रबी/जायद हेतु प्लॉट वाइज अच्छी वर्षा, मध्यम वर्षा तथा कम वर्षा तीनों स्थितियों का खाका (Digram) तैयार किया जावे।
- प्रत्येक गतिविधि से सम्बन्धित आदान, प्रकार, मात्रा, प्राप्ति-स्रोत, उपयोग का समय तथा व्यय राशि का विवरण।
- विपणन के लिये-स्थानीय/निकटतम कृषि उपज मण्डी/वायदा बाजार/ई-चौपाल/प्रसंस्करण इकाई/भण्डारगृह में से लाभप्रद विकल्प का चयन।
- प्रत्येक गतिविधि से मुख्य उत्पाद तथा उप-उत्पाद की मात्रा व व्रिकय मूल्य का विवरण रखें।
- कृषक की कम से कम पांच वर्ष की योजना तैयार की जावे, लाभप्रदता के आकलन व गत वर्षों से तुलना उपरान्त प्रतिवर्ष मध्यावधि/सामयिक संशोधन किये जावें।

कृषकवार फार्म प्लान तैयार करने हेतु नमूना प्रारूप (यह प्रारूप indicative है, स्थिति व संसाधन के अनुसार परिवर्तन योग्य)

कृषक का पूर्ण विवरण- भूमि, संसाधन, अन्य जमीन का प्लाटवार खाका- खरीब/रबी/जायद/वर्ष

नाम फसल (गतिविधि) (Crop/Var.)	**क्षेत्रफल**	**प्लाट संख्या**	**बीज (Planting Material)**				**बीज/पौध उपचार**			**उर्वरक उपयोग मृदा परीक्षण के आधार पर**					
Cereals/Pulses/Oilseeds/Other/Fodder/Boundary Plantation/Fruit-Plants/Other Economic Activity i.e. Nursery, Goat sheep, Poultry, A/H, Seed Production, Vermi Floriculture, other .			किस्म	मात्रा	स्रोत	व्यय राशि	प्रयुक्त आदान	मात्रा	व्यय राशि	***उर्वरक***		सूक्ष्म तत्व	प्रयोग मात्रा	समय	व्यय राशि
										कार्ब.	अका.				

सिंचाई			**समन्वित कीट प्रबंधन**							**खरपतवार नियंत्रण/अन्य कृषि क्रियाएं**			
प्रथम	***द्वितीय***	व्यय राशि	प्रकार	स्रोत	प्रयोग समय	रसायन	मात्रा	समय	व्यय राशि	विवरण	समय	स्रोत	व्यय राशि

Harvesting व उत्पादन				**विपणन/भण्डारण/प्रसंस्करण/अन्य**												
कटाई का समय	मुख्य उत्पाद	उप उत्पाद	अन्य उत्पाद	***क्षेत्रीय बाजार***		***कृ.उ.मं.***		***वायदा बाजार***		***ई-चौपाल***		***प्रसंस्करण अन्य***		**कुल व्यय राशि**	**कुल प्राप्त राशि (Return)**	**विशेष विवरण**
				मात्रा	प्राप्त राशि	मात्रा	प्राप्त राशि	मात्रा	प्राप्त राशि	मात्रा	प्राप्त राशि	मात्रा	प्राप्त राशि			

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
RURAL DEVELOPMENT & PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

(Land Resources Section)

Room No. 153, Krishi Pant Bhawan

No. F 6 (12) RD/LR/2/96 Pt. III Jaipur, Dated : 4 Oct, 2006

Chief Executive Officer, Zila Parishad,
(All Rajasthan (except Sriganganagar).

Sub. : Criteria for Selection of Watershed Projects.

Watershed projects under DDP, DPAP and IWDP are being implemented in the district under Hariyali guidelines. Criteria for selection of Watersheds, though has been clearly mentioned in para 5 of Hariyali, however, districts interpret in its own way. Thus, uniformity in selection of watersheds is not observed.

In view of selection criteria mentioned in para 5 of Hariyali, ranking has been fixed attaching highest priority to those areas where there is acute shortage of drinking water, on the scale of one to ten as follows, superseding all previous circulars/directions issued for selection of watersheds-

S.No.	Criteria	Points to be awarded
(i)	Watershed area having acute shortage of drinking water	5
(ii)	Watershed having large population of SC/ST dependent on it.	1.5
(iii)	Watershed where people's participation is assured through contribution of labour, cash, material etc for its development as well as for the operation and maintenance of the assets created	1
(iv)	Watershed having preponderance of common land	1
(v)	Watershed where actual wages are significantly lower than the minimum wages.	0.5
(vi)	Watershed having preponderance of non forest wasteland/degraded land	0.5
(vii)	Watershed, which is contiguous to another watershed that has already been developed/treated.	0.5
	Total	**10**

Please ensure that selection of watershed is made as per criteria explained above. Copy of this letter should be made available to BDO's also.

Sd/-
Commissioner

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

RURAL DEVELOPMENT & PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

(Land Resources Section)

Room No. 153, Krishi Pant Bhawan

No. F. 2 (104) RD/LR/2/2006 Jaipur, Dated : 05.10.2006

CIRCULAR

Officers of Wasteland, Watershed Development & Soil Conservation Department have been visiting Panchayat Samities for review and inspection of watershed projects from time to time. Visiting Officers are supposed to contact BDO of the concerned Panchayat Samiti while visiting watershed projects and also invite him in the review meeting for proper coordination and facilitation.

All the visiting officers are directed to contact the BDO and invite him in the meeting whenever they visit Panchayat Samiti area or review its progress and a note to this effect should be made in their tour diary also. **Compliance at each level should be ensured.**

Sd/-

Commissioner

Copy to :-

1. S.A. to Hon'ble Minister, RD & PR.
2. PS to Pr. Secretary, RD & PR.
3. Additional Director, WWDSC.
4. CEO, Zila Parishad, ... with the remark to make available the copy of circular to BDO's.
5. Joint Director, WDSC, Jaipur, Ajmer, Bhilwara, Jodhpur, Kota and Udaipur.
6. Officer Incharge of districts.

Sd/-

Commissioner

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(भू-संसाधन प्रकोष्ठ)

कमरा नं. 153, कृषि पंत भवन

प. 8 (107) ग्रावि/भू.सं./2/2006 जयपुर, दिनांक : 11.10.2006

परिपत्र

जलग्रहण विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सभी जिलों में जलग्रहण विकास दलों का गठन किया जा कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है। जलग्रहण विकास दल के सदस्यों को क्रियाशील बनाने हेतु विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। जलग्रहण विकास दलों हेतु दायित्वों का निर्धारण करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश परिपत्र दिनांक 4.9.06 द्वारा जारी किये जा चुके है।

वर्तमान परिपेक्ष्य में जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग के परियोजना अधिकारी (भू-संसाधन)/सहायक परियोजना अधिकारी (भू संसाधन), सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ताओं के कर्तव्य एवं दायित्वों का पुनः निर्धारित किया गया है, जिनका विवरण परिशिष्ट 1, 2 व 3 पर संलग्न है।

कृपया निर्धारित दायित्व का विवरण परियोजना अधिकारी (भू-संसाधन)/सहायक परियोजना अधिकारी (भू संसाधन), सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ताओं को उपलब्ध करावें तथा सुनिश्चित करे कि सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा इनका पालन किया जा रहा है।

ह./-

आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान (गंगानगर को छोड़कर)।

ह./-

आयुक्त

LOG FRAME ANALYSIS (LFA)

RESPONSIBILITIES OF PROJECT OFFICER (LR)/ASSISTANT PROJECT OFFICER (LR)

S.No.	Objective	ACTIVITY	Time frame	Performance Indicators
	1.Preparation of shelf of projects	1. Identification of completed, ongoing and balance number of projects in each Gram Panchayat. 2. Recommendation/Approval of Gram Sabha for including projects in shelf of Projects. 3. Prioritization of projects and approval of shelf of projects by Zila Parishad. 4. Allotment of Project to Project Implementation Agency (PIA).	End of April every year End of May every year End of June every year.	1. No overlapping of area in selected untreated projects. 2. Approval by Gram Sabha in Scheduled time frame. 3. Hariyali para 5 is strictly adhered to for prioritization of projects. 4. Approved by Zila Parishad in stipulated time in accordance to priority fixed in shelf of projects. 5. PIA received allotment in prescribed time limit.
	2.Entry Protocol	1. Funds are released to PIA 2. Opening and operation of project account. 3. Opening of WDF account. (a) Minimum 5 to 10% contribution to be sought from users for any W/S activity.	Within one month from the date of sanction of GOI 15 days of receipt from GOI 15 days of transfer of funds to PIA One month of transfer of funds to PIA.	1. Project account is opened in Bank. 2. Funds received have been deposited in Bank account. 3. Account operated jointly by Sarpanch and Gram Sewak. (Panchayat Secretary). 4. WDF account is opened separately. 5. Amount of beneficiaries share has been collected.
	3. Placement of Watershed Development Team (WDT)	(b) Donors may be motivated to contribute in WDF. (c) Imposition & Collection of user charges by GP and depositing 50%	One month from the allotment of project to the PIA. Within one month of	1. DPR's submitted are strictly in accordance of GOI guidelines and has approved production plans and annual action plans (100%) checking by the

	4. Preparation of DPR	1. Ensure proper identification of 4 member of WDT by PIA. 2. Training to WDT members. (i) PRA (ii) Production Plan : (a) Agri. production plan (b) Animal Husbandry (c) Pasture & Afforestation (d) Horticulture Production Plan (e) Livelihood Production Plan. (iii) Preparation of DPR. 1. Checking of DPRs. 2. Submission of DPRs with yearwise phasing of activities in view of quantum of funds earmarked in the guidelines.	selection One month from the training of WDT. Within 3 months of the PRA after seeking conve-rgence from the line departments. Within one month of the production plan. 15 days In the first meeting of Zila Parishad convened after receipt of DPR.	PO (LR). 2. Permissibly activities as per guidelines
	6. Training Calendar for different stakeholders of watershed projects and its out-sourcing.	1. Exposure visits to successful watershed projects. 2. Training to SHG's, UG's, Sarpanch, Gram Sewak and Community. 3. Ownership feeling generated in Community.	30th of April every year.	have been included in DPRs. 3. Yearwise funds for each activity are proposed in DPR's to the extent permitted in the guidelines. 4. Different production plans for development of Agriculture. Horticulture, Animal Husbandry, Pasture & Afforestation have been given due weightage. 5. Works of different activities in approved DPR are completed with the earmarked

				funds without any diversion. 6. DPR's approved by Zila Parishad in its first meeting held after receipt of DPR's. 1. PIA has made provision for exposure visit in training calender. 2. PIA completed exposure visits in stipulated time. 3. Training have been organised for SHGs, UG's Sarpanch, Gram Sewak and Watershed Secretary by PIA as per programme indicated in Training Calender in schedule time frame. 4. 50% of Community members attached to watershed have feelings to own the project for post project management.
	7.Commencement of works 8.Review of project activities	1. Works start in time. 1. Project planning and funds utilisation. 2. Training and community Mobilisation. 3. Review and Planning meeting. 4. Development of Warning Signals. 5. Project Management : (i) Each project claims min. one instalment in a year. (ii) Within a fortnight of 50% utilisation of the previous instalment, proposals for the new installments are sent to GOR. (iii) Monthly pursuance with GOI/GOR.	Within 15 days from the date of approval of DPR. Continuous.	1. Works of the sanctioned project started as per approved DPR. 2. Timely release of funds to GP by ZP. 1. Activities as per approved DPR executed 2. No change/deviation in approved DPR. 3. Monthly action plan prepared. 4. Review and Planning Meeting were carried out every month with : (i) PRIs/PIAs/WDTs to effectively moniter implementation of projects. (ii) With line departments for convergence. (Agri, AH, Forest, ICDs, horticulture). (iii) WDT at the block hq. (on watershed basis). 5. Identified delay in :

		(iv) Number of projects where last instalment received is more than 3 months old and ascetaining the reasons thereof.		* Preparation of DPR * Backlog of installment * Submission of proposals of installment * Audit of project accounts. * Observing exit protocol. 6. Cohesiveness developed among Stakeholders. 7. Physical Financial Progress. Target Achieved : 40% in first Quarter 40% in Second Quarter
		(v) Mid Term Evaluation with 45% release of funds to ZP. (a) Formal contact with evaluator. (b) Submission of necessary details to Evaluator. (c) ATR on the report of evaluator. (d) Payment to the evaluator. 6. SHG/Livelihood activities	15 days of appointment 15 days of appointment. Within one month of report. Within a week of the receipt of the report.	10% in Third Quarter 10% in Fourth Quarter. 8. Claiming of 2nd instalment within 9 months of the release of 1st instalment. 9. Converged other related schemes in watershed projects. 10. Componentwise utilisation of funds observed. 11. Installments of projects received in time. 12. Audit of project accounts by auditors in schedule time. 13. Bottlenecks of Weakest project identified for improving quality and pace of watershed projects. 14. Mid Term Evaluation (MTE) and Action Taken Report submitted in stipulated time to get next instalment. Payment to Evaluator made in time. 15. Claims for 4th instalment be put up to GOI within 2 months of the receipt of

				Evaluation report.
	9. Progress reporting 10. Coordination with WDT members 11. Evaluation of Projects 12. Exit Protocol	1. Preparation and submission of MPR. 2. Analysis of submission of proposal for next instalment. 3. Shortcomings pointed out in proposals. 4. Success Stories. 5. Vigilance/enquiry report. 1. Identify problems faced by WDT members in implementation. 2. Availability of required information needed by WDT for project area. 1. Final evaluation of completed projects. 1. Handing over of assets generated in project to Gram Panchayats through UG's/SHG's.	Every month One per block per year Continuous Within 6 months after completion of projects Within six months from the closure of project	1. Progress received from PIA in schedule time frame. 2. Submitted Physical and Financial Progress to Head Office on 10th of every month. 3. Analysed eligibility for submitting proposal of next instalment every fortnight. 4. Submitted clarification on obser-vations made by GOI within 10 days from the receipt of letter. Ensure submission by 31 May every year No enquiry report is pending for more than 30 days. 1. Remedial measures provided to remove bottlenecks faced by WDT members. 2. Data/Informations necessary for project arranged in time for smooth implementation. 1. Project accounts were audited after getting projects evaluated finally. 2. Final UCs, Final CA Audit Reports and Final evaluation reports submitted to HQ. 1. Assets created, handed over to Gram Panchayat in prescribed time limit. 2. Funds of WDF transferred to GP in schedule time frame.
	13. Support &	2. Transfer of WDF to Gram Panchayats.	Monthly reporting	3. Gram Panchayat uses WDF only on

	Supervision of WDTs. 14. Social Audit 15. Field visits & Inspections	3. Utilisation of WDF. 1. Regular monthly interaction with WDT at Block Hq. and redresal of grievances. 2. Ensuring smooth functioning between PIA and WDT. 3. Capacity building of WDF. 1. Display Boards. 2. Wall Paintings. 3. Interaction in Gram Sabha. 1. Scheduled visits of Watershed. 2. Days travel. 3. Night halts.	after completion of the project. Minimum 5 Blocks in a month Every month Every Quarter Within 1st Quarter of the sanction of watershed project Every Quarter 5 Watershed every month 10 days in a month 3 nights in a month	Common Property Resources for their maintenance/development. 4. GP awared of the fact the that WDF can not be used for maintaining individuals assets. Interaction done for improvement of the pace and quality of work and removal of bottlenecks. Monthly Reports by WDT to PIAs are sent. Regular Payment of honorarium to WDT by PIA by 10th of very month. In the form of exposure visits, training and regular visits. At least 3 display boards were placed for each watershed at common places. At least 10 wall paintings for each watershed are in place. Participated in every Gram Sabha meetings Report of Visits undertaken sent to Head office. Carried out travel for prescribed days. Nights halts observed as prescribed. Carried out inspection of watershed projects regularly as per norms prescribed by the department.

Annexure- 2

JOB RESPONSIBILITY OF AEn. (PS)

S.No.	Objective	ACTIVITY	Time frame for completion	Performance Indicators
	1.Preparatory Activities for the Projects	1. Preparing shelf of project (150% of the No. of Projects in the previous year).	31st March of every year	The Projects are ready in time.
		2. Prioritisation as per para 5 of Hariyali guidelines and submission to Zila Parishad.	10th April of every year	Ensure Submission to ZP for approval strictly as per guidelines.
		3. Constitution of WDT.	Within first month of the sanction of the project	WDT are identified, trained and deployed in all the watersheds & MOU is signed.
		4. Conducting PRA and bench mark surveys.	Within one month of sanction of project	In all the watershed PRA is done.
		5. Preparation of detailed Production plan as per land capability:		
		- Agriculture Production Plan	31st May of every year	Production Plan is ready.
		- Animal Husbandry Plan	31st May of every year	-Do-
		- Horticulture Production Plan	31st May of every year	-Do-
		- Pasture Development Plan	31st May of every year	-Do-
		6. To prepare Community Organisation Calendar for the year to organise people in UG's & SHG's.	15th April of every year	The Calendar is ready.
		7. To prepare Training calendar for the year and its out-sourcing	31st March of every year	Training Calendar ready. Out-sourcing proposals are submitted to ZP.
		8. Preparation of DPR incorporating production, community mobilisation and training plans and annual action plan and its submission to ZP	31st August of every year	DPRs approved.
		9. Advance action for Production System	Quarterly	UG's & SHG's are constituted.
				Advance action as per production plan is done before onset of monsoon.
	2.Training andCommunity Mobilisation	(i) Improved Agriculture (ii) Planting of fruit plants (iii) Agro-Forestry (iv) Pasture Development	preferably before monsoon	

	3.Execution of Production Plan 4.Financial Monitoring of the Project	(v) Afforestation Summer Ploughing, arrangement of improved seeds, planting material, manure, fertilizer, establishment of nurseries, Fencing, V-ditches, Contour trenching, Pits, Water Harvesting, Grass Seeding, Seed sowing for live fence for strengthening of bunds and embankments. 10. Advance action for support to SHGs. Training of WDT, SHG, UG, Watershed Community, exposure visit, Jan Chetana rally, awareness camps, night gosties, slogan writing etc. Planting activity, Replacement of casualities, weeding and hoeing, Application of fertilizer and insecticides, watch and ward etc. 1. Keeping a regular monthly check on the expenditure pattern. 2. Componentwise gainful utilization of resources	Quarterly Ist capacity building of WDT within 20 days of its identification. Fur-ther steps as per training and Comm-unity Mobilisation plan During Monsoon The Project is able to claim at least 2 install-ments in a year Every month	Required No. of SHGs constituted. Revolving fund given to SHGs. Credit linkages established with Banks. Marketing support established. The plan is strictly adhered to. Production plan are executed. 1st Proposal to ZP should be sent before 30th June every year to avoid CA Audit requirement and 2nd proposal to be sent before 30th September. Component-wise progress as per the guidelines
	5. Review and planing of the Project Activities	3. Pursuance with ZP for pending claims. 4. Timely reply of GOI/GOR queries. 1. RPM with JENS/WDTs and other staff 2. Convergence meetings with Agriculture, Horticulture, Forest, Animal Husbandry and WCD Depts. at the Block level.	Every fortnight As and when required Every month Every month	No Claims are pending with ZP for more than 3 days. Reply sent. Regular meetings done. Regular meetings done.

	6.Reporting	1. To the ZP. 2. Success Stories. 3. Submission of UCs after his counter signature. 4. Vigilance/inquiry reports	Every month, by 5th Quarterly As per Scheme requirements	Reports sent. At least 2 Success Story every Block in a year. Sent to ZP.
	7.Travel & Field Visit to improve quality and pace of projects	1. Scheduled visits of Watershed 2. Unscheduled visits 3. Days travel 4. Nights halts	Monthly 10 Watersheds every Month 5 Watersheds every Month 15 days in a month 8 days in a month	No report is pending for more than 20 days. Visits done and Report sent to ZP in the Prescribed format. Visits done and Report sent to ZP . Travel made and reported. Halts made and reported .
	8.Support & Supervision of WDTs	1. Regular weekly interaction with WDT. 2. Ensuring smooth functioning between PIA and WDT. 3. Approval of Tour Programme/Diary of WDT. 4. Timely payment of WDTs.	Minimum 50% W/Ss in a month Every week Every month Every month	Technical support provided. Monthly Reports by WDT to PIAs are sent Regular feedback by PIA to WDT given Regular payment of honorarium to WDT
	9.Social Audit 10.Evaluation of the Projects 11.Exit Protocol	1. Display Boards. 2. Wall Paintings. 3. Interaction in Gram Sabha. 1. Regular Evaluation.	Within 1st Quarter of the sanction of Watershed Project Within 1St Quarter of the sanction of Watershed Project Every Quarter Every year	by PIA-by 10th of every month. At least 3 display boards are in place in each watershed. At least 10 Wall Paintings for each watershed in place and regular updating. Participation in Gram Sabha meetings. No Project is stand still. Each Project is getting installments in time. Physical Progress is keeping pace with the Financial Progress. To facilitate evaluator for carrying out timely evaluation and should accompany the evaluator during the field visit.

		2. Mid Term Evaluation. 3. End of the Project. 1. Closing the Project formalities and handing. 2. Use of WDF with the approval of Gram Sabha.	After the 2nd installment has been utilised Outcome Para-meters at the end of the Project. Within 6 months of the end of the Project As and when required after project period	Soft component of training & community mobilization move as desired. Mid Term Evaluation Report received and action taken report sent to ZP. Detailed report sent regarding-Increase in groundwater level, Agriculture Production, successful AI cases, development of Gochar/Common lands etc. MOU with GP signed. Use of money for the maintenance of assets created on community lands.

JOB RESPONSIBILITY OF JEn.

S.No.	Objective	ACTIVITY	Time frame for completion	Performance Indicators
	1.Preparatory Activities for the Project	1. To assist in the preparation of shelf of project (150% of the No. of Projects in the previous year).	31st March of every year	The Projects are ready.
		2. To assist in Prioritisation as per para of 5 of Hariyali guidelines and submission to Zila Parishad.	10th April of every year	Ensure submission to ZP for approval
		3. Conducting PRA and Bench Mark Surveys.	1. To participate in PRA in all the new watersheds. 2. Within one month of sanction of project	In all the watershed PRA is done.
			31st August of every year	
		4. To assist in Preparation of DPR (including community mobilisation, training and production plan) and its submission to ZP.	The Project is able to claim at least 2 install-ments in a year	1. All the DPRs are approved, UGs & SHG's constituted. 2. Execution is as per DPRS.
	2.Financial Monitoring of the Project	1. Assist in Keeping a regular monthly check on the expenditure pattern.	Regularly, every fortnight Every month	Ist Proposal to ZP should be sent before 30th June every year to avoid CA Audit requirement and second proposal by 30th Sept.
	3.Review and Planning of the Project Activities	1. RPM with WDTs.	Every month, by 3rd	Regular meetings done.
		2. To assist in Carrying out convergence with Agriculture, Horticulture, Forest, Animal Husbandry and WCD Deptt.	Quarterly	Regular meetings done.
	4.Reporting	1. To the AEN, PS with help of WDT.		Reports sent.
		2. Success Stories (including CDs, Write-up, Photographs).		At least 2 Success Story per month in his jurisdiction
	5.Travel & Field Visit to improve quality and pace of project.	3. Submission of UCs/CCS after verification.	As per scheme requirements	UCs after counter signature are sent to PS.
		4. Assist in Vigilance/inquiry reports.	As and when required	No report is pending for more than 15 days.

	6.Support & Supervision of WDTs 7.Social Audit	1. Scheduled visits of Watershed. 2. Unscheduled visits. 3. Days travel. 4. Night halts. 1. Regular interaction with WDT and technical support. 2. Assist in smooth functioning between PIA and WDT. 3. Capacity building of WDTs/UGs/SHGs/PRIs and Community. 1. Display Boards. 2. Wall Paintings.	Each allotted watershed atleast once in a month 7 watersheds every month 20 days in a month 15 days in a month All the allotted W/S Every week Within 20 days of its identification in all the watersheds (i) Exposure visit (ii) Training Within 1st Quarter of the sanction of Watershed Project Within 1st Quarter of the sanction of Watershed Project	Visits done and Report sent to PS. Visits done and Report sent to PS. Travel made and reported to PS. Halts made and reported to PS. Interaction done. Monthly Reports by WDT to PIAs are sent. Regular feedback by PIA to WDT given. WDTs/UGs/SHGs/PRIs are capable of handling watershed activities properly. Ensure atleast 3 display boards are in place in each watershed. Ensure atleast 10 Wall Paintings for each watershed in place and regular updating
	8.Evaluation of the Projects	3. Interaction in Gram Sabha. 1. Regular Evaluation.	Every Quarter As directed	Participation in Gram Sabha meetings, in all the watersheds Social Audit is done. No Project is stand Still. Dispute, if any, is resolved timely. Each Project is getting installments in time. Physical Progress is keeping pace with the Financial Progress.

	9.Exit Protocol	2. Mid Term Evaluation. 3. End of the Project. 1. Closing the Project formalities and handing over of assets/WDF to GP WA, with assistance of WDT. 2. Use of WDF.	As directed Outcome Parameters at the end of the Project Within 6 months of the end of the Project Quarterly	To facilitate evaluator. Soft component of training & community mobilisation move as desired. Mid Term Evaluation Report received and action taken report sent to PS after ensuring mid term correction suggested by evaluator. Detailed report sent regarding-Increase in groundwater level, Agriculture Production, successful AI cases, development of Gochar/common lands etc. MOU with GP signed. Regular use of money for the maintenance of assets created.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
RURAL DEVELOPMENT & PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

(Land Resources Section)

Room No. 153, Krishi Pant Bhawan

No. F 6 (12) RD/LR/2/96 Pt. III Jaipur, Dated : 4 Oct, 2006

Chief Executive Officer, Zila Parishad,
All Rajasthan (except Sriganganagar).

Subject : Criteria for Selection of Watershed Projects.

Watershed project under DDP, DPAP and IWDP are being implemented in the district under Hariyali guidelines. Criteria for selection of Watersheds, though has been clearly mentioned in para 5 of Hariyali, however districts interpret it in its own way. Thus, uniformity in selection of watersheds is not observed.

In view of selection criteria mentioned in para 5 of Hariyali, ranking has been fixed attaching highest priority to those areas where there is acute shortage of drinking water, on the scale of one to ten as follows, superseding all previous circulars/directions issued for selection of watersheds-

S.No.	Criteria	Points to be awarded
(i)	Watershed area having acute shortage of drinking water.	5
(ii)	Watershed having large population of SC/ST dependent on it.	1.5
(iii)	Watershed where people's participation is assured through contribution of labour, cash, material etc for its development as well as for the operation and maintenance of the assets created.	1
(iv)	Watershed having preponderance of common land.	1
(v)	Watershed where actual wages are significantly lower than the minimum wages.	0.5
(vi)	Watershed having preponderance of non forest wasteland/degraded land.	0.5
(vii)	Watershed which is contiguous to another watershed that has already been developed/treated.	0.5
	Total	**10**

Please ensure that selection of watershed is made as per criteria explained above. Copy of this letter should be made available to BDO's also.

Sd/-

Commissioner

जलग्रहण परियोजना प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव

ग्राम पंचायत ..... द्वारा मीटिंग दिनांक ..... में जलग्रहण परियोजना प्राप्त करने हेतु निम्न प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया हैः-

1. ग्राम पंचायत द्वारा जलग्रहण परियोजना लागू करने हेतु पंचायत के उत्तरदायित्व को भली भांति समझ लिया है व पंचायत इस योजना को लागू करेगी।

2. ग्राम पंचायत की ..... बीघा चारागाह भूमि का विकास भी इस योजना में किया जावेगा। इस चारागाह के ..... क्षेत्रफल में खुली चराई बन्द रहेगी व पंचायत द्वारा निर्धारित फीस देने पर घास की कटाई की अनुमति होगी। बी.पी.एल. परिवारों से फीस वसूल नहीं की जावेगी।

3. चारागाह क्षेत्र व राजकीय भूमि पर इस योजना के रखरखाव का उत्तरदायित्व पंचायत का होगा। यदि पंचायत उसमें असफल रहती है तो सरकार द्वारा इस हेतु किया गया व्यय वापस राजकोष में जमा कराने हेतु उत्तरदायी होगी।

4. परियोजना क्षेत्र के लाभान्वितों की निजी भूमि पर कार्यों की लागत की 10 प्रतिशत राशि व बी.पी.एल., अनुसूचित जाति व जन जाति हेतु 5 प्रतिशत व सामुदायिक सम्पत्तियों की लागत का 5 प्रतिशत श्रम, नकद या सामग्री के रूप में वसूल कर जलग्रहण विकास कोष' में जमा कराएगी व इसका उपयोग जलग्रहण कार्यों के रखरखाव पर किया जावेगा। इस संबंध में लाभान्वितों की बैठक दिनांक ..... को आयोजित कर उनकी सहमति प्राप्त कर पंचायत रिकार्ड में रख ली गई है।

5. जलग्रहण परियोजना के कार्य मजदूरों से ही कराए जाएंगे, मशीनरी का उपयोग नहीं किया जावेगा।

6. लाभान्वित (Users) उन्नत कृषि की तकनीक, पानी की बूंद-बूंद के उपयोग की नई सिंचाई पद्धति, पशु नस्ल सुधार हेतु कृत्रिम गर्भाधान तकनीक अपनाएंगे, इस संबंध में परियोजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे व जलग्रहण समिति की बैठकों में नियमित भाग लेंगे, पंचायत इन गतिविधियों की प्रभावी क्रियान्विति सुनिश्चित करेगी।

7. यदि पंचायत उपरोक्तानुसार कार्यवाई करने में असफल रहती है तो राज्य सरकार परियोजना के कार्यों को बन्द कर दे, उसमें पंचायत कोई कोई एतराज नहीं होगा।

हस्ताक्षर **हस्ताक्षर**

नाम ग्राम सेवक ..... नाम सरपंच .....

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

RURAL DEVELOPMENT & PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

(Land Resources Section)

Room No. 153, Pant Krishi Bhawan

No. F2 (140) RD/LR/2/2006 Jaipur, Dated : 01.12.2006

Chief Executive Officer, Zila Parishad,
All districts (except Sriganganagar)

Sub. : Time frame and responsibilities for different activities for the projects sanctioned in 2006-07.

Sir,

Government of India has sanctioned new watershed projects under DDP, DPAP and IWDP in 2006-2007. Funds of first installments have already been released to Zila Parishad.

Implementation of these programmes has to be carried out as per GoI guidelines 'Hariyali'. Well begin is half done. Since the shelf of projects are ready with you, therefore following the provisions of para 5 of Hariyali Guidelines and instruction issued vide this office order No. F. 6(12) RD/LR/2/06/Pt.III dated 4.10.2006 and priority, the allotment should have already been done and preparation of DPR must be in progress.

Pr. Secretary, RD & PR has desired that competent WDT should be in place, proper base line survey and PRA should be carried out in consultation with watershed people, appropriate Soil & Water Conservation measures & Production plan for Agriculture, Horticulture, Pasture development, Afforestation Livestock development should be prepared for complete water shed to ensure increased and sustainable production. For every watershed activity user group should be identified, people who do not have assets need be organized in self help groups for income generation looking to the resources & traditions. Time limit to complete initial activities have been spelt out in the enclosed format.

I am directed to inform that Zila Parishad should take all possible steps to complete the process for preparation of meaningful DPRs in stipulated time.

Pr. Secretary, RD & PR has desired to have details of projects sanctioned in 2005-06 and 2006-07 on the basis of enclosed format. Please send details by Fax/e-mail latest by 15.12.2006

Encl : As above

Yours faithfully,

Sd/-

Dy Secretary (LR)

ACTIVITIES, TIME FRAME & RESPONSIBILITIES WITH RESPECT TO NEW PROJECTS SANCTIONED IN 2006-07

S. No.	Activities	DDP	DPAP	IWDP	Person responsible for timely action
1.	Issue of sanction of Projects by Govt. of India.	28.09.06	29.09.06	18.07.06	DoLR, MoRD, Gol
2.	Allotment of projects to PIA.	28.11.06	29.11.06	18.08.06	CEO
3.	Release of funds to PIA.	13.12.06	14.12.06	02.09.06	CEO
4.	Identification and placement of four members of WDT.	31.12.06	31.12.06	18.09.06	PIA/CEO
5.	Training for WDT members.	15.01.07	15.01.07	03.10.06	CEO
6.	PRA and baseline Survey.	31.01.07	31.01.07	18.10.6	AEn., PS through WDT members
7.	Soil & Water Conservation Plan.	28.02.07	28.02.07	18.11.06	Engineering Expert
8.	Production Plan & Constitution of different user groups :	28.02.07	28.02.07	18.11.06	AEn., PS through WDT members
	(i) Agriculture				Agricultural Expert
	(ii) Animal Husbandry				Livestock Expert
	(iii) Pasture development and Afforestation				Agriculture/Forest Expert
	(iv) Horticulture				Agriculture/Horticulture Expert
	(v) Constitution of SHGs and Preparation of Livelihood Plan				Social Scientist
9.	Preparation of DPR and consent of Gram Sabha.	15.03.07	15.03.07	03.12.06	AEn. Sarpanch
10.	Finanlization of DPRs.	31.03.07	31.03.07	31.12.06	AEn./BDO
11.	Approval of DPRs by ZP.	In the first meeting of ZP convened after receipt of DPR			CEO

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(भू-संसाधन प्रकोष्ठ)

कमरा नं. 153, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक : एफ. 2 (103) ग्रावि/भू.सं./2/2003 जयपुर, दिनांक : 20.12.2006

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, राजस्थान।

विषय : चारागाह विकास हेतु क्रियान्वयन मार्गदर्शिका।

महोदय,

समस्त जलग्रहण क्षेत्रों में सामुदायिक भूमि की बहुतायत होना हरियाली गाईड लाईन की अनिवार्य शर्त है। जिन पंचायतों में चारागाह नहीं है, उनमें चारागाह भूमि आवंटन करवाने का प्रावधान राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 169 में दिया हुआ है। चारागाह भूमि के विकास का दायित्व राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 170 में स्पष्ट है। इसी अधिनियम की धारा 170 के तहत ग्राम पंचायत चारागाह में चरने वाले पशुओं का शुल्क वसूल कर सकती है।

गरीब एवं भूमिहीन व्यक्ति अपने ईंधन, चारे और छोटी इमारती लकड़ी की आवश्यकता की पूर्ति भी ऐसी सामुदायिक भूमियों से ही करते हैं, अतः इनको विकसित करना अनिवार्य है। हमारे राज्य में पशुधन की संख्या जनसंख्या के बराबर है। इन पर ध्यान देकर दुग्ध, मांस एवं ऊन का उत्पादन बढ़ाकर गांवों में समृद्धि लायी जा सकती है। इन सबके लिए चारागाहों का विकास अनिवार्य है। इससे स्थानीय रोजगार तो सृजित होता ही है, गरीब एवं भूमिहीन परिवारों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और पशुधन की उत्पादकता में वृद्धि होती है।

बायफ द्वारा चारागाह विकास हेतु क्रियान्वयन मार्गदर्शिका तैयार की गई है, जिसकी प्रति संलग्न की जा रही है। इसके साथ ही चारागाहों के संबंध में ग्राम पंचायत के दायित्व, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत धारा 169, 170 और 171 की प्रति भी संलग्न की जा रही है। आपसे अपेक्षा है कि जलग्रहण क्षेत्रों में आने वाली सामुदायिक भूमियों पर चारागाह विकास का कार्य अनिवार्य रूप से कराना सुनिश्चित करें और इसके लिए अभी से कार्य योजना तैयार कर डीपीआर में शामिल कर ली जावे। यदि पूर्व में डीपीआर में यह गतिविधि किन्हीं कारणों से नहीं ली गई है तो, अब इसका समावेश कर, उसमें संशोधन करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

ह./-
परियोजना निदेशक एवं पदेन
उप सचिव (भू-संसाधन)

चारागाह विकास हेतु क्रियान्वयन मार्गदर्शिका

1. पृष्ठभूमि

राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में पशुपालन व्यवसाय का योगदान 19 प्रतिशत है। राज्य के सभी श्रेणी के किसानों की पशु सम्बन्धी क्रियाएं एवं उनकी द्वारा की जाने वाली कृषि एवं फसल चक्र के मध्य घनिष्ठ अर्न्तसम्बन्ध है। व्यक्तिगत, कृषि भूमि, चारागाह (बीड) एवं गोचर भूमि (चरनोट) पशुओं के हरे/सुखे चारे के मुख्य स्त्रोत है। 80 प्रतिशत से अधिक ग्रामों में उपलब्ध गोचर भूमि पशुओं को चराने के उपयोग में ली जाती है। सीमान्त कृषकों एवं भूमिहीन परिवारों के लिए ग्राम-चरनोट की भूमि ही पशु चारे का मुख्य स्त्रोत है। स्वतंत्रता से पूर्व गोचर भूमि का प्रबन्ध ठिकानेदार (जमीदार) द्वारा किया जाता था, जो चारे के उपयोग के बदले में शुल्क (घासमारी) वसूल करता था। यह व्यवस्था पर्याप्त एवं उपयोगी थी। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात इन सामुदायिक चारागाह के प्रबंधन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाने लगा। व्यक्तिगत लाभ की भावना के कारण गोचरभूमि पर अतिक्रमण होने लगे एवं पशु सम्पदा की संख्या में वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप घास का उत्पादन (300 से 400 कि.ग्रा. प्रति हैक्टर) कम होने लगा। अपर्याप्त प्रबन्ध व्यवस्था के कारण अनेक ग्रामों में न केवल अतिक्रमण बढ़े वरन सामुदायिक चारागाह भूमि (गोचर भूमि) का क्षेत्र भी कम हो गया।

2. चारागाह की कानूनी पहचान

शासन द्वारा पशुओं की चराई के लिए चिन्हित की गयी भूमि-चारागाह पर गांव के सभी परिवारों के छोटे/बडे जानवरों को पोषण के रूप में उत्पादक चारा उपलब्ध कराने एवं ग्राम पंचायत संस्थान को चारागाह की सुरक्षा, रखरखाव, विकास, उपयोग तथा चराई शुल्क निर्धारित करने का अधिकार देना। ***(राजस्थान पंचायत राज नियम 170, 171)***

3. चारागाह विकास के लक्ष्य एवं विषय–वस्तु

- गांवों में उपलब्ध चारागाह पर विकास कार्य कर के भूमि को उपजाऊ बनाना।
- बी.पी.एल. परिवारों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
- अविकसित चारागाह भूमि को बंजर बनने से रोकना-भूमि सुधार विधि का उपयोग तथा उन्नत घास के बीज का छिड़काव तथा चारे के उपयोगी पेड़/पौधे लगाना।
- पानी संरक्षण हेतु प्रभावी तकनीक का उपयोग करना।
- चारागाह विकास में ग्रामवासियों की पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करना।
- ग्रामवासियों द्वारा, सभी जातियों के बी.पी.एल. परिवारों का उचित प्रतिनिधित्व (70 प्रतिशत) सुनिश्चित करते हुए, चारागाह प्रबन्धन समिति (VMC) का गठन करवाना एवं गठित समिति में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देकर चारागाह प्रबन्धन समिति द्वारा सदस्यों को प्रशिक्षित करना।
- विकसित चारागाह के चारे के उपयोग के लिए व्यवस्था स्थापित करना तथा चारागाह के लाभ का समान वितरण एवं उपयोग नियमन का लक्ष्य प्राप्त करना।

4. चारागाह विकास क्षेत्र के चुनाव का मापदण्ड

1. बी.पी.एल. बाहुल ग्राम होना आवश्यक है।
2. दुग्ध उत्पादक पशुओं की प्रचुरता हो।
3. चारे की कमी हो।
4. समुचित चारागाह हो।
5. पशुधारकों की सक्रिय सहभागिता मिले।
6. ग्राम पंचायत का सहयोग मिले।
7. चारागाह विकास में आम सहमति हो।
8. नजदीकी दुग्ध बाजार उपलब्ध हो।
9. क्रियान्वयन संस्था पर लोगों का विश्वास हो।
10. पूर्व में किसी अन्य संस्था द्वारा चारागाह विकास कार्य न किया गया हों।

5. चारागाह विकास हेतु भूमि अधिकरण की प्रक्रिया

1. परियोजना क्षेत्र के चुनाव का मापदण्ड के अनुसार निर्धारण करना।
2. ब्लॉक एवं जिला स्तर पर अधिकारियों को परियोजना से होने वाले अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन परिणाम की जानकारी देना।
3. रेवेन्यू रिकार्ड से गांव के पास उपलब्ध सामुदायिक भूमि का पता लगाना।
4. ग्राम समुदाय की उपस्थिति में चारागाह विकास प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा करना।
5. ग्राम वासियों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए, जमाबन्दी, नकल ट्रेस प्राप्त करना।
6. ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम वासियों की उपस्थिति में हल्का पटवारी से सीमाज्ञान करवाना।

नोटः–चारागाह जिनके संबंध में कोई विवाद न हो, उन पर ही विकास कार्य किया जावे।

6. चारागाह विकास की गतिविधियां–

- चारागाह विकास की अवधारणाओं का प्रचार प्रसार करना एवं लोगों में जागरुकता लाना।
- रेवेन्यू रिकार्ड से गांव के पास सामुदायिक चारागाह भूमि की उपलब्धता का पता लगाना।
- ग्राम समुदाय की उपस्थिति में चारागाह विकास प्रस्ताव पारित कराना।
- ग्रामवासियों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए, पंचायत राज का अनापत्ति प्रमाणपत्र, जमाबन्दी, नकल ट्रेस, आदि प्राप्त करना।
- ग्रामवासियों की उपस्थिति में हल्का पटवारी से सीमाज्ञान करवाना।
- ग्राम प्रबन्धन समिति (वी.एम.सी.) का गठन।
- विकसित चारागाहों का शैक्षणिक भ्रमण एवं निर्मित चारागाह समितियों के साथ अनुभवों का आदान प्रदान।
- चारागाह विकास सम्बन्धित गतिविधियों के क्रियान्वयन में क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण।
- नर्सरी निर्माण।
- भूमि तैयार करना, फैंसिग कार्य, वी-डीच, वृक्षारोपण हेतु गड्ढे तैयार करवाना।
- ट्रेक्टर हकाई, घास का छिड़काव, वृक्षारोपण (जून-जूलाई)
- चारा के उपयोग की प्रक्रिया, लेखा जोखा रखना, ग्राम कोष निर्माण एवं उपयोग आदि पर वी. एम.सी. को प्रशिक्षण।
- वी.एम.सी. के निर्णय अनुसार घास बीज एकत्रित करना, घास कटाई एवं बंटवारा।
- प्रगति समीक्षा एवं अन्य प्रक्रिया हेतु समयानुसार वी.एम.सी. की सभाओं का आयोजन।

7. मानक चारागाह श्रम व लागत विवरण *(प्रति हैक्टर)*

क्र.		श्रम विवरण				लागत विवरण		
सं.	विवरण	इकाई	मानव दिवस	कुल खर्च रू.	विवरण	इकाई	मानव दिवस	कुल खर्च रू.
1.	खाई बण्ड/बाड़	335 Rf	75	5475 (48%)	परिवहन	200 Plants	3	900 (28.6)
2.	वी डी एच	1092 Rf	55	4015 (35.3%)	दीमक नियंत्रण	50 gm/p	25	375 (11.9)
3.	गडे खोदना	200 N	21	1533 (13.5%)	पौधें	200 Plants	2.8	861 (27.3)
4.	पौधे लगाना	200 P	5	365 (3.2%)	धामण बीज	6 Kg.	35	385 (12.2)
					हिमेटा बीज	4 किलो	45	180 (5.7)
					हकाई	100/Bigha		450 (14.3)
	योग		**156**	**11388 (78 %)**				**3151 (19 %)**
-	चौकीदार (One for 40 ha)			540				-
	महायोग (श्रम व लागत)							15079.00
-	मोनिटरिंग फेसिलिटेशन							2471.00
-	कुल योग प्रति हैक्टर							17550.00
-	Rs. 73 प्रति मानव दिवस							

8. चारागाह विकास गतिविधि क्रियान्वयन

1. चिन्हित क्षेत्र की बाड़ करना (खाई, थोर, पत्थर बाड)।
2. विलायती बबूल को जड से उखाड़ कर अलग करना।
3. चारागाह क्षेत्र से अनावश्यक पत्थरों को एकत्रित कर अलग ढेर बनाना।
4. बहु उपयोगी पौधारोपण हेतु विकेन्द्रीत नर्सरी तैयार करवाना।
5. दुग्ध उत्पादक घास बीज धामण (10 से 14 किलो प्रति हैक्टर) एवं भूमि कटाव को रोकने की क्षमता वाला घास बीज हेमेटा (4 किलो प्रति हैक्टर) आदि की व्यवस्था करना।
6. भूमि की ढलान के विपरित वी-डीच बनाना।
7. पौधा-रोपण हेतु 200 गड्डे प्रति हैक्टर खुदवाना।
8. घास बीज एवं उर्वरक छिड़काव के बाद भूमि पर ट्रैक्टर से हकाई करना।
9. वी-डीच पर हिमेटा बीज छिड़कना।
10. प्रथम वर्षा उपरांत बहु-उपयोगी पौधरोपण (गड्डे में, दो खाई के बीच में बण्ड की दूसरी तरफ) करना।
11 पौधरोपण के साथ-साथ पौधों की लम्बाई के अनुसार थांवला बनाना।
12. घास की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए यूरिया का छिड़काव करना।
13. प्रथम वर्ष बीज एकत्रित न करते हुए जमीन पर ही गिरने देना चाहिए ताकि पूर्णतः प्रकीर्णन हो सके।
14. अक्टूबर माह में घास की कटाई करावें।
15. द्वितीय वर्ष में मृत पौधों के स्थान पर नये पौधे लगावें।
16. छठवें वर्ष में सम्पूर्ण चारागाह क्षैत्र में पुनः धामण बीज का छिड़काव करें।
17. चारागाह के चारों तरफ बनी सुरक्षा बाड पत्थर बण्ड या खाई पर कंटीली झाड़ियों से ढकने के बाद हवा से न उड़े इस हेतु भारी पत्थरों से दबा दे।

9. भौतिक कार्य एवं माप

संरचना		*आकार*
पत्थर बाड़	:	2.5 फीट आधार x 4 फीट उंचाई x 2 फीट टॉप
खाई	:	2 फीट आधार x 3 फीट गहराई x 3 फीट टॉप
थोर की बाड+खाई	:	2 फीट आधार x 2 फीट गहराई x 2 फीट टॉप
वी डीच	:	2.5 फीट चौ. x 1 फीट गहराई
गड्ढे का आकार	:	1.5 x 1.5 x 1.5 घन फीट
पौधे से पौधे की दूरी	:	5 मी. x 5 मी.
पौधों की कतार की दूरी	:	10 मीटर
कुल पौधे प्रति हैक्टर	:	200

10. चारागाह भूमि पर मिट्टी, वर्षा आधारित घास एवं फलीदार घास का चयन

क्रम	वार्षित वर्षा (मी.मी.)	भूमि	उपयुक्त घास	फलीदार घास
1	200 से कम	बलुई मृदा	गुरत (Panicum antidotale)	
			सेवण (Lasiurus sindicus)	
			राईचा (Cymbopogon martinil)	
2	200 से 400	एलुवियल (भूरभूरी)	सफेद धामण (Cenchrus ciliaris)	Clitoria ternatia
		मृदा	काला धामण (Cenchrus setigerus)	
3.	400 से 600	लाल बलुई दोमट	सफेद धामण Cenchrus ciliaris)	हिमेटा
		मृदा	Chrysopogon fulvus	(Stylosanthus Hemata)
			लाप (Heteropogon contortus)	Botheriochloa Pertusa
		काली चीकनी दोमट मृदा	मकरा (Dactyloctenium aegyptium)	

4.	600 से अधिक	दोमट व चीकनी दोमट मृदा पथरीली-निम्न श्रेणी मृदा	Pascium Maximum नेपियर (Napier hybrid) Setaria sphacelata सेरन (Schim Nervosum)	हिमेटा (Stylosanthus Hemata) Siratarо

11. चारागाह विकास हेतु आवश्यक प्रशिक्षण

1. भौतिक कार्य के आधार पर प्रशिक्षण जैसे पत्थर की दीवार/थोर बाड़, खाई बण्ड, गड्डे वी-डीच आदि।
2. नर्सरी बनाना।
3. लेखा जोखा संधारण प्रस्ताव रजिस्टर, कार्य योजना रजिस्टर, वाउचर फोल्डर, केशबुक, खर्च रजिस्टर, उत्पादन रजिस्टर सदस्यता रजिस्टर)
4. घास कटाई एवं चराई व्यवस्था।
5. सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबन्धन प्रशिक्षण (सक्रिय निगरानी एवं सदस्यता शुल्क, घास बीज बिक्री से आय, ग्राम पंचायत सहयोग एवं पेनल्टी आदि से प्रबन्धन)।
6. प्रशिक्षण के लिए योग्य व्यक्ति-चयनित उत्साही, इच्छुक पुरुष-महिलाओं व ग्राम प्रबन्धन समिति के सदस्य।

12. भुगतान प्रक्रिया

1. कोष संचालन हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता खुलवाना।
2. भुगतान चैक या डी.डी. द्वारा।
3. श्रम भुगतान स्थल-ग्राम पंचायत कार्यालय या विद्यालय।
4. श्रम भुगतान ग्राम प्रबन्धन समिति के कोषाध्यक्ष, सरपंच, वार्डपंच, पटवारी, स्थानीय शिक्षक या शिक्षित युवाओं की उपस्थिति में।

13. घास कटाई एवं चराई व्यवस्था

1. कांटो और आधा ले जाओ (Cut & Carry system) : चारागाह के निश्चित भाग से कुल काटी गयी घास का 50 प्रतिशत हिस्सा काटने वाले का एवं शेष 50 प्रतिशत धारा प्रबन्धन समिति में जमा करवाना। जमा घास को निलामी द्वारा बेचना। प्राप्त राशि समिति खाते में जमा करवाना।
2. नियंत्रित चराई (Control Grazzing) : सम्पूर्ण चारागाह क्षेत्र को निश्चित ब्लॉक्स में बांटना, एक निश्चित अंतराल में चराई करवाना, प्राप्त आय से चारागाह का भावी प्रबन्धन करना।

14. चारागाह प्रबन्धन समिति के प्रमुख कार्य

1. चारागाह विकास हेतु कार्य योजना, क्रियान्वयन, लाभ का बंटवारा, विवाद समाधान।
2. घास बीज एकत्रीकरण।
3. चारे की कटाई।
4. पशु चराई व्यवस्था।
5. चारागाह से अन्य आय।
6. पेनल्टी एकत्रित करना।
7. सुरक्षा व्यवस्था।
8. पुर्ननिर्माण एवं सतत नियमन।
9. आवश्यकता आधारित अन्य परिवर्तन हेतु प्रबंधन समिति सामुदायिक निर्णय के लिये स्वतंत्र।
15. स्थायी चारागाह प्रबन्धन हेतु ग्रामकोष की स्थापना।

उद्देश्य

- चारागाह सुरक्षा, बाड़ मरम्मत, चौकीदार भुगतान।
- कोष में धन संचय के स्त्रोत।
- श्रमदान।

- चारागाह से प्राप्त पेनल्टी।
- चारा उपयोग की व्यवस्थाओं से।
- उपयोग के नियम, संचालन अधिकार।

ग्रा.प्र. समिति का सर्वसम्मति से उपयोग हेतु लिया गया निर्णय

- बी.पी.एल. परिवारों को प्रत्येक कार्य में प्राथमिकता।
- एकत्र घासमारी/उत्पादन कर को शीघ्र बैंक में जमा करवाना।
- चारागाह में अवैध चराई एवं अतिक्रमण को रोकना।
- बी.पी.एल. परिवारों एवं महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करना।
- प्रत्येक माह चारागाह विकास एवं ग्रामीण चारा उपलब्धता पर बैठक में चर्चा।

16. चारागाह विकास में संभावित विवाद

1. भूमि अधिग्रहण एवं विकास उपरांत उभरते अतिक्रमण।
2. अवैध खनन।
3. अवैध कृषि कार्य।
4. अवैध निर्माण।
5. आवाजाही का मार्ग निर्धारण।
6. अनाधिकृत घास चराई।
7. घास चोरी।
8. सुरक्षा व्यवस्था को नष्ट करना।

17. चारागाह विकास में संभावित विवादों का समाधान

1. विवादित स्थल को छोड़कर शेष चारागाह भूमि को विकसित करना।
2. संस्था की छवि का उपयोग करना।
3. निःस्वार्थ प्रभावशाली ग्रामीण, ग्राम पंचायत के सदस्यों जिला अधिकारी एवं प्रशासन का सहयोग लेना।
4. विकसित चारागाह क्षेत्र का भ्रमण।
5. ग्राम प्रबन्धन समिति द्वारा कड़ी निगरानी एवं निष्पक्ष कार्यवाही।

चारागाह–ग्राम पंचायत के दायित्व
(अति आवश्यक)

1. रा.पं.स. नियम 169 : चारागाह भूमियां

(1) यदि किसी ग्राम में एक सामान्य चारागाह किसी पंचायत के अधीन न रखा गया हो तो, तहसीलदार को एक नई चारागाह की भूमि प्राप्त करने या नया चारागाह बनाने के प्रस्ताव भेजेगी।

(2) ऐसे प्रस्ताव के प्राप्त होने पर, तहसीलदार उसी समय पर कार्यवाही करेगा तथा पंचायत से प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर उस प्रस्ताव पर लिए गए अपने निर्णय से पंचायत को अवगत करवाएगा। यदि प्रस्ताव के प्रस्तुत करने के तीन माह के भीतर स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तो वह विकास अधिकारी को लिख सकती है, जो चारागाह आवंटन करवाने हेतु कदम उठायेगा।

(3) चारागाह पर उत्पन्न होने वाले पेड एवं अन्य प्राकृतिक उपज से होने वाली आय पंचायत निधि में जमा की जाएगी।

(4) एक पंचायत ऐसे पेडों या प्राकृतिक उपज को किसी प्राईवेट ठेकेदार या सार्वजनिक नीलामी द्वारा ठेके पर उठा सकती है तथा वर्तमान में प्रभावशाली कानून के आधार पर उपरोक्त तरीके द्वारा सूखे, खराब एवं गिरे हुए पेड़ों को बेच सकती है।

(5) चारागाह में पाए जाने वाले गोबर को भी पंचायत प्राइवेट ठेके या सार्वजनिक नीलाम द्वारा बेच सकती है।

(6) पशुओं की संख्या में वृद्धि होने पर पंचायत चारागाह की भूमि को ओर भी बढा सकती है चारागाह बढ़ाने के लिये नये चारागाह प्राप्त करने के लिए समान कार्यवाही करनी होगी।

(7) चारागाह पशुओं के चराने के अतिरिक्त अन्य किसी उपयोग में नहीं ली जाएगी।

(8) जहां किसी व्यक्ति द्वारा चारागाह की भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा हो, या अन्य किसी उपयोग में लिया गया हो तो पंचायत नियम 160 के तहत तैयार किये गये सर्वे अभिलेख के आधार पर तत्समय लागू कानून के अंतर्गत तहसीलदार के नाम प्रार्थना-पत्र पेश कर सकती है।

2. रा.पं. स. नियम 170 : चारागाह भूमियों का विकास

(1) पंचायतों का यह कर्तव्य होगा कि चारागाह भूमियों में अतिक्रमण रोके और उपयुक्त प्रकार के घास, झाडियां और पौधे लगाकर विकास करें। इस हेतु पंचायत हर गांव की चारागाह भूमि का नियंत्रण संबंधित गांव के पंच की अध्यक्षता में गठित पांच सदस्यीय कमेटी को सुपुर्द करेगी। शेष चार सदस्य ग्राम सभा चुनेगी।

(2) बंद क्षेत्र का घास खुली निलामी या प्राइवेट ठेके द्वारा बेचा जा सकता है।

(3) विकास योजना की राशि श्रम प्रधान चारागाह विकास के कार्य में की जा सकती है।

3. रा.पं.स. नियम 171 : चराई शुल्क– पंचायत प्रस्ताव द्वारा निर्णय करके चारागाह में चरने वाले पशुओं का शुल्क वसूल कर सकती है, लेकिन ये दरें निम्नलिखित से किसी भी तरह अधिक नहीं होगी-

(अ)	भैंस, गाय, उंट, घोडा, प्रति जानवर के हिसाब से	:	10/- रूपये प्रति दिन
(ब)	बकरी और अन्य जानवर प्रति जानवर के हिसाब से	:	5/- रूपये प्रति दिन

राजस्थान पंजायतीराज मैन्युअल (पेज 127, 128)

ACTIVITIES, TIME FRAME & RESPONSIBILITIES WITH RESPECT TO NEW PROJECTS SANCTIONED IN 2006-07-CDP

S.No.	Activities	Time Frame
1.	Issue of sanction by DOLR, MoRD, GOI.	28.9.06
2.	Intimation to PIA-DCF of the district & Transfer of funds to PIA.	upto 20.10.06
3.	Identification & selection of areas in consultation with Gram Panchayat for Sand dune stabilization Afforestation & Shelter belt planation- if shelf of projects are not ready.	5.11.06
4.	Prioritization of selected areas as per sanctions.	15.11.06
5.	Constitution of Village Forest Protection Management Committees (VFPMC).	30.11.06
6.	Training of forest officials VFPMC members, PRIS & other stake holders.	15.12.06
7.	PRA including base line survey to record status of water, fuel, fodder, small timber & its availability.	31.12.06
8.	Exposure visits to successful sites within & outside state.	15.1.07
9.	Preparation of treatment & production plan as per land capability in consultation with the local people alongwith estimates on approved norms of state forest department.	30.1.07
10.	Preparation of DPR.	10.2.07
11.	Submission of DPR to Zila Parishad & CCF, Jodhpur simultaneously.	20.2.07
12.	Issue of Technical Sanction by CCF, Jodhpur.	28.2.07
13.	Approval by Zila Parishad & forwarding it to state Govt.	15.3.07
14.	Issuance of Financial Sanction by state govt.	30.03.07
15.	Execution of works through VFPMC members/User Groups/SHGs.	As per plan

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
(भू-संसाधन प्रकोष्ठ)

क्रमांक : प.15 (4) ग्रा.वि./एलआर/2/2006 जयपुर, दिनांक : 01.02.2007

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, समस्त राजस्थान।

विषय : जलग्रहण विकास दल में पंचायत समिति में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता को तकनीकी सदस्य के रूप में सम्मिलित करने हेतु।

महोदय,

विभागीय समसंख्यक पत्र क्रमांक एफ. 15 (4) ग्रा.वि./भू.सं./06 दिनांक 4.9.2006 के जरिए जलग्रहण विकास दल में विभिन्न संकाय के सदस्यों को सम्मिलित करने तथा उनको देय मानदेय के बारे में निर्देश प्रदान किये गये थे। कतिपय जिलों द्वारा विभाग के ध्यान में लाया गया हैं कि जिले में तकनीकी सदस्य के रूप में सम्मिलित किये जाने वाले अभियन्ताओं की कमी होने के कारण जलग्रहण विकास दल का पूर्ण रूप से गठन किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

हरियाली मार्गदर्शिका के अनुच्छेद 15 में व्यवस्था प्रदान की गई है कि परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि यदि वह चाहे तो अपने कर्मचारियों को जलग्रहण विकास दल के सदस्य के रूप में शामिल रप सकता है। इस व्यवस्था के मध्यनजर निर्देश दिये जाते हैं कि :-

(i) पंचायत समिति में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता जलग्रहण विकास दल के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे यदि पंचायत समिति में एक से अधिक जल ग्रहण विकास दल गठित किया हुआ है व कनिष्ठ अभियन्ता (जलग्रहण) कम पदस्थापित है, तो शेष जलग्रहण विकास दल/दलों हेतु प्राईवेट तकनीकी सदस्य की सेवाएं प्राथमिकता पर पूर्व में दिए गए निर्देशानुसार प्राप्त की जावे।

(ii) यदि किसी पंचायत समिति में सिर्फ एक ही कनिष्ठ अभियन्ता (जलग्रहण) कार्यरत है एवं भी वहां सहायक अभियन्ता (जलग्रहण) भी कार्यरत नहीं हैं तो उस स्थिति में जलग्रहण विकास दल में प्राईवेट तकनीकी सदस्य की सेवाऐं पूर्व में दिए गए निर्देशानुसार प्राप्त की जावे ताकि नियमित कनिष्ठ अभियन्ता समस्त जलग्रहण परियोजनाओं के पर्यवेक्षण का कार्य प्रभावी ढंग से कर सके।

(iii) जिन पंचायत समितियों में एक भी कनिष्ठ अभियन्ता जलग्रहण कार्यरत नहीं हैं वहां जलग्रहण विकास दल में प्राईवेट तकनीकी सदस्य की सेवाएं पूर्व में दिए गए निर्देशानुसार प्राथमिकता पर प्राप्त की जावे।

नियमित कनिष्ठ अभियन्ता जलग्रहण विकास दल के सदस्य होने की स्थिति में वह दल का लीडर (Team Leader) होगा। इन निर्देशों की प्रभावी क्रियान्विति एक माह के अन्दर-अन्दर सुनिश्चित करने का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व अधिशाषी अभिन्ता (भू संसाधन) का होगा।

भवदीय,

ह./-

(राम लुभाया)
प्रमुख शासन सचिव

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(भू-संसाधन प्रकोष्ठ

कमरा नं. 153, कृषि पंत भवन

क्रमांक : प. 15 (4) ग्रावि/भूसं/2/2006 जयपुर, दिनांक : 08.02.2007

परिपत्र

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी हरियाली मार्गदर्शिका के अनुसार जलग्रहण परियोजनाओं की क्रियान्विति राज्य में मरु विकास कार्यक्रम, सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम तथा बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत की जा रही है। जैसाकि विदित है कि जलग्रहण कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल जल संग्रहण ढाचों के निर्माण का कार्य ही नहीं कराया जाना है बल्कि क्षेत्र के प्रत्येक कृषक के लिये एक प्रभावी उत्पादन योजना बनाकर सतत उत्पादन वृद्धि सुनिश्चित की जानी है और जलग्रहण क्षेत्र में आने वाली सामुदायिक भूमियों पर चारागाह विकास एवं वृक्षारोपण कर स्थानीय ग्रामवासियों की चारे और ईंधन की आवश्यकता की पूर्ति की जानी है ताकि उनके बेहतर जीवनयापन के लिये दीर्घकालीन प्रबंध सुनिश्चित हो सके। कार्यक्रमों की समीक्षा के उपरान्त दृष्टिगत हुआ कि जलग्रहण जैसे महत्वपूर्ण जनसमुदाय के कार्यक्रम की क्रियान्विति की ओर जिला/पंचायत समिति स्तर के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिसके कारण संसाधन हीन लोगों को अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है।
उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर जलग्रहण कार्यक्रम की प्रभावी क्रियान्विति हेतु निम्नांकित आदेश प्रसारित किये जाते हैंः

(i) जलग्रहण विकास दल के चारों सदस्यों को दो माह की अवधि में प्रशिक्षित करने तथा कार्यशील (Functional) बनाने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी अधिशाषी अभियन्ता/परियोजना अधिकारी (भू-संसाधन) की होगी। यदि निर्धारित अवधि में दल के सदस्यों को प्रशिक्षित कर कार्यशील नहीं बनाया गया तो इसके लिये अधिशाषी अभियन्ता/परियोजना अधिकारी (भू-संसाधन), सहायक अभियन्ता तथा कनिष्ठ अभियन्ता व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(ii) जलग्रहण परियोजना शुरू होने से पूर्ण करने तक विभिन्न गतिविधियों का संपादन किया जाता है। समय पर कार्य शुरु कर पूर्ण करने हेतु विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक एफ. 2 (104)/ग्रावि/भूसं/2/05 दिनांक 1.8.2006 के जरिये गतिविधियों के क्रम का निर्धारण किया जाकर इनकी पूर्णता अवधि तय की गई है। अधिशाषी अभियन्ता/परियोजना अधिकारी (भू-संसाधन), सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता सुनिश्चित करेंगे कि परियोजना के कार्यों का निष्पादन विभागीय परिपत्र दिनांक 1.8.2006 में उल्लेखित क्रमानुसार प्रभावी ढंग से किया जा रहा है। निर्धारित क्रम में कार्य नहीं किए जाने की स्थिति में इसे मार्गदर्शिका का उल्लंघन माना जाएगा तथा दोषी कार्मिको के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(iii) विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ. 8(107) ग्रावि/भू.सं/2/दिनांक 11.10.2006 के द्वारा जलग्रहण परियोजनाओं के निष्पादन हेतु सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ताओं के दायित्व निर्धारित किए गए है, परन्तु उनके द्वारा दायित्वों का प्रभावी एवं पूर्ण रूप से निर्वहन नहीं किया जा रहा है। पुनः निर्देश दिए जाते हैं कि परिपत्र दिनांक 11.10. 06 की भावना के अनुरूप कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित किया जावे।

(iv) परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी सुनिश्चित करे कि जलग्रहण परियोजनाओं हेतु पूर्ण रूप से गठित जलग्रहण विकास दल कार्यों का निष्पादन विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ. 15 (4) ग्रावि/भूसं/2/06 दिनांक 4.9.06 के अनुसार करता है। जलग्रहण विकास दल के सदस्यों को पाबन्द किया जावे कि वे विस्तार कार्यकर्ता (Extension Worker) के रूप में कार्य करे और अन्य विभागों यथा कृषि, उद्यानिकी, वन, पशुपालन तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की गतिविधियों को स्वीकृत जलग्रहण परियोजना क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से लागू किया जावे।

(v) सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता जलग्रहण विकास दल के सदस्यों हेतु कार्ययोजना बनावें एवं उसके अनुसार कार्य किए जाने की साप्ताहिक समीक्षा करें।

(vi) जलग्रहण परियोजना क्षेत्र का नियमित रूप से निरीक्षण किया जावे ताकि मार्गदर्शिका के अनुसार कार्यों के निष्पादन में गुणवत्ता नियंत्रण एवं उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित हो एवं संसाधन हीन व्यक्तियों को योजना से दीर्घकालीन लाभ प्राप्त हो सकें।

ह./-

प्रमुख शासन सचिव

ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण वृत अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भीलवाडा एवं कोटा
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त (श्रीगंगानगर को छोड़कर)।
6. संयुक्त निदेशक, (एमओएपी)/पी.एफ.सी./एमआईईएस/प्रशासन, निदेशालय, जयपुर।
7. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव (मो. एवं मू.) को विभागीय बेवसाइट हेतु। ह./-

उप सचिव (भू-संसाधन)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(भू-संसाधन प्रकोष्ठ)

कमरा नं. 153, पंत कृषि भवन, जयपुर।

क्रमांक : एफ. 15 (4) ग्रावि/भू.सं./2/06 जयपुर, दिनांक : 27.02.2007

परिपत्र

समसंख्यक परिपत्र दिनांक 4.9.2006, जलग्रहण विकास दल के गठन एवं उनको देय मानदेय के क्रम में जारी किया गया था और इसके साथ जलग्रहण विकास दल के सदस्यों के साथ अनुबन्ध का प्रारूप भी संलग्न किया गया था।

विभिन्न जिलों से प्राप्त सूचनाओं से यह स्पष्ट है कि निरन्तर प्रयासों के पश्चात् भी कतिपय जिलों में कृषि/सिविल अभियन्ता निर्धारित किए मानदेय पर उपलब्ध नहीं हो रहे है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट किया जाता है कि जलग्रहण विकास दल के सदस्यों का मानदेय हरियाली मार्गदर्शिका के साथ संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुरूप सीमा तक अनुभव एवं योग्यता के आधार पर दिया जा सकता है। कृषि अभियन्ता को निम्नानुसार मानदेय दिया जा सकता हैः

क.	मानदेय	रूपये 4125.00
ख.	यात्रा/दैनिक भत्ता	रुपये 1875.00
योग		**रूपये 6000.00 प्रति माह**

अन्य सदस्यों के क्रम में भी अनुभव एवं योग्यता के आधार पर परिशिष्ट-1 में दी गई सीमा के अनुसार मानदेय एवं यात्रा भत्ते का निर्धारण जिला परिषद स्तर पर किया जा सकता है ताकि प्रत्येक जलग्रहण क्षेत्र में योग्य एवं अनुभवी सदस्यों की सुनिश्चित् सेवाएं उपलब्ध हो सके और जलग्रहण विकास परियोजनाओं की गति एवं गुणवत्ता में सुधार हो।

ह./-
परियोजना निदेशक एवं पदेन
उप सचिव (भू–संसाधन)

प्रतिलिपि

1. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान (गंगानगर को छोड़कर) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

ह./-
परियोजना निदेशक एवं पदेन
उप सचिव (भू–संसाधन)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
RURAL DEVELOPMENT & PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

No. F. 2 (147) RD/LR/2/2007 Dated : 17th March, 2007
Chief Executive Officer, Zila Parishad,
All Rajasthan (Except Sriganganagar)

Subject : Technical sanction of Watershed Projects.

Sir,

During the course of the discussions in the meeting of XEN (LR) held on 11-12.3.2006, it was brought to the notice of the department that the ' Technical Sanctions' of watershed projects under DDP, DPAP & IWDP are not being issued by the technical staff at any level before staring the works. This fact had never been brought to the notice earlier.

The following arrangements are immediately made for the issuance of technical sanctions :

(i) XEN (LR) working in Zila Parishad will issue technical sanctions up to Rs. 30.00 lacs for the projects sanctioned under DDP, DPAP and other watershed programmes.

(ii) Joint Director of the concerned circle will issue technical sanctions of IWDP and other larger projects to the extent of the sanctioned cost.

Joint Director of concerned circle and XEN (LR) will ensure that :

(a) Technical sanction for al the projects sanctioned in the year 2006-07 is issued before 31.3.2007.
(b) It is the duty of XEN (LR) and Joint Director to get the execution of works as per the technical sanction.
(c) In case of projects of the previous years, especially where DPRs are being prepared now, technical sanction will be issued by the XEN (LR) and Joint Director as the case may be.

As per provisions of GKN, the officer according technical sanctions will be responsible to ensure quality of works in the field as per the sanctioned technical parameters and specifications. Therefore, XEN (LR) & Joint Director would be responsible for this for the estimates sanctioned by them.

These orders will come into force with immediate effect.

Yours faithfully,
Sd/-
(Ram Lubhaya)
Pr. Secretary to Government

Copy to the following for information :

1. SA to Hon'ble Minister RD & PR.
2. PS to Pr. Secretary, RD & PR.
3. Secretary, Panchayati Raj.
4. Secretary, RD with a request to incorporate necessary amendments in Gramin Karya Nirdeshika (GKN).
5. Director, WD & SC.
6. Addl. Director, WD & SC.
7. Jt. Director, MoAP/MIES/Admn./PFC, WD & SC.
8. Jt. Director, WD & SC Jaipur/Ajmer/Kota/Bhilwara/Jodhpur/Udaipur.
9. XEN (LR), Zila Parishad, All Rajasthan (Except Sriganganagar).

Sd/-
PD cum Dy. Secretary (LR)

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग

क्रमांक : प.6 (41) प्र.सु./अनुभाग-3/99 जयपुर, दिनांक 21.03.2007

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 2.3.2006 से गठित जिला जलग्रहण विकास समिति को एतद्द्वारा-तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से

ह./-

(गजानन्द)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि : निम्न को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, मा. राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास)।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास पंचायती राज जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन विभाग, जयपुर।
11. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायत राज विभाग।
12. निजी सचिव, शासन सचिव, वन विभाग।
13. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
14. निजी सचिव, निदेशक, बंजर भूमि, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग।
15. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव, कृषि विभाग।
16. जिला प्रमुख, समस्त जिले (श्रीगंगानगर के अतिरिक्त)।
17. निजी सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक।
18. निजी सचिव, निदेशक, अनुसंधान राजस्थान कृषि विश्व विद्यालय, उदयपुर/बीकानेर।
19. निदेशक, पशुपालन विभाग।
20. जिला कलक्टर, समस्त जिले (श्रीगंगानगर के अतिरिक्त)।
21. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त जिले (श्रीगंगानगर के अतिरिक्त)।
22. परियोजना निदेशक, राज्य दूर संवेदी केन्द्र, जोधपुर।
23. उप सचिव, भू संसाधन ग्रामीण विकास विभाग को उनके पत्र क्रमांक एफ 19 (6) ग्रावि/2/2006 दिनांक 27.2.2007 के क्रम में आदेश की अतिरिक्त प्रतियां समस्त सम्बन्धित को को विवरण हेतु प्रेषित है।
24. रक्षित पंजिका।

ह./-

शासन उप सचिव

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

क्रमांक :-एफ. 6 (12) ग्रा.वि./LR/2/96/ जयपुर, दिनांक : 23.03.2007

परिपत्र

विषय : हरियाली गाईड लाईन से संबंधित।

जलग्रहण विकास योजनाओं की क्रियान्विति भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय (भू संसाधन विभाग) द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार किया जाता है। 'हरियाली' दिशा निर्देशों के पैरा 9 अनुसार जलग्रहण परियोजनाओं को लागू करने का कार्य भारत सरकार व राज्य सरकार की देखरेख एवं निर्देशन में जिला परिषद द्वारा सम्पन्न किया जाएगा।

भारत सरकार से जल ग्रहण परियोजनाओं का आवंटन जिला स्तर पर प्राप्त होने के पश्चात स्थान का चयन जिला परिषद द्वारा हरियाली गाईड लाईन के पैरा 5 के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किया जाता हैं।

लेकिन राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि परियोजनाओं का आवंटन करते समय इन दिशा निर्देशों की पूर्ण पालना नहीं की जाकर परियोजनाओं का आवंटन कर दिया जाता हैं। पैरा 5 में परियोजना आवंटन करने हेतु प्रथम मापदण्ड निम्न प्रकार हैः

"Watersheds where People's participation is assured through contribution of labour, cash, material etc. for its development as well as for the operation and maintenance of the assets created."

लेकिन इन दिशा-निर्देशों की पालना नहीं हो रही है। योजना के लाभान्वितों द्वारा इस योजना के पैरा 36 अनुसार 'जलग्रहण' विकास फण्ड' में निजी भूमि पर कराये गए कार्यों की लागत का 10 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति व जनजाति तथा बी.पी.एल. परिवारों की निजी भूमि पर कराए गए कार्यों की लागत का 5 प्रतिशत जमा नहीं कराया जाता हैं। इसी प्रकार सामुदायिक सम्पत्तियों के निर्माण हेतु भी लागत का 5 प्रतिशत हिस्सा लाभान्वितों द्वारा जमा नहीं कराया जाता है। दिशा निर्देशों में यह स्पष्ट है कि यह राशि मजदूरों की मजदूरी से नहीं काटी जाकर सीधी लाभान्वितों से नकद, श्रम या सामग्री के रूप में वसूल की जानी चाहिए और जल ग्रहण विकास फण्ड से जमा होनी चाहिए। लेकिन इन दिशा निर्देशों की भी पालना नहीं होती है। इस कारण से इन परियोजनाओं में जनभागिता न्यूनतम रहती हैं और परियोजनाएं पूरी होने के पश्चात सृजित सम्पत्तियों की देखरेख व रख रखाव भी पंचायतें व व्यक्ति नहीं करते है, जिससे यह परिसम्पत्तियां शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। राज्य सरकार ने इस स्थिति को गम्भीरता से लिया है और निर्णय लिया है कि परियोजना का चयन आपूर्ति आधारित (Supply driven) ना होकर मांग आधारित (Demand Driven) होना चाहिए।

जिला परिषद द्वारा परियोजनाओं के चयन की प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी :-

1. जिला परिषद वर्ष के प्रारम्भ में ही सभी पंचायतें जहां Watershed Atlas, के अनुसार जलग्रहण परियोजनाएं चिन्हित है, से परियोजना आवंटन करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त करेगी। संबंधित पंचायत इस परिपत्र के साथ संलग्न परिशिष्ठ-1 अनुसार प्रस्ताव पारित करते हुए परियोजनाओं के आवंटन हेतु जिलों को आवेदन करेंगे। पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करने से पूर्व योजना क्षेत्र के काश्तकारों/लाभान्वितों से हरियाली गाईड लाईन के पैरा 36 अनुसार राशि वसूल कर जल ग्रहण विकास कोष में जमा करवाने हेतु लिखित सहमति (Undertaking) प्राप्त कर रिकार्ड में रखी जावेगी।

2. जिला परिषद द्वारा पंचायतों से उपरोक्त लिखित प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात ही आयुक्त जलग्रहण द्वारा पत्र क्रमांक एफ. 6 (12) आर.डी/एलआर/2/96/पार्ट-III/दिनांक 4.10.2006 (प्रतिलिपि संलग्न जारी) अंक आधारित प्रक्रिया अनुसार जल ग्रहण परियोजनाओं का आवंटन किया जाएगा।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद का उत्तरदायित्व होगा कि वह इन दिशा-निर्देशों की पालना करायेंगे। यदि कोई जिला परिषद इन निर्देशों के विपरीत कोई प्रस्ताव पारित करते है तो उसे निरस्त करने हेतु राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार को तत्काल भिजवाएंगे।

यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

ह./-

(राम लुभाया)

प्रमुख शासन सचिव

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
5. निजी सचिव, निदेशक : बंजड़ भूमि जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण राज., जयपुर
6. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (भू संसाधन), निदेशालय राज., जयपुर
7. मुख्य लेखाधिकारी निदेशालय, जयपुर
8. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान
9. संयुक्त निदेशक (प्रशासन)/एमओएपी/पीएफसी/एमआईईएस) निदेशालय जयपुर
10. संयुक्त निदेशक जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण जयपुर/अजमेर/कोटा/भीलवाड़ा/उदयपुर/जोधपुर
11. समस्त अधिशाषी अभियन्ता/परियोजना अधिकारी (भू संसाधन)/ जिला परिषद
12. उप निदेशक जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण डूंगरपुर/जोधपुर/उदयपुर
13. परियोजना अधिकारी (भू संसाधन) निदेशालय जयपुर
14. समस्त विकास अधिकारी पंचायत समिति ..... जिला .....
15. समस्त सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा विकास अधिकारी पं.स. .....

ह./-

प्रमुख शासन सचिव

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

राजस्थान सरकार

निदेशालय बंजर भूमि, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग

राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : प. 2 (140) आरडी/एलआर/2/2006 दिनांक : 23.03.2007

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद,
समस्त (श्रीगंगानगर के अतिरिक्त)

विषय : जलग्रहण विकास परियोजनाओं का परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी को आवंटन एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का अनुमोदन।

महोदय,

मरू विकास कार्यक्रम, सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम एवं एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में जलग्रहण परियोजनाओं की क्रियान्विति की जा रही है।

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का आवंटन जिला परिषद द्वारा परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी को किया जाता है। प्रायः यह देखा गया है कि परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी को परियोजना आवंटन करने में जिला परिषद द्वारा अत्यधिक विलम्ब किया जाता है (उदाहरणार्थ- झुन्झुनू, जैसलमेर, बाडमेर, पाली एवं नागौर) जिसके कारण कार्य शुरू कर पूर्ण करने में निर्धारित अवधि से अधिक समय लिया जाता है। इस कारण भारत सरकार से राशि प्राप्त करने में विलम्ब होता है तथा समय पर जनसमुदाय का अपेक्षित लाभ भी प्राप्त नहीं हो पाता है।

हरियाली मार्गदर्शिका के पैरा 9 में यह प्रावधान है कि ''जिला स्तर पर जिला परिषद/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, **राज्य सरकार** तथा भारत सरकार **के पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन के अन्तर्गत** सभी क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के लिए केन्द्रक (नॉडल) प्राधिकरण होगा। यह केन्द्रक प्राधिकरण जलसंग्रहण क्षेत्रों चयन, परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों की नियुक्ति को अनुमोदित करेगा तथा परियोजनाओं की कार्य योजना/विकास योजना आदि को भी अनुमोदित करेगा।''

अतः जिला स्तर पर हो रहे विलम्ब के कारण परियोजनाओं की क्रियान्विती समय पर सुनिश्चित करने हेतु निम्न निर्देश दिए जाते हैंः-

(I) अधिशाषी अभियंता विभागीय आदेश क्रमांक प. 2(104) ग्रावि/भू.सं./2/2006 दिनांक 1.5.2006 की अनुपालना में वाटरशेड एटलस एवं इन्डैक्स कैचमेन्ट और कलस्टर चयन हेतु विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ 18 (3) पीएफसी/डीडब्लुडब्लुडीसी/2006, दिनांक 21.4.2006 तथा हरियाली मार्गदर्शिका के पैरा 5 में अंकित प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट तैयार करेंगे।

(II) भारत सरकार से स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता के अनुसार परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी को जलग्रहण विकास परियोजनाओं के आवंटन हेतु अधिषाशी अभियन्ता (भू-संसाधन) द्वारा प्रस्ताव जिला परिषद को प्रस्तुत किए जावेंगे।

(III) जिला परिषद द्वारा भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्ति के पश्चात आयोजित प्रथम बैठक में परियोजनाओं का आवंटन परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी को किया जावे। यदि इस बैठक में परियोजनाओं का आवंटन नहीं किया जाता है तो प्राथमिकता सूची राज्य सरकार को प्रस्तुत की जावे ताकि स्वीकृति हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(IV) परियोजनाओं की तैयार की गई डीपीआर की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर अनुमोदन हेतु जिला परिषद को प्रस्तुत की जावे। इसके उपरान्त यदि जिला परिषद की प्रथम बैठक में जिला परिषद द्वारा डीपीआर का अनुमोदन बिना पर्याप्त कारण के नहीं किया जाता है तो डीपीआर को अनुमोदित मानते हुये इस आशय के आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद द्वारा जारी किए जावेंगे, तत्पश्चात कार्य प्रारम्भ कर दिए जावे और इसकी सूचना राज्य सरकार को भिजवाई जावे।

उपरोक्त आदेश की पालना सुनिश्चित की जावे।

ह./-

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. संयुक्त निदेशक, बंजर भूमि, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग, मुख्यालय/वृत।
2. संयुक्त निदेशक (एम.आई.ई.एस.), मुख्यालय।
3. परियोजना अधिकारी, (भू.सं.) समस्त (श्रीगंगानगर को छोड़कर)।

ह./-

उप सचिव (भू–सं.)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT & PANCHAYATI RAJ

(Land Resource Section)

Room No. 153, PANT KRISHI BHAWAN, JAIPUR

No. F. 2 (104)/RD/L.R./2/2007/Pt-II Jaipur, dt. 23.03.2007

CIRCULAR

In order to achieve the desired results from the Watershed Development Programme under the Integrated Watershed Development Programme (IWDP)/Desert Development Programme (DDP)/Drought Prone Area Development Programme (DPAP) and to ensure optimum utilization of fund and also to bring more transparency in implementation of the Watershed Development Programme, the matter of issuing integrated instruction for effective implementation, monitoring and guidance regarding this programme was under active consideration of the Government.

For the purpose of taking up actual physical works for development of natural resources under Watershed Development Programme that may prove beneficial to the rural community, the Govt. after careful consideration decides to issue following instructions :-

1. **Purpose of Watershed :** Watershed programme is intended to enhance and augment the capacity of natural resources in such a way that the natural resources can be utilized more effectively for improving the lives of rural community, specially the weaker section of society. Rural community is predominantly dependant on natural resources in their vicinity, Therefore, the linkage between the community and the natural resources should not be forgotten while planning and implementing the watershed programme. Thus, no such works need to be taken up which do not directly benefit the community.

2. **Need for Watershed :** With increasing pressure of population, natural resources have suffered and depleted. Forces of nature such as rain, wind, scarcity, floods and famine have further damaged the natural resources. This makes the available natural resources lesser and lesser productive over the years. The need for watershed has arisen so as to reverse this process of depletion so that the community resources such as land and water are able to serve the community in a much more effective manner. This means therefore, that watershed programme must lead to an increased agriculture and animal productivity resulting into higher income levels of the village community. Therefore, no such works need to be carried out which do not visibly lead to improved livelihood forthe community. This must be kept in view while planning new projects and reviewing ongoing projects.

3. **Need for more Tangible Works :** Under the Hariyali Guidelines, 85% of funds must be utilized for actual physical works. Therefore, there is a need to do more tangible works that can be verified in future and can sustain over a long period of time even after end of the project period.

4. With this objective in mind, it is decided that henceforth only following categories of works would be carried out in new projects :-

(a) Farm Ponds & Tankas should be constructed in the fields of only the BPL beneficiaries, Scheduled Castes, Scheduled Tribes or marginal and small farmers.

(b) New percolation tanks on community lands in the vicinity of the village. Deepening of existing talabs, nadis etc. shall not be allowed. The talabs/tanks must have pitching on sides.

(c) New check dams on nallas & ravines.

(d) Percolation tanks and other structures for re-charging of village wells/ground water. (New and semi semi pucca only).

(e) works purely of temporary nature such as pure earthwork, earthen bunds/kanabunding/medbundi etc. that are likely to be washed away in the rains, shall not be taken up at all. Instead of them, works for safe disposal of water, such as check dams, waste weirs or semi pucca bunds must be carried out to ensure that structures that are created are long lasting. In hilly terrains, contour trecnches, bench terraces, graded terraces (have gentle lateral slope with stone rubble or earthen bund with stone pitching at the end) gully plugs (Structures across small stream) contour bunds (narrow based embankment made of dry stone rubble or soil with pitching of stone) etc. of suitable specifications could be taken up to reduce the velocity of rain water flowing down the hill resulting in the deposition of silt load and permitting more infiltration of water, thus, creating micro environment for establishment of vegetative cover.

Violation of these guidelines shall be viewed seriously.

(f) Development of part of a pasture or a grass land in Government/community wasteland for more production of fodder should be taken up if the Gram Sabha passes a resolution to the effect that:-

(i) The Panchayat shall maintain the pasture after the project is over.

(ii) Open grazing in 50% of the pasture land must be totally banned and people will cut and carry grasses on payments of nominal fees to be determined by the Panchayat.

(g) General Plantation works on Government Wasteland/Gaucher or River Banks only if the planation is agreed to be maintained for a minimum period of 3 years by the Gram Panchayat or the Forest Deptt. Unless an effective arrangement is made for maintenance of planation in community lands/ river banks etc. they have very rare chance of survival. For this purpose, participatory forest management can also be arranged wherein, the Village Forest Protection and Management Committee (VFP & MC) is required to be registered with the Forest Department. The amount payable to a Van Rakshak as provided in the guidelines for protection of plantation may be paid to these beneficiary groups on the basis of the percentage of existing trees. Plantation of multipurpose trees in consultation with local people shall be undertaken by adopting the above mentioned arrangement.

(h) Construction of round tank (tanka) of 20000-40000 ltrs. capacity with suitable agore (catchment) for harvesting rain water giving full attention on stability of structure looking to the soil. These will be constructed first to benefit BPL, second small and marginal farmers of SC & ST and third small and marginal farmers of general category. Tank, hand pump, and overhead tank (may be PVC) for irrigating the planted seedlings through drip can also be considered.

(i) SHGs/Farmers need be motivated to raise Kisaan Nursery (25000 seedlings per farmer) by providing poly bags seeds and other inputs from the project fund, so that the right type of seedlings are available within the watershed. These can be given free of cost to BPL, small & marginal farmers for planting within the

watershed area. For horticulture plants, the assistance available under National Horticulture Mission could also be availed for dovetailing with the watershed project funds.

(j) In Southern Rajasthan, "Keshav Wadi" programme should be taken up wherein 30 fruit plants and 150 forest plants are planted and improved agriculture practices are adopted in the field of BPL, small and marginal SC/ST families. This should also be dovetailed with NREGS to have more area covered under the watershed.

(k) Mobilize minimum 50 of the farmers to adopt dry land farming practices and arid horticulture in the project area.

(l) Demonstration of Energy Conservation, Development of Non Conventional Sources of Energy, Bio Gas Plant, Micro Irrigation, Conservation of Roof Water (Rain Water) can be carried out at the Panchayat Ghar, Govt. School, at the residence of beneficiary members from BPL, SHGs of the SCs, STS.

(m) Any other work of even special merit shall not be taken up without prior approval of Director, WD &SC, If the Zila Parishad feels that works of some special nature are required to be carried out that may have direct area specific benefit, a proposal may be sent, It will be the policy of Directorate to generally agree to such proposals if the reasons are valid, If no decision is communicated within 30 days of sending the proposal. Zila Parishad governing body, can pass a resolution bringing out special merit of such works and go ahead with such works, and the same shall be deemed to have been approved.

(n) It may be noted that apart from the above works, no other works may be carried out in projects. However, the ongoing projects may continue as planned, but projects which have not yet started or are in the first year should be revised on the above lines and works be executed as per revised DPR. Above guidelines may be strictly followed and no works other than those mentioned above may be taken up in the future under new projects. All the above mentioned works for water conservation including land conservation and raising ground water table, shall be included in rational proportion. CEO, Zila Parishad shall ascertain this.

5. The actual physical work may be carried out by following agencies under overall supervision of the PIA :-

(a) Farm Ponds or Tanka - to be constructed by the beneficiary himself or by the SHG.

(b) Percolation Tank - Gram Panchayat/User Group.

(c) New Check Dam - Gram Panchayat/User Group.

(d) Structure for recharging of village wells/groundwater - individual beneficiary, SHG, USER Group, Gram Panchayat.

(e) Gaucher Development - SHG/User Group/Gram Panchayat/VFPMC.

(f) Development of kitchen garden/wadi scheme/nursery or vermi compost or medicinal and herbal plants or Jetropha - individual beneficiary/SHG.

(g) Jetropha cultivation on Govt. Wasteland Gaucher-Gram Panchayat or BPL SHG.

(h) General plantation work and fodder cultivation on Govt. Wasteland/Gaucher or river bank or ravines - Gram Panchayat/Forest Department/VFPMC or as may be decided by Zila Parishad.

(i) Works in respect of non conventional sources of energy, energy conservation and micro irrigation may be taken up for demonstration only for and by the BPL. SHG or the beneficiaries of SCs and STs.

6. Monitoring of Physical Works :

(a) Physical works shall be carried out by individual/group as mentioned above and the PIA shall monitor the works.

(b) Concurrent monitoring of the works undertaken by the PIA shall be done by the PO (LR) and their progress shall be reviewed monthly/quarterly/yearly.

(c) Concurrent monitoring of the works taken up for the watershed project under the Zila Parishad shall be carried out by the monitoring cell of the Directorate of WWD & SC.

7. Mode of implementation of works :

(a) Unless otherwise decided by Zila Parishad, Panchayat Samiti must be the PIA.

(b) For the works earmarked under treatment plan, the Gramin Karya Nirdeshika (GKN) must be followed for all purposes for making estimates, granting technical and administrative sanctions.

(c) Gram Panchayat should carry out the works with the assistance of WDT, keeping in view the above and Hariyali guidelines.

Sd/-

(Ram Lubhaya)

Principal Secretary (RD & PR)

Copy forwarded to the following for kind information-

1. SA to Hon'ble Minister RD & PR, GOR.
2. PS to Hon'ble State Minister RD & PR, GOR.
3. PS to Pr. Sec., RD & PR, GOR.
4. PS to Sec, PR, GOR.
5. PS to Sec., RD, GOR.

Copy forwarded to the following for Compliance-

6. Addl. Dir., WWDSC, Jaipur.
7. JD, WWDSC, Jaipur/Bhilwara/Kota/Udaipur/Jodhpur/Ajmer.
8. Joint Director, MOAP/Adm/PFC/MIES, DWWDSC, Jaipur.
9. Chief Executive Officer, Zila Parishad, All districts (except Sri Ganganagar).
10. XEn (L.R), Zila Parishad, All districts (except Sri Ganganagar).
11. BDO, All Panchayat samities (except of Sri Ganganager).

Sd/-

Dy. Sec. (LR)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT

(Land Resources Section)

No. F 2 (140) RD/LR/2/06 Jaipur, Dated : 29.03.2007.

Executive Engineer (Land Resource),
Zila Parishad,
All (except Sriganganagar).

Subject : Preparation of Detailed Project Report (DPR's).

Sir,

Watershed projects are being implemented under Desert Development Programme (DDP), Drought Prone Area Programme (DPAP) and Integrated Wasteland Development Programme (IWDP). Sanctioned projects are required to be completed in stipulated time which is 5 years from the date of sanction.

It is mandatory for each Project Implementing Agency (PIA) to get prepared a Watershed Development Plan, Commonly known as Detailed Project Report (DPR) which is the basis for release of funds monitoring, review, evaluation etc. by ZP/State Government/Government of India.

It is, therefore, necessary that DPR shall address baseline data and expected level of achievement against each activity that has been included so that impact assessment could be done at the time of final evaluation.

Baseline data for each sanctioned project must contain :

- Existing cropping pattern in Rabi & Kharif.
- Agriculture production per unit area for every crop.
- Existing level of water table.
- Condition of Village tanks, how long water remains.
- Soil health.
- Present status of AI among animals.
- Production of grass on pasture land.
- Number of available trees in Pastures & Revenue waste lands.
- Status of migration : (a) Cattle (b) People
- Condition of existing common property resources : Prevailing management system, self sufficiency, shortage, how met.
- Status of Fodder.
- Status of Fuelwood self sufficiency, shortage, how met.
- Number of existing Self Help Groups linked with bank credit.

a) Inactive

b) active : (i) activity
(ii) linked with bank credit.

- Other baseline data deemed necessary may be incorporated

DPR shall indicate the interventions & action plan as to what extent achievement would be made after completing project activities in comparison to baseline data.

Further, DPR should specify :

(i) Pre-set deliverable output
(ii) Elaborate road map with definite milestones
(iii) Definite time frame for each activity
(iv) Technology interventions
(v) Clear exit protocol
(vi) Convergence of other programmes.
(vii) Use of WDF

Performance of the project shall be assessed by comparing achievement made with respect to baseline data. It is necessary that, recording of baseline data be made carefully so as to ascertain impact of the project interventions correctly.

Yours faithfully

Sd/-
Dy. Secretary (LR)

Copy for information and necessary action to :

1. Chief Accounts Officer, WWDSC HQ.
2. Joint Director, MOAP/Administration/MIES/PFC.
3. Joint Director, WWDSC Jaipur/Jodhpur/Ajmer/Kota/Udaipur/Bhilwara Circle.

Sd/-
Project Officer (LR)

E-mail

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

RURAL DEVELOPMENT & PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

No. PS/RD & PR/2007 Dated : 11th April, 2007

Chief Executive Officer,
All Zila Parishad,
All Rajasthan (except Ganganagar).

Sub : Criteria for inter ranking of districts for performance in Watershed Projects.

Sir,

This is being widely believed that the watershed projects have largely failed to meet the objective of increased agriculture productivity. A number of studies have shown that the processes as laid down in the guidelines were not effectively followed that resulted into the improved outcomes.

In order to have the improved outcomes of watershed projects, it is very necessary that the projects are timely started, completed, the works are of quality and there is a full people's participation. While final outcome will be judged during the interim and final evaluation and in order to closely monitor the processes of implementation, a score based performance has been evolved as under :

S.No.	Activity	No. Awarded
1.	% expenditure as against target	20
2.	% sanctioned projects on which work started after approval of DPR by Zila Parishad	15
3.	% claims lodged with MoRD against instalment due :	
	(i) For 2nd instalment	3
	(ii) For 4th instalment	3
	(iii) Others	9
4.	% inspection carried out as against norms	15
5.	% achievement of targets of WHS	15
6.	% WDT's fully constituted and functional	10
7.	% advance DPR's prepared as against targets (Shelf of Projects)	5
8.	% funds released to PIA's within 15 days of receipt	5
Total	100	

On this criteria, every month each district will be evaluated and inter ranking of the districts will be conveyed to you with the objective of creating in district competition for improving the performance.

Yours faithfully,

Sd/-
(Ram Lubhaya)
Pr. Secretary to Government

Copy for information and necessary action to :

1. PS to Pr. Secretary, RD & PR.
2. Secretary, Panchayati Raj.
3. Secretary, Rural Development.
4. Director, WD & SC.
5. Dy. Secretary (LR).
6. Addl. Director, WD & SC.
7. Jt. Director, WD & SC Circle .....
8. Jt. Director, MIES (HQ) with the remark that inter ranking of districts for the month of April, 2007 (to be issued in May, 2007) shall be prepared on the basis of criteria explained above. The data base of the software of Carisma should be so prepared that the outputs indicated above are delivered. JD (MIES) in consultation with DS (LR) will ensure it so that AEN's/Others working on software could take care of this.

Sd/-
Pr. Secretary to Government

प्रबोधन, सूचना एवं मूल्यांकन पद्धति

राजस्थान सरकार

बंजड़ भूमि, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 4(20)पार्ट -थर्ड/बं.भू.ज.भू.सं./एम.आई.ई.एस./05-06/6746-820 दिनांक 10.3.2006

1 संयुक्त निदेशक,
बंजड़ भूमि, ज.ग्र.वि. एवं भू संरक्षण,
वृत जयपुर/अजमेर/उदयपुर/भीलवाड़ा/कोटा/जोधपुर।

2 मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, ...

विषयः–विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वाटरशेड की मासिक/त्रैमासिक प्रगति प्रेषित करने के संबंध में।

यह ध्यान में लाया गया है कि वर्तमान में संयुक्त निदेशकों (वृत) द्वारा वाटरशेड की विभिन्न योजनाओं की मासिक/त्रैमासिक प्रगति, आयुक्तालय के विभिन्न प्रकोष्ठ जैसे एन.डब्ल्यू.डी.पी./आर.डी./लेखा/प्रशासन/सामु. संगठन/प्रशिक्षण को प्रेषित की जा रही है। इसी तरह जिला परिषदों द्वारा आर.डी. योजना की प्रगति सीधे उप सचिव (भू-संसाधन)को प्रेषित की जाती है। अब यह प्रक्रिया तुरन्त प्रभाव से समाप्त की जाती है। आगे से यह प्रगति आयुक्तालय के विभिन्न प्रकोष्ठों अथवा उप सचिव (भू-संसाधन) (जोकि अब आयुक्तालय में स्थानान्तरित हो चुका है) को प्रेषित नहीं की जावेगी।

मासिक प्रगति के संबंध में आयुक्तालय के अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक एफ 4(20)।/एम.आई.ई.एस./05-06/6450-558 दिनांक 01.03.2006 द्वारा वृत कार्यालय एवं जिला परिषदों/पी.ओ.(एल.आर.) को मासिक प्रगति हेतु 7 प्रपत्र प्रेषित किए गए है। इन्हीं प्रपत्रों में एकजाई मासिक प्रगति प्रत्येक माह की 7 तारीख तक आयुक्तालय के सिर्फ एम.आई.ई.एस. प्रकोष्ठ को मय फ्लोपी के प्रेषित की जावेगी। यह प्रकाष्ठ इसे इकजाई कर विभिन्न प्रकोष्ठों/राज्य सरकार को प्रेषित करेगा।

संयुक्त निदेशकों द्वारा अन्य किसी प्रकोष्ठ को अथवा जिला परिषदों द्वारा उप सचिव(भू-संसाधन) को अलग से कोई मासिक प्रगति प्रेषित नहीं की जावेगी। यदि इन आदेशों की पालना नहीं की जाती है, तो संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

इसी तरह उपरोक्त पत्र द्वारा त्रैमासिक प्रगति के 6 प्रपत्र भी प्रेषित किए गए है। इन प्रपत्रों में प्रत्येक त्रैमास की प्रगति निम्न प्रकार एम.आई.ई.एस. प्रकोष्ठ को प्रेषित की जावेगी :-

प्रथम त्रैमास	7 जुलाई
द्वितीय त्रैमास	7 अक्टूबर
तृतीय त्रैमास	7 जनवरी
चतुर्थ त्रैमास	7अप्रेल

यह भी निर्णय लिया गया कि तुरन्त प्रभाव से मासिक एवं त्रैमासिक प्रगति उपरोक्तानुसार, संयुक्त निदेशकों (वृत) द्वारा प्रेषित नहीं की जाकर सीधे जिला परिषदों द्वारा आयुक्तालय को प्रेषित की जावेगी, जिसकी प्रति संबंधित संयुक्त निदेशकों (वृत) को दी जावेगीताकि वे भी उनके स्तर पर आवश्यक मोनीटरिंग कर सकें।

मासिक/त्रैमासिक प्रगति के प्रपत्र पुनः पत्र के साथ संलग्न किए जा रहे हैं।

ह./-

आयुक्त

क्रमांक एफ 4(20)पार्ट -थर्ड/बं.भू.ज.भू.सं./एम.आई.ई.एस./05-06/6746-820 दिनांक 10.3.2006

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप सचिव (भू-संसाधन), आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक (प्रथम/द्वितीय), आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक (प्रशासन/एम.ओ.ए.पी./एम.ओ.आर.डी./पी.एफ.सी.) को भेजकर लेख है, कि फरवरी, 2006 की उनकी शाखा में प्राप्त प्रगति एम.आई.ई.एस. शाखा को प्रेषित करें, ताकि एकजाई की जा सके।
4. परियोजना अधिकारी (भू-संसाधन), जिला परिषद, ... को भेजकर निर्देश दिये जाते है कि मासिक एवं त्रैमासिक प्रगति व्यक्तिगत तौर पर उपरोक्तानुसार प्रेषित करवाना सुनिश्चित करावें।

ह./-

आयुक्त

Wasteland, Watershed Development and Soil Conservation Department
Rajasthan, Jaipur
District progress Card

District : **Month :**

I Scheme wise status of Financial & Physical Progress : (up to)

S. No.	Name of Scheme	Financial (Rs. in lacs)			Physical (Area in Ha)		
		Annual Target	Achi.	%Achi.	Annual Target (Area)	Achi.	%Achi.
1	DDP						
2	CDP						
3	DPAP						
4	IWDP						
5	NWDPRA						
	Total :						

II Status of Component-wise Financial Progress :-

Scheme	Adm. Overhead			Comm. Org.			Training			Dev. Works						
	Target	Achi.	%	Target	Achi.	%	Target	Achi.	%	Target	Achi.	%		Target	Achi.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	DDP															
2	CDP															
3	DPAP															
4	IWDP															
										NRM			Farm Prod. Management	Livelihood support		
5	NWDPRA															
	Total :															

III Physical Progress :

(a) SHG

S.No.	Name of Scheme	Total W/S	Targets	SHG Progress				
				Total W/S in which SHGs formed	total No. of SHGs formed	No. of total members	Total amt. savings / thrift (lac)	Total amt. Provided from project as Rev. fund (lac)
1	DDP							
2	DPAP							
3	IWDP							
4	NWDPRA							
	Total :							

(b) Training DISTRICT :

S. No.	Name of Scheme	Total W/S	Training Progress (Physical)									
			Trg. of trainers		Trg. Of WC/UC members		Farmers & commu.Org.		Edu. Tours		SHG Trg.	
			Target	Achi.	Target	Achi.	Target	Achi.	Target	Achi.	Target	Achi.
1	DDP											
2	CDP											
3	DPAP											
4	IWDP											
5	NWDPRA											
	Total :											

(c) Pasture Development

Area (in Ha.)	DDP		DPAP		IWDP		NWDPRA		Total	
	Target	Achi.	Target	Achi.	Target	Achi.	Target	Achi.	Target	Achi.

D) Plantation

S. No.	Name of Scheme	Agro Forestry			Horticulture Plants			Afforestation on common lands		
		No. of Plants		% of Survival	No. of Plants		% of Survival	No. of Plants		% of Survival
		Target	Achi.		Target	Achi.		Target	Achi.	
1	DDP									
2	CDP									
3	DPAP									
4	IWDP									
5	NWDPRA									
	Total :									

(E) Water Harvesting Structures

S. No.	Name of Scheme	Pucca (No.)		Others (No.)	
		Target	Achi.	Target	Achi.
1	DDP				
2	DPAP				
3	IWDP				
4	NWDPRA				
	Total :				

(F) Livestock Development : District :

S. No.	Name of Scheme	Helth Coverage (No. of Animals)		AI (No.)	
		Target	Achi.	Target	Achi.
1	DDP				
2	DPAP				
3	IWDP				
4	NWDPRA				
	Total :				

IV Status of Disputed W/S

S. No.	Name of Scheme	Total No. of Disputed W/S		No. of W/S activated				
				Upto the month		During the month		Total
1	DDP							
2	CDP							
3	DPAP							
4	IWDP							
5	NWDPRA							
	Total :							

V Other important issues :

(a) CM Office References : ------Nos.

(b) Complaints received from MPs/ MLAs/ Ministers : ------Nos.

(c) AG paras are still pending for disposal : ------Nos.

(d) Projects in time over-run

S. No.	Scheme	No. of Projects in Progress		No. of Projects in time Over-run		Details of Districts	
1	DDP						
2	CDP						
3	DPAP						
4	IWDP						
5	NWDPRA						

(e) Status of timely lodging of claims for reiease of instalment from GOI :

S. No.	Scheme	Year of Sanction		No. of Instalments to have been claimed			No. of instalments actually claimed	
1	DDP							
2	CDP							
3	DPAP							
4	IWDP							
5	NWDPRA							

(f) Compliance of norms for inspection :

	Officer/ Officials	Norms of Inspection	No. of Inspections done
1	CEO		
2	PO (LR)		
3	AEn		
4	JEn		

(g) Disposal of Complaints:

S. No.	From whom received	Dt. Of receitpt	Dt. Of disposal	Reasons, if pending
1				
2				
3				
4				

WASTELAND, WATERSHED DEVELOPMENT AND SOIL CONSERVATION DEPARTMENT, RAJASTHAN

District & Scheme wise status of Financial & Physical for the year 2005-06

Month : **District :**

Scheme	Financial (Rs. in lacs)		Physical (Area in Ha)		Remarks
	Annual Target	Achi. Upto the month Actual	Annual Target	Achi. Upto the month	
1	2	3	4	5	6
(I) NWDPRA					
(A) State Plan Part					
Non TSP Area					
TSP Area					
Total (A)					
(B) CSS Part					
Non TSP Area					
TSP Area					
Total (B)					
Total (I)					
(II) RD Schemes					
DDP (Including CDP)					
DPAP					
IWDP					
Sub-Total (RDS)					
Other RD Schemes :					
(i) Bisalpur Project					
(ii) TADA					
(iii) SGRY					
(iv)					
Sub-Total (Others)					
Total (II)					
Total (I+II)					

Revised MIES Performa for NWDPRA Monitoring

Name of the District : **Total Pilot W/S :** **Total Tenth FYP W/S :** **Total NWDPRA W/s :**

Month :

(On Monthly basis)

S. No.	Componets / Activities	Unit	For Pilot W/S				For Tenth FYP W/S				Total NWDPRA W/S			
			Physical		Financial		Physical		Financial		Physical		Financial	
			Target 05-06	Ach. Upto Month	Target 05-06	Ach. Upto Month	Target 05-06	Ach. Upto Month	Target 05-06	Ach. Upto Month	Target 05-06	Ach. Upto Month	Target 05-06	Ach. Upto Month
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A.	**Management Component**													
I	***Administration***													
	(a) State GQ.													
	(b) Distt. HQ.													
	(c) PIA													
	- Salary / Honorarium	Rs.												
	- Other Expenses													
	Sub Total (PIA)													
	(d) W/S Committees													
	- Salary / Honorarium	Rs.												
	- Other Expenses													
	Sub Total (WC)													
	Sub Total (Admn. Cost)													
II	***Community Organisation***													
	(a) Entry point Activities of WC	No.												
	(b) Honorarium to village based Com. Organizer	No.												
	(c) Registration of WA.	No.												
	(d) Expanses at Distt HQ for Misc.													
	(e) corpus for WDF	Rs.												
	(f) Awareness Camps	No.												
	(g) Medical Camps	No.												
	(h) Animal Health Camps	No.												
	(i) Eye Camps	No.												
	(j) Literacy Camps	No.												
	(k) Padyatra	No.												
	(l) Publicity													
	(m) No. of Users Groups formed / operational	No.												
	(n) Self Help Groups (SHG)													
	(i) Total no. of SHG formed	No.												
	(ii) Total No. of SHGs functional	No.												

	(iii) SHGs Availed Revolving Fund from	No./Rs.
	NWDPRA	
	(iv) No. of SHG in volved in income generation	No.
	(v) Amt. Deposited as Savings with SHGs	Rs.
	Sub Total (Community Org.)	
III	***Training Programme***	
	@ State Level	
	(a) Trainigs	No.
	(b) Orientation	No.
	(c) Skill enhancement	No.
	(d) Publication	
	(e) Exposure Visits	No.
	(f) Others Specify	
	@ Distt Level	
	(a) Trainigs	No.
	(b) Orientation	No.
	(c) Skill enhancement	No.
	(d) Publication	
	(e) Exposure Visits	No.
	(f) Topographical survey	Ha.
	(g) Evaluation Studies	No.
	(h) Others specify	
	@ PIA Level	
	(a) Training at Unit / WS	No.
(i)	Trg. to WDT Members	No.
	(ii) Trg. to SHG Members	No.
	(iii) Trg. to Users Groups	No.
	(iv) Trg. To WC / WA Secys. (v) Trg. to watershed community	No. No.
	(b) Exposure Visits	
	(c) Others specify	
	Sub Total (Training)	
	Total of Management Component (I+II+III)	
B.	**DEVELOPMENT COMPONENT**	
I	***Natural Resource Management***	
	(a) Arable land	
	- soil & moisture cons. activities	
	(a) Contour Bunding	Ha
	(b) Terracing	Ha

	(c) Filter Strips	
	(d) Gully Control Structures	No.
	(e) Ohters	
	- Agronomic cons. Practices	
	- Other	Ha
	Sub Total (Arable Land)	
	(b) Non Arable	
	- Runoff management structures	No
	- Water Harvesting Structures	No
	(i) Check Dams	
	(ii) Anicurs	
	(iii) Khadins	
	(iv) Nadis	
	(v) Others	
	- Gully Control Structures	
	- Dryland Horticulture	No
	- Conservation and Development of Biomass	Ha
	- Fencing	Rmt
	- V-Ditches	Ha
	- Overseding	Ha
	- Plantation	No
	- Staggered Trenches	Ha
	- Others (Plantation)	
	Sub Total (Non Arable)	
	(c) Drainage lines	
	- Upper reaches	No
	- Middle Reaches	No
	- Lower Reaches	No
	Sub Total (Drainage Line)	
	Sub Total of NRM	
II	***Farm Production System land owning Families***	
	(a) Establishment of nurseries & Production of Seedlings :	No
	(b) Testing and demo. of new technology	No

	(I)	
	(II)	
	(d) Diversification of production system (Agro Forestry + Horticulture + Household system in Arable land)	No
	(I)	
	(II)	
	(d) Adoption of proven techology	No
	(I) (II)	
	(e) Livestock Management	No
	(f) Others	No
	Sub Total FPS	
III	***Livelihood Support System for landless families***	
	(a) Household production system	No
	(b) Biomass based rural industry	No
	(c) Dairy, Sericulture etc.	No
	(d) Livestock management	No
	(e) Others	No
	Sub Total for LSS	
	Total of Development Component (I+II+III)	
	Grand Total A+B	
	Mandays Generated	
	Area Treated	**Ha**
	Actual Expenditure	**Rs.**

FINANCIAL PROGRESS DURING THE YEAR .....

Name of Scheme : DDP/CDP/DPAP

Name of Zila Parishad .....

(Upto the month .....

S. No.	Sanctioned by Govt. of India	Projects alloted by GOI (Col. 7/4)		Amount received since inception upto the month			% of amount receuved		Expenditure		% of Exp. (Col. 11+4)	Remarks, if any
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	W/s Projects (1995-96) Batch-I											
2.	W/s Projects (1999-2000) Batch-V											
3.	W/s Projects (2000-2001) Batch-VI											
4.	W/s Projects (2001-2002) Batch-VII											
5.	W/s Projects (2002-2003) Batch-VIII											
6.	W/s Projects (2003-2004) Hariyali-I											
7.	W/s Projects (2004-2005) Hariyali-II											
8.	W/s Projects (2005-2006) Hariyali											
	Total :											

Signature
X.En. (LR) (Zila Parishad)

Signature
C.E.O. (Zila Parishad)

Financial progress during the year .....

Name of Scheme : DDP/CDP/DPAP

Name of Zila Parishad .....

(Upto the month .....

S. No.	Sanctioned by Govt. of India												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	W/s Projects (1995-96) Batch-I												
2.	W/s Projects (1999-2000) Batch-V												
3.	W/s Projects (2000-2001) Batch-VI												
4.	W/s Projects (2001-2002) Batch-VII												
5.	W/s Projects (2002-2003) Batch-VIII												
6.	W/s Projects (2003-2004) Hariyali-I												
7.	W/s Projects (2004-2005) Hariyali-II												
8.	W/s Projects (2005-2006) Hariyali-III												
	Total :												

Signature
X.En. (LR) (Zila Parishad)

Signature
C.E.O. (Zila Parishad)

Monthly Progress of IWDP

(Upto the month _____)

1. Name of Zila Parishad
2. Name of Watershed/Project
3. Block
4. Period of Project
5. Total sanctioned cost (Rs. in lacs)
6. Total area to be treated (Ha)

Progress of project since inception upto current month

Year	Amount Received			Expenditure	Area teated (Ha)	Audited balance at the end of year
	Central Share	State Share	Total			
1999-2000						
2000-2001						
2001-2002						
2002-2003						
2003-2004						
2004-2005						
2005-2006						
Total :						

Description of next due Installment

7. Time & No	Dt. Of submission of proposal to GOI	Amt. of due installment	Whether Mid Evaluation before due installment is to be done (Yes/No)

Monthly Progess Report of RD Watersheds Programme for the year 2005-06

Name of Scheme : DDP/CDP/DPAP/IWDP/Other Scheme (Phase - wise & consolidated of the District)

Name ot District : _____ Total No. of W/s (Phase wise) : _____

Upto the Month : _____

S. No.	Particulars	Allocation		Achievement since Inception	
		Physical	Financial	Physical	Financial
		(A)			
1.	**Adminstrative Charges**				
	a. Zila parishad level				
	b. PIA level				
	c. Village level				
	Total (1) :				
2.	**Community Organisation**				
	a. Awareness camps (No.'s)				
	b. Medical Camps (No's)				
	c. animal Health Camps (No's)				
	d. Eye Camps (No's)				
	e. Literacy Camps (No's)				
	f. Padyatra (No's)				
	g. Publicity (No's)				
	h. Others (Specify) (No's)				
3.	**Self Helf Groups**				
	a. SHG formed (No's)				
	b. Groups functional (No's)				
	c. Groups availed revolving fund (No's)				
	d. Groups involved in income generation (No's)				
	e. Amount deposited as saving with SHG (Rs.)				
	f. Amount provided from revolving fund of RD W/s (Rs.)				
	Total (3) :				
4.	**Training**				
	a. WDT members (No's)				
	b. SHG members (No's)				
	c. Users Groups (No's)				

Monthly Progess Report of RD Watersheds Programme for the year 2005-06

Name of Scheme : DDP/CDP/DPAP/IWDP/Other Scheme (Phase - wise & consolidated of the District)

Name ot District : _____ Total No. of W/s (Phase wise) : _____

Upto the Month : _____

S. No.	Particulars	Allocation		Achievement since Inception	
		Physical	Financial	Physical	Financial
d.	WC/WA/GP/Volunteer/Vanrekshak/ Secretary (No's)				
e.	Watershed community (No's)				
f.	Field visit to successful watersheds (No's)				
g.	District & block level W/s functionaries/ representatives (No's)				
	Total (4) :				
5.	**Treatment Identified**				
a.	Agriculture land (Ha)				
b.	Afforestation (Ha)				
c.	Pasture Development (Ha)				
d.	Horticulture Development (Ha)				
e.	Agro forestry (No's)				
f.	Nursery development (No's)				
g.	Crop/fodder demonstrations (No)				
	Total (5) :				
6.	**Area Treated**				
a.	Govt. land (Ha)				
(i)	Contour trench (Ha)				
(ii)	Stragerred trench (Ha)				
(iii)	Gully control structures (No)				
(iv)	Earthen structures (No)				
(v)	Diversion channel (Rmt)				
(vi)	Vegetative filter Strip (Rmt)				
(vii)	Others, (Specify)				
b.	Community/Panchayat land (Ha)				
(i)	Fencing (Rmt).				
(ii)	Contour trench (Ha)				

Monthly Progess Report of RD Watersheds Programme for the year 2005-06

Name of Scheme : DDP/CDP/DPAP/IWDP/Other Scheme (Phase - wise & consolidated of the District)

Name ot District : _____ Total No. of W/s (Phase wise) : _____

Upto the Month : _____

S. No.	Particulars	Allocation		Achievement since Inception	
		Physical	Financial	Physical	Financial
	(iii) Stragerred trench (Ha)				
	(iv) Gully control structures (No)				
	(v) Earthen structures (no)				
	(vi) Overseeding (Ha)				
	(vii) Plantation in PD area (No)				
	(viii) Others, (Specify)				
	c. Forest land (Ha)				
	i) Contour trench (Ha)				
	(ii) Stragerred trench (Ha)				
	(iii) Gully control structures (No)				
	(iv) Earthen structures (No)				
	(v) Diversion channel (Rmt)				
	(vi) Vegetative filter Strip (Rmt)				
	(vii) Others, (Specify)				
	d. Private land (Ha)				
	(i) Contour bunding (Ha)				
	(ii) Terracing (Ha)				
	(iii) Filter strip (Rmt)				
	(iv) Gully control (No)				
	(v) Others, (Specify)				
	Total (6) :				
7.	**Water Harvesting Structures**				
	a. Check dams (No's)				
	b. Anicuts (No's)				
	c. Khadins (No's)				
	d. Nadi (No's)				
	e. Others (Specify names) (No's)				
	Total (7) :				

Monthly Progess Report of RD Watersheds Programme for the year 2005-06

Name of Scheme : DDP/CDP/DPAP/IWDP/Other Scheme (Phase - wise & consolidated of the District)

Name ot District : _____ Total No. of W/s (Phase wise) : _____

Upto the Month : _____

S. No.	Particulars	Allocation		Achievement since Inception	
		Physical	Financial	Physical	Financial
8.	**Livestock Development**				
	a. Artificial incemination (No's)				
	b. Castration (No's)				
	c. Vaccination (No's)				
	d. Health coverage (No's)				
	Total (8) :				
	Grand Total (A) :				

(B)

1.	Project sanctioned (No's)	
2.	DPR's approved (No's)	
3.	Meetings of the WC/GP (No's)	
4.	Gerenral body meeting of the W/s memebers (WA) (No's)	
5.	Mandays generated (No's)	
6.	Submission of UC's	

Signature of CEO Zila Parishad **Signature of X.En. (LR)**

बजट मद ..... (आयोजना / गैर आयोजना)

कार्यालय का नाम .....

मासिक व्यय विवरण माह .....

क्र. सं.	बिल संख्या व दिनांक	आहरण दिनांक	संवेतन	यात्रा व्यय	चिकित्सा	कार्या. व्यय	वाहन संधा.	वाहन किराया	भवन किराया	स्टेशनरी	प्रिंटिंग	संविदा	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
योग वर्तमान माह का व्यय :														
गत माह तक व्यय :														
अब तक कुल व्यय :														
बजट आवंटन :														

नोट : आयोजना एवं गैर आयोजना मद की सूचना पृथक-पृथक दी जानी है।

आहरण वितरण अधिकारी

जलग्रहण विकास कार्यक्रमों अन्तर्गत योजनावार लाभान्वित परिवारों की त्रैमासिक सूचना हेतु निर्धारित प्रपत्र

जिले का नाम ..... माह ..... तक

योजना का नाम	लाभान्वित परिवारों की मासिक प्रगति								
	लाभान्वित परिवारों की संख्या			उपचारित किया गया क्षेत्र (क्षेत्रफल हैक्टर में)			व्यय की गई राशि (रु. लाखों में)		
	कुल (अ.जा.+ अ.ज.जा.+अ.पि. वर्ग + सा. वर्ग)	अनु. जाति.	अनु. ज. जाति	कुल (अ.जा.+ अ.ज.जा.+अ.पि. वर्ग + सा. वर्ग)	अनु. जाति.	अनु. ज. जाति	कुल (अ.जा.+ अ.ज.जा.+अ.पि. वर्ग + सा. वर्ग)	अनु. जाति.	अनु. ज. जाति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.रा.ज.ग्र.वि.परि.									
2.डी.डी.पी. (मय सीडीपी)									
3.डी.पी.ए.पी.									
4.आई.डब्ल्यू. डी. पी.									
5.बीसलपुर परि.									
6.स्वर्ण जयंती ग्रा. रोजगार योजना									
7.टाडा									
महायोग :–									

QUARTERLY PROGRESS REPORT OF PHYSICAL ACHIEVEMENTS STATE/DISTRICT WISE

PHYSICAL PROGRESS OF WATERSHED PROJECTS TAKEN UP UNDER DDP/ DPAP DURING ___________

STATE _________________ DISTRICT ___________________ YEAR ______________ QUARTER ENDING _____________

(Area in Ha.)

S.No.	Name of District	No. of Blocks under DDP/ DPAP	Total No. of Projects		Area of Projects				Area Treated under								
			Target	Taken up	Total	Indentified for development			Land Resources Development			Water Resources Development			Afforestation &Pasture Dev.		
						Private land	Public land	Total	Upto previous Otr.	During the Qtr.	Total	Upto previous Otr.	During the Qtr.	Total	Upto previous Otr.	During the Qtr.	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

QUARTERLY PROGRESS REPORT OF PHYSICAL ACHIEVEMENTS STATE/DISTRICT WISE

PHYSICAL PROGRESS OF WATERSHED PROJECTS TAKEN UP UNDER DDP/ DPAP DURING ___________

STATE _________________ DISTRICT ___________________ YEAR ______________ QUARTER ENDING _____________

(Area in Ha.)

S. No.	Name of District	Area completely developed out of the area mentioned under Col. 17	Total employment generated in mandays			Total Area Treated				Area of private land treated belonging to							
			Upto previous Otr.	During the Qtr.	Total	Public Land	Private Land		Total	SC	ST	Women	Handicap	OBC	Minorities	Others	Total
							Marginal & small farmers	Big farmers									
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		34

QUARTERLY PROGRESS REPORT OF PHYSICAL ACHIEVEMENTS STATE/DISTRICT WISE

PHYSICAL PROGRESS OF WATERSHED PROJECTS TAKEN UP UNDER DDP/ DPAP PROGRAMME

STATE _____DISTRICT _____ YEAR _____QUARTER ENDING _____

(Rs. in Lacs)

Name of District	Opening balance as on 1 st Apri	Allocation	Releases to DRDA's							Shortfall in Release to DRDA's	Expenditure on					
			Central Share			State Share			Total release to DRDA							
			1st Install.	2nd Install.	Total	1st Install.	2nd Install.	Total			Upto previous Qtr.	During the Qtr.	Total	Upto previous Qtr.	During the Qtr.	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

QUARTERLY PROGRESS REPORT OF PHYSICAL ACHIEVEMENTS STATE/DISTRICT WISE

PHYSICAL PROGRESS OF WATERSHED PROJECTS TAKEN UP UNDER DDP/ DPAP PROGRAMME

STATE ________________DISTRICT __________________ YEAR _____________QUARTER ENDING ____________

(Rs. in Lacs)

Name of District	Expenditure on												Total of Columns from 12 to 29	% Exp. Against allocation	% Exp. Against available funds
	Establishment of PIA's & WC's			Entry Point Works			Area Development Works			Non Farm activities of SHG's					
	Upto previous Qtr.	During the Qtr.	Total	Upto previous Qtr.	During the Qtr.	Total	Upto previous Qtr.	During the Qtr.	Total	Upto previous Qtr.	During the Qtr.	Total			
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

QUARTERLY FINANCIAL PROGRESS REPORT FOR INTEGRATED WASTELANDS DEVELOPMENT PROJECT

NAME OF THE PROJECT _____ STATE _____ FUNDS RELEASED _____ PHYSICAL TARGET _____

COST _____ DISTRICT _____ TOTAL INTT. ACCURED _____

BLOCK _____ TOTAL EXPENDITURE _____

BALANCE _____

PROJECT PERIOD _____

For the Quarter _____

S.No.	Name of the Activity	Financial													
		Approved target up to the year	Receipt upto pre. year	Receipt during the year	Total receipt (4)+(5)=6	Total interest accured	Total funds available (6)+(7)+8	Exp. Upto pre.year	Exp. Pre. Upto pre. Qtr.	Exp. During the Qtr.	Total Exp. (10)+(11) =12	Cumulative Exp. (9)+(12)=13	Net balance (8)(13)=14	% Utilisation (!3)/(8)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**Survey and Planning**														
	Fin. Asstt. Given to														
I.	SHG														
II.	Entry Point Activities (No's)														
	Sub Total :														
2.	**Training**														
I.	SHG (No's)														
II.	UG (No's)														
III.	WA's (No's)														
IV	Others (No's)														
	Sub Total :														
3.	**Community Organisation**														
I.	Camps (No's)														
II.	Seminar & Workshop etc.														
	Sub Total :														
4.	**Work Components**														
I.	**Soil & Moist. Cons.Works**														
	Works														
	a Contour Vegetative Hedgs (Rmt)														
	b Contour Bunding (Rmt)														

	c Waste Weirs (No's)
II.	**Water Harvesting Structure**
	a Nallah Bandh (CMT)
	b Check Dam (CMT)
	c Retaining Wall (CMT)
	d Anicut (No's)
	e Well & Water Tank
	f Deepening & Repairing of Ponds (Existing)
	(i) Big size (No's)
	(ii) Mid size (No's)
	(iii) Small size (No's)
	q New Ponds (No's)
III.	**Afforestation Works**
	a Private Agri, Land (Ha)
	b Community Land (Ha)
IV.	**Pasture Development**
	a Private Agri, Land (Ha)
	b Community Land (Ha)
V.	**Horticulture Development**
	a Private Agri, Land (Ha)
	b Community Land (Ha)
	Sub Total (Ha) :
5.	**Administrative Overhead**
	Sub Total :
	Grand Total :

Conribution to Watershed
Dev. fund

QUARTERLY PHYSICAL PROGRESS REPORT FOR INTEGRATED WASTELAND DEVELOPMENT PROJECT

NAME OF THE PROJECT _____ STATE _____ TOTAL PHYSICAL TARGET _____ AREA

DISTRICT _____ TOTAL AREA TREATED _____ I. Private agri. Land

BLOCK _____ PROJECT DURATION _____ II. Forest Land

DATE OF FORMATION OF WDT _____ III. Commo Land

For the Quarter _____ TOTAL MANDAYS GERERATED _____ IV. Others

S.No	Name of the Activity	Physical									Remarks
		Target			Acheivement						
		Upto pre. Year	or the Year	Cumulative (3)+(4)=5	Upto pre. Year	Upto pre. Quarter	During the Quarter	Total for the year	Cum. Ach. (6)+(9)=10	% Achi. (10/%)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

1. Survey and Planning

Fin. Asstt. Given to

I. SHG

II. Entry Point Activities (No's)

Sub Total :

2. Training

I. SHG (No's)

II. UG (No's)

III. WA's (No's)

IV Others (No's)

Sub Total :

3. Community Organisation

I. Camps (No's)

II. Seminar & Workshop etc.

Sub Total :

4. Work Components

I. Soil & Moist. Cons. Works

a Contour Vegetative Hedgs (Rmt)

b Contour Bunding (Rmt)

c Waste Weirs (No's)

II. Water Harvesting Structure

a Nallah Bandh (CMT)

b Check Dam (CMT)

c Retaining Wall (CMT)

d Anicut (No's)

e Well & Water Tank

f Deepening & Repairing of Ponds (Existing)

(i) Big size (No's)

(ii) Mid size (No's)

(iii) Small size (No's)

q New Ponds (No's)

III. Afforestation Works

a Private Agri, Land (Ha)

b Community Land (Ha)

IV. Pasture Development

a Private Agri, Land (Ha)

b Community Land (Ha)

V. Horticulture Development

a Private Agri, Land (Ha)

b Community Land (Ha)

Sub Total (Ha) :

5. Area Treated

a Private Agri. Land (Ha)

b Community Land (Ha)

c Others (Ha)

Total Area Treated (Ha)

FINANCIAL PROGRESS DURING THE YEAR _____

Name of Scheme : SGSY/Bisalpur Project/TADA/MADA

Name of Zila Parishad _____
(Upto the month _____)

(Rs. in Lacs)

S. No.	Name of Scheme/Year of sanction	Projects alloted by GOI/State Govt.		Amount received since inception upto the month			% of amount received (Col. 7/4)	Expenditure			% of Exp. (Col. 11/4)	Remarks, if any
		Target (No)	Amount (Rs. in lacs)	Govt. of India	State Govt.	Total		Upto last year	During the year	Total (Col.9+10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	SGSY											
2.	Bisalpur project											
3.	NREGP											
4.	TADA											
5.	MADA											
6.	Ohters											
	Total :											

Signature
X.En. (LR (Zila Parishad)

Signature
C.E.O. (Zila Parishad)

Revised MIES Performa for Quarterly monitoring of NWDPRA

Name of the District : **Total Pilot W/S :** **Total Tenth FYP W/S :** **Total NWDPRA W/s :**

Quarter :

(On Quarterly basis)

S. No.	Components / Activities	Unit	For Pilot W/S				For Tenth FYP W/S				Total NWDPRA W/S			
			Physical		Financial		Physical		Financial		Physical		Financial	
			Target 05-06	Ach. Upto Month	Target 05-06	Ach. Upto Month	Target 05-06	Ach. Upto Month	Target 05-06	Ach. Upto Month	Target 05-06	Ach. Upto Month	Target 05-06	Ach. Upto Month
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A.	**Management Component**													
I	**Administration cost**													
	(a) State/District HQ.													
	(b) Watershed Committees													
	- Salary													
	- Other Expenses													
	(c) Project Implimentation Agencies													
	- Salary													
	- Other Expenses													
	Sub Total (1)													
2	**Community Organisation**													
	(a) Entry point Activities of WC													
	(b) Honorarium to village based Com. Organizer													
	(c) Expanses at District headquarter for publicity, support for production of technology input, support for information technology at village level miscellaneous charges etc.													
	(d) corpus for WDF													
	Sub Total (2)													
3	**Training component**													
	(a) State/District level training cost													
	(b) PIA : Training cost at Identified institute													
	Sub Total (3)													
	Total-A, Mgt. Comp. (1+2+3)													
B.	**Development Component**													
1	Natural Resource Management													
	(a) Arable Land													
	- Soil & Moisture conservation activities													
	- Agronomic conservation practices													
	- Others													

	Sub Total (a)	
	(b) Non Arable Land	
	- Run off management structures	
	- Water Harvesting Structures	
	- Dryland Horticulture	
	- Conservation & development of bio-mass	
	- Others	
	Sub Total (b)	
	(c) Drainge Lines	
	- Upper reaches	
	- Middle reaches	
	- Lower reaches	
	Sub Total (c)	
	Sub Total of NRM (a+b+c)	
2	**Farm production system for land owning families**	
	(a) Establishment of nurseries and production of seedlings	
	(b) Testing and demonstration of new technology	
	(c) Diversification of production system	
	(d) Adoption of proven technology such as organic farming, use of bio-fertilizers, integrated Nutrient Management, intergrated pest Management, on farm management, development of micro irrigation system etc.	
	(e) Livestock management	
	(f) Others	
	Sub Total of Form Production System (a+b+c+d+e+f)	
3	**Livelihood support system for land-less families**	
	(a) Household production	
	(b) Bio-mass based rural industry activities	
	(c) Dairy, sericulture, goat breeding, Bee-keeping Murshroom cultivation, commercial poultry etc.	
	(d) Livestock management	
	(e) Others (Specify)	
	Sub Total of Livelihood support system (a+b+c+d+e)	
	Total -B, Dev. Comp. (1+2+3)	
	Grand Total (A+B)	
	Area Treated	

Note : Financial Achievement should be reported as ACTUAL ACHIEVEMENT.

राजस्थान सरकार

बंजड़ भूमि, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग,पंत कृषि भवन, राज., जयपुर

क्रमांक एफ 4(3)2/बंभूजभूसं/एमआईईएस/2006-07/141-215 दिनांक 12.4.2006

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (श्रीगंगानगर जिले के अतिरिक्त)

जिला परिषद, ...

विषयः–जलग्रहण विकास कार्यक्रमों अन्तर्गत विभिन्न योजनान्तर्गत मासिक एवं त्रैमासान्त वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण।

प्रसंग :–निदेशालय का पत्र क्रमांक एफ 4 (10)2/निजभूस/आयो./2003-04/4905-40 दिनांक 10.2.04

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र द्वारा पूर्व में विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही समस्त जलग्रहण विकास योजनाओं के संबंध में मासिक एवं त्रैमासान्त वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण किया गया था। उक्त प्रासंगिक पत्र की निरन्तरता में जलग्रहण विकास कार्यक्रमों अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही समस्त योजनाओं हेतु मासिक एवं त्रैमासान्त अन्तर्गत वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :-

क्र.सं.	त्रैमास	माहवार विवरण	प्रतिशत विभाजन
1	प्रथम	प्रथम माह (अप्रेल)	15%
		द्वितीय माह (मई)	15%
		तृतीय माह (जून)	20%
		त्रैमासान्तर्गत (50%)	त्रैमासान्तक (50%)
2	द्वितीय	प्रथम माह (जुलाई)	7%
		द्वितीय माह (अगस्त)	8%
		तृतीय माह (सितम्बर)	10%
		त्रैमासान्तर्गत (25%)	त्रैमासान्तक (75%)
3	तृतीय	प्रथम माह (अक्टूबर)	5%
		द्वितीय माह (नवम्बर)	5%
		तृतीय माह (दिसम्बर)	5%
		त्रैमासान्तर्गत (15%)	त्रैमासान्तक (90%)
4	चतुर्थ	प्रथम माह (जनवरी)	5%
		द्वितीय माह (फरवरी)	3%
		तृतीय माह (मार्च)	2%
		त्रैमासान्तर्गत (10%)	त्रैमासान्तक (100%)

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी कम्पोनेन्ट में पिछले वर्षों का बैक लोग है तो उक्त बैकलोग की प्राप्ति प्रथम त्रैमासान्त में ही किया जाना सुनिश्चित करें। प्रथम त्रैमास में बैकलोग की प्राप्ति नहीं हो पाए तो द्वितीय त्रैमास में तो आवश्यक रूप से बैकलोग की प्राप्तिसुनिश्चित कर लेवें।

अतः प्रत्येक माह एवं त्रैमासान्त उपरोक्त तालिका में दर्शाये गये मापदण्ड के अनुसार प्रगति/उपलब्धि अर्जित किया जाना सुनिश्चित करें।

ह./-

आयुक्त

क्रमांक एफ 4(3)2/बंभूजभूसं/एमआईईएस/2006-07/141-215 दिनांक 12.4.2006

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. अतिरिक्त निदेशक (प्रथम/द्वितीय), आयुक्तालय, जयपुर।
2. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (भू-संसाधन), आयुक्तालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि लक्ष्यों के निर्धारण में योजनावार कम्पोनेन्टवार पिछले वर्षों का बैकलोग पृथक से दर्शाया जावे।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी, आयुक्तालय, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (एम.ओ.ए.पी.), आयुक्तालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि लक्ष्यों के निर्धारण में योजनावार कम्पोनेन्टवार पिछले वर्षों का बैकलोग पृथक से दर्शाया जावे।
5. संयुक्त निदेशक (प्रशासन/पी.एफ.सी.), आयुक्तालय, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक, बंजड़ भूमि ज.ग्र.वि. एवं भू संरक्षण वृत, जयपुर/अजमेर/भीलवाड़ा/जोधपुर/उदयपुर/कोटा।
7. समस्त अधिशाषी अभियंता (भू-संसाधन) (श्रीगंगानगर जिले के अतिरिक्त), जिला परिषद, ... को प्रेषित कर निर्देशित है कि उपरोक्तानुसार प्रत्येक माह एवं त्रैमासान्त तक प्रगति अर्जित किया जाना सुनिश्चित करावें।

ह./-

आयुक्त

राजस्थान सरकार

बंजड़ भूमि, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग,राज., जयपुर

क्रमांक प 4(9) एम.आई.ई.एस./6-7/684-754 दिनांक 04.5.2006

परिपत्र

विषय : जलग्रहण विकास कार्यक्रमों के प्रभाव/लाभ का आंकलन बाबत्।

विभाग द्वारा जलग्रहण विकास कार्य विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत राज्य में कराये जा रहे हैं। प्रायः यह देखने में आया है कि जलग्रहण कार्य प्रारम्भ कर पूर्ण भी हो जाते हैं, परन्तु इन जलग्रहण क्षेत्रों में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व के 'बेस लाईन डाटा' नहीं लिये जाते हैं, जिससे परियोजना उपरान्त अर्जित प्रभाव/लाभों का आंकलन किया जाना सम्भव नहीं होता है। अतः जलग्रहण क्षेत्रों में जलग्रहण विकास कार्यो के प्रभाव/लाभों का आंकलन करने के लिए निम्न लिखित कार्यवाही तुरन्त प्रभाव से की जावे।

(अ) जलग्रहण क्षेत्र में परियोजना की स्वीकृति के तुरन्त बाद विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने एवं विकास कार्यों के प्रारम्भ करने से पूर्व निम्न प्रकार से बेस लाईन डाटा बाबत् सूचनाऐं एकत्रित की जावे एवं उसका विस्तृत उल्लेख परियोजना प्रतिवेदन में अलग चैप्टर योजना पूर्ण होने पर अपेक्षित प्राप्तियाँ (Expected Outcomes) किया जावे।

1. जलग्रहण क्षेत्र में कार्य शुरू करने से पहले, जितने भी कुएं है, में सम्भवतया माह जून या गर्मी के किसी भी माह में जलस्तर मापा जाकर कुओं के उपर जलस्तर एवं जलस्तर मापने की दिनांक पेन्ट से लिखी जावे। जलग्रहण क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र में कुंओं में यह जलस्तर मापा जाकर रजिस्टर भी संधारित किया जावे।
2. जलग्रहण क्षेत्र में खसरा नम्बरवार, फलों के पेड़, चारे हेतु पेड़ एवं जलाऊ लकड़ी हेतु पेड़ की गणना की जावे।
3. जलग्रहण क्षेत्र में चारागाह एवं बंजर भूमि का क्षेत्रफल एवं उसमें चारे का उत्पादन (क्विण्टल में) बाबत् सूचना।
4. कृत्रिम गर्भाधान प्रक्रिया से बछड़ों की संख्या कृषकवार बाबत् सुचना।
5. जलग्रहण क्षेत्रा में मुख्य-मुख्य फसलों की पैदावार क्विण्टल प्रति हैक्टर बाबत् सूचना।
6. कृषकवार सूची जिन्होंने केचुएं की खाद की तकनीक, उन्नत फसल चक्र एवं उन्नत पैकेज ऑफ प्रेक्टिस अपनाई है, का विवरण।
7. जलग्रहण क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह का विवरण मय उनके सदस्यों की संख्या एवं नाम एवं बैंकों के साथ जुड़ाव का विवरण।

(ब) परियोजना के पूर्ण होने पर एवं एक्जिट प्रोटोकॉल के समय उपरोक्त सूचना पुनः एकत्रित की जाकर जलग्रहण विकास कार्यक्रम के प्रभाव/लाभों का आंकलन निम्न प्रारूप में किया जावे।

क्र.सं.	गतिविधि	परियोजना से पहले	परियोजना के बाद
1.	कुओं के जलस्तर में बढ़ोत्तरी (मीटर में)		
2.	वृक्षों की संख्या-		
	1. फलदार वृक्ष		
क्र.सं.	गतिविधि	परियोजना से पहले	परियोजना के बाद
	2. चारे हेतु वृक्ष		
	3 जलाऊ लकड़ी हेतु वृक्ष		
3.	चारागाह एवं बंजर भूमि से चारे का उत्पादन (क्विं. में)		
4.	कृत्रिम गर्भाधान से बछड़ों की संख्या		
5.	फसल उत्पादन में बढ़ोत्तरी- क्षेत्र की मुख्य फसलें (क्विं. प्रति हैक्टर)		
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
6.	कृषकों की संख्या जिन्होंने		
	1. केचुएं की खाद की तकनीक को अपनाया		
	2. उन्नत फसल को अपनाया		
	3. उन्नत पैकेज ऑफ प्रेक्टिस को अपनय		
7.	स्वयं सहायता समूहों की संखय जिनका बैंको से जुड़ाव हुआ		

प्रत्येक जलग्रहण क्षेत्र में तुरन्त प्रभाव से जलग्रहण विकास कार्यक्रम के प्रभाव/लाभों का आंकलन करने के लिए उपरोक्त दर्शायी 'बेस लाईन डाटा' बाबत् सूचनाऐं एवं परियोजना के पूर्ण हाने पर जलग्रहण विकास से हुये प्रभाव/लाभों की सूचनाएं एकत्रित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

ह./-

प्रमुख शासन सचिव

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

क्रमांक प 4(9) एम.आई.ई.एस./6-7/684-754 दिनांक 04.5.2006

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. अतिरिक्त निदेशक प्रथम/द्वितीय।
2. उप सचिव (भू संसाधन)।
3. संयुक्त निदेशक, जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, भलवाड़ा।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (भू संसाधन) समस्त (गंगानगर को छोड़कर)।
5. परियोजना अधिकारी (भू-संसाधन) समस्त (गंगानगर को छोड़कर)।

ह./-

अतिरिक्त निदेशक-प्रथम